खंड 2
भारतीय समाजः एक आलोचनात्मक बहस-I

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 5 जाति*

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 जाति व्यवस्था की विशेषताएँ

- 5.2.1 समाज का विभाजन
- 5.2.2 अनुक्रम
- 5.2.3 भोजन और सामाजिक संसर्ग पर प्रतिबंध
- 5.2.4 विभिन्न वर्गों के नागरिक और धार्मिक अपात्रता और विशेषाधिकार
- 5.2.5 विवाह पर प्रतिबंध
- 5.2.6 व्यवसाय की अप्रतिबंधित विकल्प का अभाव

5.3 जाति को समझने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण

- 5.3.1 जाति और वर्ग
- 5.3.2 जजमानी प्रणाली

5.4 जाति व्यवस्था के भीतर परिवर्तन और निरंतरता

- 5.4.1 जाति और राजनीति
- 5.4.2 जातिगत भेदभाव को रोकने के उपाय

5.5 सारांश

5.6 संदर्भ

5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप सक्षम होंगे –

- जाति को परिभाषित करने और इसकी विशेषताओं का वर्णन करने में
- जाति की समझ के सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने
- जजमानी प्रणाली और जाति व्यवस्था के साथ इसके संबंध का वर्णन करने
- जाति व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तनों और निरंतरता के तत्वों पर चर्चा करने
- भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अंत में जाति व्यवस्था के प्रभाव की व्याख्या और
- जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए किए गए उपायों पर चर्चा कर सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना

जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रणाली है। यह भारतीय सामाजिक संरचना के मूल में है। इसमें जन्म के अनुसार रैंकिंग शामिल है और एक व्यक्ति के व्यवसाय, विवाह और सामाजिक संबंधों को निर्धारित करता है। मानदंडों, मूल्यों और प्रतिबंधों का एक निर्धारित समूह है जो जाति के भीतर सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है।

*डॉ. शैली भाषांजलि/अनु. डॉ. शास्वत कुमार

समाजशास्त्रियों ने जाति को , वंशानुगत, अंतोगामी समूह के रूप में, जो आमतौर पर स्थानीयकृत है में परिभाषित किया है। जिसका एक पारंपरिक व्यवसाय है और जो जातियों के स्थानीय पदानुक्रम में एक पेशा और एक विशेष स्थान रखता है। जातियों के बीच संबंध अन्य बातों के अलावा, शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा और जाति के भीतर होने वाली सामान्य अधिकतम समानता के आधार पर संचालित होते हैं "(श्रीनिवास 1962)। यह जाति व्यवस्था के आदर्श रूप की परिभाषा है। वास्तव में, हालांकि, जाति व्यवस्था की संरचना और कार्यप्रणाली में भिन्नताएं हैं ।

जाति व्यवस्था के सैद्धांतिक निरूपण और इसकी अस्तित्वगत वास्तविकता के बीच अंतर करना अनिवार्य है। सैद्धांतिक रूप से, भारतीय समाज के जातिगत स्तरीकरण का मूल वर्ण व्यवस्था में है। इस प्रणाली का शाब्दिक अर्थ है रंग जो वैदिक काल के दौरान प्रचलित था। रंग के इस सिद्धांत के अनुसार, हिंदू समाज चार मुख्य वर्णों में विभाजित था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ।

वर्ण की अवधारणा का आम तौर पर ऋग्वेद वेद के पुरुष सूक्त से पता चलता है। इसमें कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति यज्ञ द्वारा आदि जीव या पुरुष से हुई है। यज्ञ के बाद, मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए । इस प्रकार, जिन चार वर्णों का उदय हुआ, उन्हें दैवीय उत्पत्ति माना गया।

5.2 जाति व्यवस्था की विशेषताएँ

प्रसिद्ध समाजशास्त्री घुर्ये (1962), ने जाति व्यवस्था की छह विशेषताओं की पहचान की। ये छह विशेषताएं हैं :

5.2.2 समाज का खंडीय विभाजन

हिंदू समाज विभिन्न जातियों में विभाजित है। जाति की सदस्यता का निर्धारण जन्म से होता है न कि चयन और उपलब्धियों से। इसलिए, जाति की स्थिति को जन्म (जन्म के अनुसार) माना जाता है।

5.2.3 पदानुक्रम

जाति व्यवस्था में सामाजिक प्राथमिकता की एक विशिष्ट योजना है जिसमें उन्हें एक सामाजिक और अनुष्ठान पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उच्च और निम्न, श्रेष्ठता और हीनता की भावना इस उन्नयन या रैंकिंग के साथ जुड़ी हुई है। ब्राह्मणों को पदानुक्रम के शीर्ष पर रखा जाता है और उन्हें अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध या सर्वोच्च माना जाता है। सबसे अशुद्ध माने जाने वाले अछूत, पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर होते हैं। बीच में क्षत्रिय हैं, उसके बाद वैश्य हैं। इस प्रकार, जाति पदानुक्रम के समग्र ढांचे में एक विशिष्ट स्थिति पर कब्जा करती है।

5.2.3 भोजन और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध

ऐसे नियम निर्धारित किए गए हैं जो भोजन के आदान-प्रदान को नियंत्रित करते हैं जिसे विभिन्न जातियों के बीच खान -पान और सामाजिक संपर्क भी कहा जाता है। जातियों के बीच एक तरह के भोजन को एक साथ खाने , प्राप्त या आदान-प्रदान करने पर प्रतिबंध है। एक ब्राह्मण किसी भी समुदाय से 'पक्का' भोजन, जैसे घी ष्में तैयार किया हुआ भोजन स्वीकार करेगा, लेकिन वह अन्य जाति के हाथों पानी में तैयार किए गए भोजन को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रदूषण की अवधारणा सामाजिक संपर्क की सीमा पर गंभीर प्रतिबंध लगाती है।

5.2.4 विभिन्न वर्गों के नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएँ और विशेषाधिकार

प्रत्येक जाति, अनुष्ठान के रूप में अन्य की तुलना में अधिक शुद्ध या अशुद्ध मानी जाती है। शुद्धता और अशुद्धता की विचारधारा विभिन्न जातियों के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करती है। श्रेष्ठ जातियों द्वारा अपनी औपचारिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए कई वर्जनाएँ प्रचलित हैं।

अनुष्ठान को अशुद्ध माना जाने वाली जातियों को कई गुना विकलांग बना दिया गया। उदाहरण के लिए, उन्हें सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक कुओं का उपयोग करने या हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने से मना किया गया था। कुछ जातियों की छाया को प्रदूषणकारी माना जाता था, जैसे कि तमिलनाडु में शार्न्स या ताड़ी निकालने वाली जाति को पहले के समय में ब्राह्मण से अपनी दूरी को 24 कदम तक सीमित करना पड़ता था। प्रत्येक जाति के अपने रीति-रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं और रिवाज हैं। इसके अपने अनौपचारिक नियम, नियम और प्रक्रियाएं हैं।

5.2.5 विवाह पर प्रतिबंध

अंतर्विवाह (एंडोगैमी) या किसी एक जाति या उपजाति के भीतर विवाह जाति व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। आमतौर पर, लोग अपनी जाति या उप-जाति में विवाह करते हैं। हालाँकि, कुछ अपवाद भी थे। भारत के कुछ क्षेत्रों में, उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति की महिलाओं से शादी कर सकते थे। इस तरह के विवाह गठबंधन को बहिर्विवाह (हाइपरगामी) के रूप में जाना जाता है।

5.2.6 व्यवसाय के अप्रतिबंधित पसंद का अभाव

परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी। अनुष्ठान की शुद्धता और उनके संबंधित व्यवसाय की शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर उन्हें उच्च और निम्न स्थान दिया गया था। ऊपर के पद पर काबिज ब्राह्मणों को पवित्र ज्ञान प्राप्त करने और सिखाने का कर्तव्य निर्धारित किया गया था।

उपरोक्त, जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषताओं का विवरण बताता है। हालाँकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी संरचना में जातिगत संरचना के कई रूप हैं। एक क्षेत्रीय वास्तविकता के रूप में, कोई व्यक्ति जाति-रैंकिंग, रीति-रिवाजों और व्यवहारों, विवाह नियमों और जाति प्रभुत्व के विभिन्न पैटर्न देख सकता है।

प्रत्येक जाति की अपनी जाति परिषद या पंचायत होती थी जहाँ उसकी जाति के सदस्यों की शिकायतों को सुना जाता था। जाति पंचायत निर्धारित मानदंडों के अनुसार जाति के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित कर रही थी और सामाजिक व्यवहार को मंजूरी दे रही थी। यदि कोई व्यक्ति जाति प्रतिबंधों का पालन नहीं करता था तो उस जाति के बुजुर्गों के नेतृत्व में, इन परिषदों के पास एक सदस्य को पूर्व-संवाद करने की शक्ति थी। इस प्रकार जाति पंचायतें , ग्राम पंचायतों से अलग रही हैं, यद्यपि अब वैधानिक निकायों के रूप में ग्राम पंचायतें , जाति की परवाह किए बिना सभी ग्रामीणों की सेवा करती हैं, हालांकि वे एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं

बॉक्स 5.1

ड्यूमॉन्ट उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने जाति को राजनीतिक-आर्थिक कारकों के संदर्भ में समझाने की कोशिश की, जहां जाति को वर्चस्व और शोषण की

प्रणाली के रूप में देखा गया था। उदाहरण के लिए, वह एफ.जी. बेली की आलोचना करता है। बेली, जिन्होंने दि कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर '(उड़ीसा में उनके क्षेत्रीय कार्य पर आधारित) में अपनी पुस्तक में तर्क दिया है कि राजनीतिक-आर्थिक रैंक और जातीय संस्कार के श्रेणीक्रम के बीच उच्च स्तर का संयोग था। यह जाति के सामान्य नियम का प्रतिबिंब है कि जो लोग धन और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं, वे श्रेणीक्रम की संस्कार पद्धति में वृद्धि करते हैं। कहने का मतलब यह है कि गाँव के उत्पादक संसाधनों पर अंतर नियंत्रण द्वारा जाति समूहों की रैंकिंग प्रणाली को मान्य किया गया था।

5.3 जाति के ज्ञान के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण

आइए हम विद्वानों द्वारा जाति प्रणाली की समझ के लिए गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण की जांच करें। i) जाति के लिए जिम्मेदार गुणात्मक दृष्टिकोण जाति की विभिन्न अपरिवर्तनीय विशेषताओं के संदर्भ में जाति का विश्लेषण करता है। इस दृष्टिकोण का उपयोग करके जी एस घुर्रे, जे एच हटन जैसे समाजशास्त्री अपनी महत्वपूर्ण विशेषताओं के माध्यम से जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। उपरोक्त खंड में घूरे द्वारा वर्णित जाति प्रणाली की छह विशेषताएं शामिल हैं।

अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया', हटन ने माना कि जाति व्यवस्था की केंद्रीय विशेषता है। इस तथ्य के आसपास विभिन्न प्रतिबंध और वर्जनाएँ निर्मित हैं। विभिन्न जातियों के बीच बातचीत विभिन्न जातियों पर लगाए गए इन प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती है। हटन द्वारा देखी गई जाति व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उनकी अपनी जातियों के अलावा अन्य लोगों से पका हुआ भोजन लेना है। एम एन श्रीनिवास इन विशेषताओं के आधार पर जातियों के बीच उत्पन्न संबंधों की संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं। इस प्रकार, वह जातिगत पहचान के एक गतिशील पहलू का परिचय देता है।

अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया ', हटन ने माना कि अंतर्विवाह (एण्डोगामी) जाति व्यवस्था की केंद्रीय विशेषता है। इस तथ्य के आसपास विभिन्न प्रतिबंध और वर्जनाएँ निर्मित हैं। विभिन्न जातियों के बीच बातचीत विभिन्न जातियों पर लगाए गए इन प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती है। हटन द्वारा देखी गई जाति व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उनकी अपनी जातियों के अलावा अन्य लोगों से पका हुआ भोजन लेना है। एम एन श्रीनिवास इन विशेषताओं के आधार पर जातियों के बीच उत्पन्न संबंधों की संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं। इस प्रकार, वह जातिगत पहचान के एक गतिशील पहलू का परिचय देता है।

ii) अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण इस बात को ध्यान में रखता है कि एक स्थानीय अनुभवजन्य संदर्भ में जातियों को वास्तव में एक दूसरे के संबंध में कैसे श्रेणीगत किया जाता है। बेली के अनुसार जाति की गतिशीलता और पहचान अलगाव और पदानुक्रम के दो सिद्धांतों द्वारा संयुक्त हैं। उसे लगता है कि 'जातियाँ संस्कारों के नियमों में व्यक्त और धर्मनिरपेक्ष पदानुक्रम में खड़ी हैं'। धर्मनिरपेक्ष पदानुक्रम से उनका तात्पर्य था आर्थिक और राजनीतिक पदानुक्रम और संस्कार धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। संस्कारों की प्रणाली राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली को ओवरलैप करती है। इस संदर्भ में बेली (1957) ने उड़ीसा के गाँव बिसिपारा द्वारा अपना दृष्टिकोण समझाया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे बिसिपारा में जाति की स्थिति बदली है और आजादी के बाद और अधिक तरल हो गई है जब क्षत्रियों ने अपनी जमीन खो दी है। इससे उनकी अनुष्ठान रैंकिंग में भी गिरावट आई। इसे दूसरी जातियों से भोजन की स्वीकृति और गैर-स्वीकृति, जैसे कि बातचीत के पैटर्न में स्पष्ट रूप से परिवर्तन किया गया।

अनुष्ठानिक अंतःक्रिया द्वारा मैरिएट ने जाति रैंकिंग की व्यवस्था का अध्ययन किया। उन्होंने पुष्टि की कि अनुष्ठान पदानुक्रम स्वयं आर्थिक और राजनीतिक पदानुक्रम से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर आर्थिक और राजनीतिक श्रेणियों का मेल होता है। यह कहना है कि अनुष्ठान और गैर-अनुष्ठान दोनों पदानुक्रम जाति क्रम में श्रेणियों को प्रभावित करते हैं, हालांकि अनुष्ठान पदानुक्रम एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।

ड्यूमॉन्ट ने जाति के अध्ययन के अंतःक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में एक नया आयाम जोड़ा। उनके अनुसार स्थानीय संदर्भ का जाति श्रेणी और पहचान में एक भूमिका है, लेकिन यह पदानुक्रम की विचारधारा की प्रतिक्रिया है जो संपूर्ण जाति व्यवस्था पर फैली हुई है। ड्यूमॉन्ट के अनुसार जाति एक विशेष प्रकार की असमानता है और पदानुक्रम जाति व्यवस्था के आधार पर आवश्यक मूल्य है। यह वह मूल्य है जो हिंदू समाज को एकीकृत करता है। जाति के विभिन्न पहलुओं का कहना है कि ड्यूमॉन्ट का सिद्धांत शुद्ध और अशुद्ध के बीच विरोध के सिद्धांत पर आधारित हैं। ''शुद्ध'' ''अशुद्ध'' से बेहतर है और उसे अलग रखा जाता है।

बॉक्स 5.2

एक अनुकूल संस्था के रूप में जाति पर इस भागीदारी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दो गुना हैः जाति के आंतरिक सामाजिक संगठन पर एक रूढ़िवादी के रूप में जो अपनी अखंडता को अधिक प्रभावी ढंग से जुटाने के लिए संरक्षित करेगा, और अन्य जातियों के लिए अपने बाहरी संबंधों में एक अधिक रचनात्मक रूप में वे शक्ति, प्रतिष्ठा और धन के लिए दुर्लभ संसाधनों के अपने हिस्से को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, और 'मूल समझौते की नागरिक राजनीतिश को विकसित करते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में बहुत अधिक निर्भरता लाने के लिए जाति समूहों को दूसरों के उद्देश्यों के विपरीत शक्ति प्रदान करती है। जिसका पहला प्रभाव जाति की निष्ठाओं का संरक्षण करना और दूसरा व्यापक लोगों का निर्माण करना होता है। इस प्रकार लिंच का निष्कर्ष है : 'आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ही इस प्रक्रिया में खुद को आगे लाती है और एक नए राज्य के संघर्ष में नागरिकता और जातिगत प्रस्थितियों के प्रति निष्ठावान राष्ट्र बनने के लिए संघर्ष करती है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण में जाति की सैद्धांतिक स्थिति अत्यधिक जटिल है। यह सामाजिक स्तरीकरण की एक संरचनात्मक इकाई के साथ-साथ एक प्रणाली दोनों का गठन करता है। दोनों के बीच निहित अंतर विश्लेषण के स्तर पर निर्भर करता है । समाजशास्त्री जो जाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को देखते हैं, शुरू से ही, इसे स्तरीकरण के एक स्वायत्त सिद्धांत से जोड़ते हैं, जिसके आधार हैं, संस्थागत असमानता, सामाजिक गतिशीलता के संबंध में बंद सामाजिक प्रणाली, श्रम के विभाजन का एक प्राथमिक स्तर पारस्परिकता के अनुष्ठान आधारों पर वैधता, और प्रदर्शन के बजाय गुणवत्ता (अनुष्ठान शुद्धता या नस्लीय शुद्धता) पर जोर देता है।

दूसरे शब्दों में, जाति सांस्कृतिक प्रणाली या विश्व-दृष्टिकोण के एक स्वायत्त रूप से जुड़ी हुई है। जाति के इस दृष्टिकोण का इतिहास समाजशास्त्रीय साहित्य में बहुत पहले से ही पाया जाता है (देखें डुबॉइस 1906, नेसफील्ड 1885: ओ मल्ले 1932, वेबर 1952, क्रोबेबर 1930 आदि) और यह प्रवृत्ति अभी भी जारी है (बर्कमैन 1967 देखेंय बर्थ 1960य डेविस 1951) डलतकंस 1968, आदि)। इस सम्बन्ध में जाति की महत्वपूर्ण धारणा केवल स्तरीकरण के सिद्धांत का एक प्रकार है जो न केवल भारत में, बल्कि अन्य समाजों में भी कार्यरूप में पाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ है , जैसा कि हम डेविस के लेखन में पाते हैं, ए.आर. देसाई (1966) और बोस (1968 अन्य) और अन्य यह समझते

हैं कि एक संरचनात्मक वास्तविकता होने के नाते यानी सामाजिक संरचना जाति का हिस्सा होने के बाद भारत में समाज उच्च स्तर (औद्योगिकीकरण के बाद सिंह 1968) में विकसित होता है। जाति के संरचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में एक सरल समझ यह है कि यह एक आदर्श प्रकार की स्तरीकरण प्रणाली बनाता है और जोकि हमेशा के लिए अस्तित्व में हो सकता है, या समाजों में स्तरीकरण के अन्य रूपों के साथ सह-अस्तित्व में है। यह दृष्टिकोण समाजशास्त्रियों द्वारा आयोजित किया जाता है जो सामाजिक स्तरीकरण के विकासवादी-ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बजाय एक संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। (सिंह, योगेंद्र 1997. पृष्ठ .32)

इस प्रकार जाति को एक सांस्कृतिक घटना के रूप में मानने वाले समाजशास्त्रियों और एक संरचनात्मक घटना के रूप में परिभाषित करने वालों के बीच अंतर किया जा सकता है। इन पदों में से प्रत्येक में जाति के दृष्टिकोण के आधार पर एक और उपविभाजन होता हैः चाहे वह एक विशेष घटना हो, इस मूल रूप से भारतीय हो , या उसके सार्वभौमिक गुण हों। जब हम सैद्धांतिक निर्माण के दो स्तरों के बीच अंतर करते हैं, अर्थात, सांस्कृतिक और संरचनात्मक और सार्वभौमिक और विशिष्ट तब इस प्रकार चार दृष्टिकोण तार्किक वर्गों के रूप में यह उभरते हैं।

5.3.1 जाति और वर्ग

भारतीय समाज में, जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के दो विभिन्न रूपों में अक्सर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते पाए गए हैं। योगेंद्र सिंह (1997) ने उल्लेख किया है कि भारत में अक्सर वर्ग जाति द्वारा परस्पर-व्याप्त होता है। जबकि जाति को एक वंशानुगत समूह के रूप में माना जाता है, एक सामाजिक वर्ग उन लोगों की श्रेणी है जो अपने समुदाय या समाज के अन्य वर्गों के संबंध में समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति साझा करते हैं। आंद्रे बेत्तेई (1965) ने दक्षिण भारत के श्रीपुरम में जाति और वर्ग के अपने अध्ययन के आधार पर पाया कि जाति और वर्ग के बीच एक गतिशील संबंध रहा है। पारंपरिक प्रणाली में, जाति और वर्ग के बीच अधिक से अधिक समानता थी। लेकिन वर्ग व्यवस्था धीरे-धीरे जातिगत संरचना से अलग हो रही है । जाति की संरचना में किसी की भी स्थिति अलग-अलग हो सकती है। हालांकि, जाति, वर्ग भी शक्ति संरचना के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं जो संपत्ति के जहाज में स्वामित्व के संदर्भ में परिलक्षित होता है, जैसे कि, भूमि और राजनीतिक और समाज में आर्थिक स्थिति ।

गतिविधि 1

अपने परिवार और दोस्तों के साथ चर्चा से उन विशेषताओं की एक सूची बनाइये जिन्हें आप जाति से संबंधित मानते हैं। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ चर्चा करें।

5.3.2 जजमानी प्रणाली

जजमानी प्रणाली को भारतीय सामाजिक मानव-शास्त्र में विलियम विजर (1937) द्वारा उनके अग्रणी कार्य, ''द हिंदू जजमनी सिस्टम'' के माध्यम से पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश के एक गांव के अपने अध्ययन में, उन्होंने पता लगाया कि विभिन्न जातियों ने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विनिमय में एक दूसरे के साथ कैसे अंतः क्रिया करती हैं । उन्होंने यह पाया गया कि, कुछ भिन्नताओं के साथ, यह प्रणाली पूरे भारत में मौजूद थी।

वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण की कृषि प्रणाली पर आधारित , जजमानी प्रणाली जमींदार उच्च जाति समूहों और व्यावसायिक जातियों के बीच की कड़ी है। यह

कहा जा सकता है कि जजमानी प्रणाली वितरण की एक प्रणाली है जिसके तहत उच्च जाति की भूमि के मालिक परिवारों को विभिन्न निम्न जातियों जैसे कि बढ़ई, नाई, स्वीपर, आदि द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

यह गांव में विभिन्न जाति समूहों के बीच आर्थिक, सामाजिक और अनुष्ठान संबंधों की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत संरक्षक और सेवा जातियां हैं। चूँकि जाति का पेशा से पारंपरिक संबंध है, इसलिए कई सेवाएँ हासिल करने के लिए जातियाँ एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

सेवा करने वाली जातियों को कमीन कहा जाता है जबकि सेवा की जातियों को जजमान कहा जाता है। प्रदान की गई सेवाओं के लिए, सेवक जातियों का भुगतान नकद या प्रकार (अनाज, चारा, कपड़े, दूध, मक्खन, आदि जैसे पशु उत्पादों) में किया जाता है। राजपूत, भूमिहार और जाट उत्तर में संरक्षक जातियां और दक्षिण में काममा, रेड्डी और लिंगायत हैं। सेवा जातियों में नाई, बढ़ई, लोहार, धोबी आदमी, चमड़ा-मजदूर आदि शामिल हैं, जजमानी के अधीन संबंध स्थायी और वंशानुगत था। ऑस्कर लेविस का उल्लेख है कि एक गांव के भीतर प्रत्येक जाति समूह पारंपरिक रूप से अन्य जातियों के परिवारों को कुछ मानकीकृत सेवाएं देने के लिए बाध्य है। जबकि उच्च जाति के परिवारों को निम्न जातियों से सेवाएँ प्राप्त होती हैं और बदले में निम्न जातियों के सदस्यों को अनाज प्राप्त होता है।

पिछले दशकों में जजमानी प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। गाँव में, हर जाति इस प्रणाली में भाग नहीं लेती है। जजमानी संबंध के अलावा, माल और सेवाओं के प्रदाताओं और उनके खरीदारों के बीच हमेशा संविदात्मक, मजदूरी श्रम प्रकार का संबंध रहा है। नकदी अर्थव्यवस्था का परिचय परिवर्तन भी लाया है, क्योंकि जजमानी प्रणाली में भुगतान नकदी के बजाय कृपा पर आधरित थे। कस्बों और शहरों में नए अवसर आए हैं, और कई व्यावसायिक जातियां इन अवसरों में भाग लेने के लिए शहरों में चली गई हैं। जीवन शैली, आधुनिक शिक्षा, बेहतर परिवहन और संचार के प्रभाव के कारण जजमानी प्रणाली में गिरावट आई है। विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। अब भुगतान नकद के रूप में किया जाता है। जाति व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन भी जजमानी प्रणाली के पारंपरिक संस्थान के कामकाज के रास्ते में बाधा उत्पन्न किया है।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) जाति को परिभाषित करें और भारत में जाति व्यवस्था की कम से कम तीन विशेषताओं का उल्लेख करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) जाति की समझ के प्रति गुणात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? जवाब देने के लिए पांच लाइनों का उपयोग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

5.4 जाति व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन एवं निरंतरता

परिभाषा के अनुसार, जाति व्यवस्था को स्तरीकरण की कठोर और बंद प्रणाली के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक जाति की प्रस्थिति से दूसरी जाति की ओर में कोई आंदोलन या गतिशीलता नहीं है। सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह आगे या नीचे की ओर बढ़ते हैं अथवा एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक पदानुक्रम में परिवर्तित होते हैं । वास्तव में, सामाजिक गतिशीलता जाति व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जाति व्यवस्था एक गतिशील वास्तविकता है, जिसमें इसकी संरचना और कार्य के संदर्भ में लचीलापन है।

संस्कृतिकरण की अवधारणा जो मूल रूप से सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है, जिसे एम एन श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था की गतिशील प्रकृति का वर्णन करने के लिए विकसित किया था। अपने पथप्रवर्तक अध्ययन , कूर्ग (1952) के बीच धर्म और समाज,में एम एन श्रीनिवास ने स्थानीय निचली जातियों द्वारा ब्राह्मणों के सांस्कृतिक अनुकरण के संदर्भ में जातिगत गतिशीलता को समझाया। उन्होंने संस्कृतिकरण को 'एक ऐसी प्रक्रिया' के रूप में परिभाषित किया, जिसके द्वारा 'निम्न' हिंदू जाति, या आदिवासी या अन्य समूह अपने रीति-रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन के तरीके को उच्च, अक्सर 'द्विज' जाति के रूप में बदलते हैं। आम तौर पर इस तरह के बदलावों को जाति पदानुक्रम में एक उच्च पद के लिए एक दावे के बाद किया जाता है, जो परंपरागत रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा दावेदार जाति को स्वीकार किया जाता है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के सेनापुर गाँव में नोनिया के विलियम रोव्स के अध्ययन से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के बाद संस्कृतिकरण के माध्यम से ऊर्ध्वगामी गतिशीलता प्राप्त करने में एक मध्यम स्तर की जाति की सफलता का पता चलता है। संस्कृतिकरण का एक स्पष्ट उदाहरण 'द्विज' जाति का अनुकरण है, जैसे कि, तथाकथित 'निचली जातियों' द्वारा शाकाहार का प्रयोग । जाति व्यवस्था के भीतर गतिशीलता के लिए यह प्रशस्त तरीका है। हालांकि, जातिगत पदानुक्रम में ऊपर की ओर चढ़ने के इच्छुक निचली जातियों को उच्च जातियों से विरोध का सामना करना पड़ता है।

संस्कृतिकरण के साथ-साथ पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भी सामाजिक गतिशीलता को संभव बनाया है। पश्चिमीकरण भारत में सभी सांस्कृतिक परिवर्तनों और संस्थागत नवाचारों को संदर्भित करता है क्योंकि यह पश्चिमी देशों विशेषकर ब्रिटिश के साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक अनुबंध में आया था। इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, राष्ट्रवाद का उदय, देश में नई राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व शामिल हैं। इस प्रक्रिया में कई उच्च जातियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों को छोड़ दिया और पश्चिमी लोगों की जीवन शैली को अपनाया।

औद्योगीकरण और नगरीकरण या शहरीकरण की प्रक्रिया (गाँवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन) ने जाति संरचना को काफी हद तक प्रभावित किया। औद्योगिक विकास ने लोगों को आजीविका के नए स्रोत प्रदान किए और व्यावसायिक गतिशीलता को संभव बनाया। साथ ही नई परिवहन सुविधाओं के साथ, लगातार संचार का प्रयोग भी बढ़ा। इस कारण सभी जातियों के लोगों ने एक साथ यात्रा की और जातियों के बीच अनुष्ठान शुद्धता और प्रदूषण की प्रचलित विचारधारा का पालन करने का कोई तरीका नहीं बचा । भोजन के बंटवारे के खिलाफ वर्जनाएं कमजोर पड़ने लगीं जब विभिन्न जातियों के औद्योगिक कार्यकर्ता एक साथ रहने लगे और एक साथ काम करने लगे ।

शहरों के शहरीकरण और विकास ने भी जाति व्यवस्था के कामकाज को बदल दिया। इस सन्दर्भ में किंग्सले डेविस (1951) ने माना कि शहर की गुमनामी, भीड़, गतिशीलता, धर्मनिरपेक्षता और परिवर्तनशीलता जाति के संचालन को लगभग असंभव बना देती है। घुर्ये (1961) का मानना है कि जाति व्यवस्था की कठोरता में परिवर्तन शहर के जीवन के विकास के कारण थे। एम एन श्रीनिवास (1962) का मानना है कि कस्बों में ब्राह्मणों के प्रवास के कारण गैर-ब्राह्मणों ने उनके प्रति वही सम्मान दिखाने से इनकार कर दिया, जो वे पहले दिखाते थे, और इसने ही अंतरजातीय खाने और पीने की वर्जनाओं को भी कमजोर किया।, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी गई है, जिसे कभी धार्मिक हठधर्मिता माना जाता था जो अतीत में और जन्म पर आधारित था लेकिन अब ऐसा नहीं है।

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के अलावा, देश में स्वतंत्रता के बाद उभरे अन्य कारकों ने जाति व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। देश में स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक नीतियों और सुधारों की शुरुआत की गई, जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद कई बदलाव हुए। सामाजिक-धार्मिक सुधार और आंदोलनों, कुछ राज्यों के विलय से आधुनिक शिक्षा का प्रसार, आधुनिक पेशे का विकास, स्थानिक गतिशीलता और बाजार अर्थव्यवस्था आदि के प्रसार ने आधुनिकीकरण और विकास की प्रक्रिया को तेज किया। नतीजतन, परिवर्तन और जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया ने गति प्राप्त की है।

औद्योगिकरण के विकास से नए व्यावसायिक अवसर उभरे जो अनुष्ठानिक रूप से तटस्थ थे। इन नए व्यवसायों में प्रवेश आधुनिक शिक्षा के माध्यम से प्रदान किए गए तकनीकी कौशल पर आधारित थे। जब अलग-अलग जातियों के लोग आधुनिक व्यावसायिक समायोजन में एक साथ निकट संपर्क में आए , तो इसने जाति के अनुष्ठान, आनुवंशिकता और पदानुक्रमित संरचना और पहलुओं को एक गंभीर झटका दिया।

जाति व्यवस्था के तहत, अंतर्विवाह (एंडोगैमी) जीवन - साथी के चयन का आधार था। समूह के बाहर शादी करने के लिए गैर-बदलते सामाजिक कानूनों द्वारा एक जाति या उप-जाति के सदस्यों को मना किया जाता है। लेकिन वर्तमान में स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 ने एंडोगैमी के प्रतिबंधों को हटा दिया है और अंतर-जातीय विवाह को कानूनी रूप से वैध घोषित कर दिया है। बाद में, पश्चिमी दर्शन के प्रभाव, सह-शिक्षा, एक ही कारखाने या कार्यालय में विभिन्न जातियों के पुरुषों और महिलाओं के एक साथ काम करने के कई कारकों ने अंतर-जातीय विवाह और प्रेम-विवाह, देर से विवाह और लिव-इन-रिलेशनशिप के मामलों में वृद्धि में योगदान दिया है।

राम कृष्ण मुखर्जी (1958) ने कहा कि आर्थिक पहलू (व्यावसायिक विशेषज्ञता में बदलाव) और सामाजिक पहलू (उच्च जाति के रीति-रिवाजों को अपनाना, प्रदूषण फैलाने वाले व्यवसायों को छोड़ना आदि) दोनों ने जाति व्यवस्था को बहुत हद तक बदल दिया है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन अधिक विशिष्ट है जहां सामाजिक संपर्क पर नियम हैं, और जातियों के साथ सहभोजन बढावा दिया है और निचली जातियों के नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएँ को हटा दिया गया है। बहुत से विद्वानों का दृष्टिकोण के है कि जाति व्यवस्था के भीतर धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन वे समग्र रूप से व्यवस्था के लिए विघटनकारी नहीं हैं। इस सन्दर्भ में घुर्ये (1961) का मत था कि जाति ने अपनी कुछ विशेषताओं को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि, 'जाति अब किसी व्यक्ति के व्यवसाय का कठोरता से निर्धारण नहीं करती है लेकिन जाति के भीतर विवाह के बारे में अपने मानदंडों को निर्धारित करना जारी रखती है।' शादी, जन्म और मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण समय पर मदद के लिए किसी एक जाति पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। "उनका मानना था कि सामाजिक जीवन में जाति व्यवस्था की ताकत आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। हालांकि आंद्रे बेतेइ ने जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में जातियों, जीवन शैली, समानता और सहभोजन के बीच अपनी संरचनात्मक दूरी के संदर्भ में बताया है। विद्वानों ने यह भी कहा है कि जाति ने शुद्धता और प्रदूषण के अपने पारंपरिक तत्वों को खो दिया है और वह एक पहचान समूह के रूप में विकसित हुई है। (शर्मा, के)

5.4.1 जाति और राजनीति

एक जाति के दूसरे पर प्रभुत्व की घटना जाति व्यवस्था के बने रहने का एक महत्वपूर्ण कारक थी। परंपरागत रूप से, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व संस्कार के प्रभुत्व के साथ मेल खाता था। श्रीनिवास (1966) के अनुसार किसी जाति को तब प्रमुख कहा जाता है जब वह गाँव या स्थानीय क्षेत्र में संख्यात्मक रूप से सबसे मजबूत होती है और यह आर्थिक और राजनीतिक रूप से बड़ा प्रभाव डालती है। इस तरह के कारक एक विशेष जाति समूह को राजनीतिक प्रभुत्व की स्थिति में रखने के लिए गठबंधन करते हैं।

समाजशास्त्रियों ने जाति के संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषण किया है और समय के साथ से जाति के राजनीतिक विकास का पता लगाया है। उन्होंने राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए जाति की भूमिका और राजनीति से इसके जुड़ाव का विश्लेषण किया है। संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली, वयस्क मताधिकार, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की प्रणाली ने राजनीति को जमीनी स्तर पर ले जाता है जहां जाति चुनावी राजनीति में एक प्रमुख चर बन जाती है। राजनीति में संगठित पार्टी प्रणाली की माँगों ने जातियों के गठजोड़ को जन्म दिया है और जाति आधारित राजनीति ने जाति के महत्व को बढ़ावा दिया है । यह जाति लामबंदी और साथ ही राजनीतिक लाभ, भौतिक कल्याण, सामाजिक स्थिति और जातिगत गठजोड़ के लिए एकीकरण का कारक रही है। (देखें कोठारी, आर. (सं.) 1970ः भारतीय राजनीति में जाति, ओरिएंट लैंगमैन, नई दिल्ली)

आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था संविधान द्वारा सार्वभौमिक है और यह जाति के कारक को विशेषाधिकार में नहीं लेती है लेकिन व्यवहार में, जमीनी स्तर पर, जातिगत विचार लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में एक प्रमुख स्थान पर काबिज हो गए हैं। उनकी भूमिका के संदर्भ में जाति आधारित राजनीतिक चेतना, जाति सभा या जाति संघों और भारतीय राजनीति और राजनीतिक गोलबंदी में स्पष्ट है। रजनी कोठारी ने जाति और राजनीति के बीच संबंधों की जांच की है। उन्होंने पाया कि उन्होंने शिक्षा के कारकों, सरकारी संरक्षण और मताधिकार का विस्तार करने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया, जिससे देश में लोकतांत्रिक राजनीति प्रभावित हुई। आर्थिक अवसर, प्रशासनिक संरक्षण बढ़ती चेतना, सामाजिक दृष्टिकोण बदल रहा है। नए अवसरों की मान्यता और बढ़ती चेतना और आकांक्षाओं ने जाति को राजनीति और राजनीतिक गोलबंदी में खींच लिया है।

विभिन्न दलों और आंदोलनों ने जाति आधारित स्थिति समूहों को अपने राजनीतिक हित के लिए संसाधनों के रूप में जुटाया। बहुत बार उम्मीदवारों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा मैदान में उतारा जाता है। जाति संगठित पार्टी की राजनीति के लिए जुटाव और समर्थन की एक पहले से तैयार प्रणाली प्रदान करती है। विभिन्न जाति महासंघ हैं जो अपने सामान्य पाठ्यक्रम के लिए लड़ने के लिए एक संगठित राजनीतिक मंच प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात की क्षत्रिय सभा एक सक्रिय जाति महासंघ का चित्रण है। इसमें जाति या जाति के समूह शामिल हैं, जो जाति आधारित राजनीतिक समुदाय की तरह काम करते हैं। इस प्रकार, जाति राजनीतिक महत्व का एक कारक है और यह राजनीति के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

5.4.2 जातिगत भेदभाव को रोकने के उपाय

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों और वर्गों की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के प्रभाव के कारण विभिन्न अन्य कानूनी संवैधानिक उपायों में जाति और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। हमारा संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यह किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए, संसद में कई अधिनियमों को पारित किया गया है ताकि अंतिम अपराधियों के खिलाफ शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जा सके। भारत सरकार ने अस्पृष्यता को दूर करने के लिए कानून बनाए हैं। इसने समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सुधार भी किए हैं। उनमें से कुछ हैं:

i) मौलिक मानवाधिकारों की संवैधानिक रूप से गारंटी

ii) 1950 में अस्पृश्यता का उन्मूलनष्य

iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और

iv) शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार और अन्य अवसरों में आरक्षण का प्रावधान,

v) 1976 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए समाज कल्याण और राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना और अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम का नाम दिया गया।

एससी और एसटी अधिनियम, 1989 उनके खिलाफ गतिविधियों की जाँच, बचाव और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास के रूप में रोजगार के निशेध के लिए एक अधिनियम, 2013 भी है। इस अधिनियम का उद्देश्य मैला ढोने के रोजगार को रोकना, बिना सुरक्षात्मक उपकरणों के सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मनुष्यों द्वारा सफाई, और अस्वास्थ्यकारी शौचालयों के निर्माण पर रोक लगाना है। अधिनियम मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना चाहता है और उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करना चाहता है।

गतिविधि 2

अपने दोस्तों के साथ कानूनी उपायों और विभिन्न कदमों के बारे में चर्चा करें, जो हमारे संविधान भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए प्रदान करते हैं। इस चर्चा पर एक पृष्ठ की एक रिपोर्ट लिखें और अपने अध्ययन केंद्र में अपने सहकर्मी समूह के साथ इस पर चर्चा करें।

भारत का संविधान एक समानतावादी समाज बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों के तहत सुरक्षात्मक भेदभाव के लिए उपाय प्रदान करता है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिमान्य उपचार देता है। इस प्रकार आरक्षण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान करने के लिए सत्ता, राजनीति, सेवाओं, रोजगार में हिस्सेदारी देने की रणनीति रही है। 1950 में, संविधान ने अनुसूचित जातियों के लिए 12.5% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% आरक्षण दिया, लेकिन बाद में 1970 में, इसे SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% कर दिया गया। आरक्षण नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में प्रदान किया गया था। तदनुसार, सभी राज्य सरकारों ने राज्य में एससी और एसटी को सेवाओं और अन्य क्षेत्रों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाए। भारत के संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें उनके लिए ओबीसी शब्द का उपयोग किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 15 (4) उन्हें, नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों 'के रूप में संदर्भित करता है। अनुच्छेद 340, उन्हें 'सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों' के रूप में संदर्भित करता है। अनुच्छेद 16 (4) उन्हें केवल पिछड़े वर्ग के नागरिकों 'के रूप में संदर्भित करता है। अनुच्छेद 46 उन्हें शैक्षिक और लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रूप में संदर्भित करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की उन्नति के लिए हमारे संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में कई प्रावधान हैं।

हालाँकि, आरक्षण का मुद्दा अधिक जटिल है, विशेष रूप से अखिल भारतीय स्तर पर। जमीनी हकीकत ने दिखा दिया है कि गरीबों और वंचितों की हालत सुधारने के लिए कई उपाय कारगर नहीं हैं। इसलिए, आरक्षण के मानदंडों के मुद्दे को बार -बार से उठाया गया है। समय-समय पर इसके मूल्यांकन और नीति निर्माण की आवश्यकता है।

अंतिम विश्लेषण में हम मानते हैं कि समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण जाति पारंपरिक कार्यों, मानदंडों और संरचना को खो रही है लेकिन जाति अभी भी मौजूद है। यह बदले हुए वातावरण, स्थिति और मानसिकता के अनुरूप नया 'अवतार प्राप्त कर रहा है।

जाति खुद को संशोधित कर रही है लेकिन अभी भी कायम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। शहरी क्षेत्रों में, जाति हित और वर्ग समूहों के जटिल नेटवर्क के रूप में बनी हुई है। हालाँकि भारतीय समाज की एक गतिशील वास्तविकता के रूप में जाति में कई परिवर्तन हुए हैं और अभी भी निरंतरता के तत्व मौजूद हैं। एक पहचान समूह के रूप में जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनूठी सामाजिक संस्था के रूप में मौजूद है।

बोध प्रश्न 2

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) समकालीन भारत में जाति व्यवस्था कैसे बदल गई है, इस पर संक्षिप्त चर्चा करें। प्रश्न का उत्तर देने के लिए लगभग 10 पंक्तियों का उपयोग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारतीय संविधान निम्न जातियों को भेदभाव से बचाने में कैसे मदद करता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लगभग 10 पंक्तियों का उपयोग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

5.5 सारांश

हमने जाति और उसके इतिहास की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताया है। यह पदानुक्रम के साथ जुड़ा हुआ है और जजमानी प्रणाली के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है। पदानुक्रम के अलावा, जाति प्रणाली को श्रम के व्यवसाय वाले विभाजन की विशेषता है, जो कि एक साथ 'कच्चे' या 'पक्के' खाने और सामाजिक संपर्क, नागरिक और धार्मिक विकलांग, विभिन्न वर्गों के विशेषाधिकार, विवाह और प्रतिबंधों द्वारा प्रतिबंधित है। इस सन्दर्भ में व्यवसायों की पसंद, जाति व्यवस्था के भीतर परिवर्तन और निरंतरता को समझाया गया है। जाति और राजनीति के संबंध को पंचायती राज की संस्था में जाति की भूमिका के विशेष संदर्भ के साथ भी समझाया गया है। पिछले भाग में, हमारे संविधान के निर्माण के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए जातिगत भेदभाव को रोकने के उपायों के बारे में बताया गया है। निष्कर्ष रूप में, व्यवस्था के भीतर जाति की व्यवस्था, परिवर्तन और निरंतरता की वर्तमान स्थिति को समझाया गया है।

5.6 संदर्भ

श्रीनिवास एम.एन.1962, आधुनिक भारत में जाति और अन्य निबंध, मीडिया प्रकाशक, बॉम्बे।

श्रीनिवास, एम.एन. 1952. दक्षिण भारत के कूर्गों के बीच धर्म और समाज, मीडिया प्रचारक और प्रकाशक प्रा. लि., बंबई।

घुर्ये, जी.एस. जाति, वर्ग और व्यवसाय - लोकप्रिय प्रकाशन, 1961 बॉम्बे।

राम आहूजा, इंडियन सोशल सिस्टम, रावत पब्लिकेशन, 1966 नई दिल्ली। (प्रामाणिक स्रोत नहीं)

इग्नू बीडीपी सामग्री पर (2017 (पुनर्मुद्रण) ईएसओ-12, ब्लॉक 5 जाति और वर्ग और समाज और स्तरीकरणय भारतीय समाज ईएसओ-14 में ब्लॉक 5 स्पष्टीकरण जाति।

5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) जाति, वर्ण (या रंग) के अखिल भारतीय दर्शन के भीतर, जाति और उपजाति के अपने क्षेत्रीय जाति पदानुक्रम के आधार पर हिंदू समाज को अलग-अलग खंडों में विभाजित करती है। यह पदानुक्रम जन्म आधारित है यानी किसी को उस वर्ण या जाति में और यह अनुष्ठान शुद्धता और प्रदूषण पर आधारित है।

2) जाति व्यवस्था को समझने के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण जाति की समझ पर आधारित है जो विभिन्न विशेषताओं की दृष्टि से हैय जैसे पदानुक्रम, शुद्धता और प्रदूषण व्यवसाय, आदि। इस दृष्टिकोण का उपयोग जी.एस घुर्ये, जैसे समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया है

बोध प्रश्न 2

1. जाति व्यवस्था को वर्ग के विपरीत स्तरीकरण की एक बंद प्रणाली माना जाता है। हालांकि, समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में पाया है कि निचले समूहों से लेकर उच्च स्तर तक के जाति समूहों के आंदोलन के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता हमेशा से थी। परंतु, स्वतंत्रता के बाद, हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र की एक सार्वभौमिक राजनीतिक प्रणाली द्वारा लाए गए परिवर्तनों के साथ-साथ संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने समाज में तेजी से बदलाव लाने में मदद की। इसके कारण जाति व्यवस्था में बदलाव आया लेकिन अभी तक कुछ कठोर तत्वों, जैसे, पहचान और राजनीति से इसके जुड़ाव अभी भी भारत में समाज को आकार दे रहे हैं।

2) भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लाने के अपने जनादेश के माध्यम से अपने नागरिकों को कुछ संवैधानिक उपायों जैसेः

   i) अस्पृशयता का उन्मूलन

   ii) मौलिक मानवाधिकारों की संवैधानिक रूप से गारंटी।

   iii) एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भविष्य कहे जाने वाले भेदभाव के उपायों के रूप में और सामाजिक न्याय और समाज में समानता लाने के लिएय और इसी तरह अन्य उपाय।

इकाई 6 जनजाति*

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 जनजाति को समझना

6.2.1 भारत में जनजातियों के विशिष्ट लक्षण

6.3 मध्य भारत में आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ

6.3.1 आजीविका तक पहुँच से संबंधित मुद्दे

6.3.2 कृषि नीतियां, भूमि कानून और आदिवासियों के बीच भूमि निसंबंध

6.4 जनजातियाँ और वन

6.4.1 भूमि और आजीविका का नुकसान

6.4.1.1 स्वतंत्रापूर्व के भारत में भूमि और आजीविका का नुकसान

6.4.1.2 स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में भूमि और आजीविका का नुकसान

6.4.2 विनियम और प्रतिरोध

6.4.3 भूमि के मुद्दे पर नए तरह का संघर्ष

6.4.4 जनजातीय 'अशांति'

6.5 सारांश

6.6 संदर्भ

6.7 बोध प्रश्नो के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित करने में सक्षम होंगे :

- भारत में जनजातियों की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करना;
- आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर चर्चा;
- आदिवासियों के बीच कृषि नीतियों, भूमि कानूनों और भूमि अलगाव की व्याख्या करना;
- विनियम और प्रतिरोध पर चर्चा; और
- भूमि के मुद्दे पर नए तरह के संघर्ष का वर्णन करना।

6.1 प्रस्तावना

'जाति' पर पिछली इकाई में आपने 'जाति' के बारे में सीखा जो कि भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यहाँ इस इकाई 3 "जनजाति" में, हमने विशेष रूप से ट्राइब्स या भारत में "जनजाति" का वर्णन किया है।

भारत में जनजातियों का अध्ययन और लेखन कई विद्वानों द्वारा किया गया है। इस इकाई में हम भारत में जनजातीय समुदायों से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्हें अधिकतर सामाजिक जीवन की मुख्यधारा से बाहर रखा गया है और वे आजीविका के अपने

* डॉ. टी. गांगमी,दि.वि./अनु. शास्वत कुमार

मूल स्रोतों से वंचित हैं। वे अक्सर अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं से पृथक कर दिए जाते हैं। वे अपनी गरिमा और निर्भरता की हानि का अनुभव करते हैं। सरकार की नीतियों का जनजातीय समाजों पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप इन नीतियों के लिए जनजातीय प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग हैं। नीति-निर्माताओं के बीच आदिवासी उत्थान की बड़ी चिंता है।

6.2 जनजाति को समझना

लैटिन शब्द 'ट्राइब्स' से व्युत्पन्न, जनजाति शब्द का अर्थ है एक निवास स्थान। यह एक समुदाय बनाने वाले व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है जो एक पूर्वज के वंश होने का दावा करता है। 'जनजाति' शब्द (मुंशी, 2013) का उपयोग भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा जाति शब्द से अलग समूहों की एक बड़ी संख्या को वर्गीकृत करने के लिए किया गया था। जनजाति शब्द समुदाय के जनसांख्यिकीय आकार, भाषाई और सांस्कृतिक लक्षणों, पारिस्थितिक स्थितियों और जीवन की भौतिक स्थितियों के संदर्भ में एक दूसरे से बहुत अलग है। जनजातियाँ अनिवार्य रूप से 'आदिम' हैं, और 'पिछड़ी' हैं। स्वतंत्रता के बाद, 'अनुसूचित जनजाति' (एसटी) शब्द का इस्तेमाल उन जनजातियों को निरूपित करने के लिए किया जाने लगा, जिन्हें भारत के संविधान के तहत अनुसूचित किया गया है। आदिवासी समुदाय सापेक्ष अलगाव, सांस्कृतिक विशिष्टता और उत्पादन और निर्वाह के निम्न स्तर के कारण अन्य समुदायों से अलग हैं। वे मूल निवासी हैं। उनके लिए कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे 'आदिवासी' (प्रारंभिक निवासी जनसमूह), 'वनवासी' (जंगलों के निवासी), 'वन्यजाति' (आदिम लोग), 'जनजाति (लोक जनसमूह), और 'अनुसूचित जाति' (एसटी)।

डब्ल्यू, एच. आर. रिवर्स ने जनजाति को एक सरल एक सामाजिक समूह कहा है, जिसके सदस्य एक सामान्य बोली बोलते हैं, एक ही सरकार है और युद्ध जैसे सामान्य उद्देश्यों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। (चौधरी, 1977)

2011 की जनगणना में भारत में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है जो भारत के 30 राज्यों में अधिसूचित हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तिगत जातीय समूहों की संख्या 705 है।

बॉक्स 6.1: आदिवासी और ब्रिटिश नीति

आदिवासियों के प्रति ब्रिटिश नीति के दो प्रमुख तत्व थे। सबसे पहले, इसने आदिवासी क्षेत्रों को मुख्यधारा से अलग करने का पक्ष लिया (भौमिक 1980, चौधरी 1982)। इस प्रकार 'बहिष्कृत' और/या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों की अवधारणा दी गई थी। क्योंकि ब्रिटिश आदिवासी नीति राजनीतिक और औपनिवेशिक थी, ब्रिटिश प्रशासन को डर था कि अगर इन आदिवासियों (धनुष-बाण सशस्त्र आदिवासियों को अक्सर उग्रवादी, बेलगाम और जंगली के रूप में चिह्नित किया जाता है) का भारतीय समाज की मुख्यधारा से संपर्क हुआ, तो स्वतंत्रता आंदोलनों को और मजबूती मिलेगी। इस पृष्ठभूमि में, उन्हें अलग-थलग करना, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से, उन क्षेत्रों के लिए तर्कसंगत लगता था, जिनमें मुख्यतः जनजातीय आबादी थी।

दूसरे, सुधार के स्तर पर, ब्रिटिश प्रशासन इन लोगों को 'सभ्य' करने में रुचि रखता था। एक जनजातीय-केंद्रित मूल्यांकन में, आदिवासियों को श्रेष्ठता के चरण के साथ देखा गया था। उदविकास के शास्त्रीय सिद्धांत, जिसने तत्कालीन आदिम जनजाति को और बर्बरता के अवशेषों या बची प्रारंभिक स्तर के मानवता प्रजाति के रूप में नब्बे

के दशक के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत में अकादमिक ध्यान आकर्षित किया था, सर ई.बी. टाइलर, के शब्दों में, यह पहाड़ी आबादी या विरल इलाके में आबादी और कठिन संचार के साथ रहने वाले लोग 'सामाजिक जीवाष्म' थे। उनका मानना था कि इनका अध्ययन, मानव अस्तित्व के प्रागैतिहासिक चरणों को उजागर करेगा (IGNOU (पुनर्मुद्रण): 2017 ईएसओ -12 ब्लॉक 6, ट्राइब्स इन इंडिया)

6.2.1 भारत में जनजातियों के विशिष्ट लक्षण

1) निश्चित सामान्य स्थलाकृति

आदिवासी लोग एक निश्चित स्थलाकृति के भीतर रहते हैं और यह उस क्षेत्र पर निवास करने वाले एक विशेष जनजाति के सभी सदस्यों के लिए एक आम जगह है। एक सामान्य लेकिन निश्चित रहने की जगह के अभाव में, आदिवासी एक आदिवासी जीवन की अन्य विशेषताओं को खो देंगे, जैसे कि आम भाषा, रहने का तरीका और सामुदायिक भावना आदि।

2) एकता की भावना

एक वास्तविक आदिवासी जीवन के लिए एकता की भावना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। जनजाति का अस्तित्व शांति और युद्ध के समय आदिवासियों की एकता की भावना पर निर्भर करता है।

3) अंतर्विवाही (Endogomos) समूह

आदिवासी लोग आमतौर पर अपने जनजाति के बाहर शादी नहीं करते हैं और जनजाति के भीतर शादी की बहुत सराहना की जाती है। लेकिन गतिशीलता की शक्तियों के कारण हुए परिवर्तनों के दबाव के प्रभाव ने भी आदिवासियों के रवैये को बदल दिया है और अब, अंतर-जनजातीय विवाह अधिक से अधिक आम हो रहे हैं।

4) आम बोली

एक आदिवासी समुदाय के सदस्य एक सामान्य बोली में अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। यह तत्व उनकी एकता की भावना को और मजबूत करता है।

5) रक्त-संबंध की मर्यादा

रक्त-सम्बन्ध सबसे बड़ा बंधन है और सबसे शक्तिशाली ताकत है जो आदिवासियों में एकता की भावना पैदा करता है।

6) सुरक्षा जागरूकता

जनजातीय लोगों को हमेशा घुसपैठ और घुसपैठियों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है और इसके लिए एक एकल राजनीतिक प्राधिकरण की स्थापना की जाती है और सभी शक्तियाँ इस अधिकार में निहित होती हैं। आदिवासी की सुरक्षा को राजनीतिक अधिकार का आनंद लेने वाले व्यक्ति की कुशलता और मानसिक शक्ति पर छोड़ दिया जाता है। आकस्मिक आपदा के समय एक आदिवासी समिति अपने मुखिया की सहायता के लिए तत्पर रहती है। जनजाति को कई छोटे समूहों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समूह का नेतृत्व अपने स्वयं के नेता द्वारा किया जाता है।

7) **विशिष्ट राजनीतिक संगठन**

हर जनजाति का अपना अलग राजनीतिक संगठन है जो आदिवासी लोगों के हितों की देखभाल करता है। पूरा राजनीतिक अधिकार एक आदिवासी मुखिया के हाथों में होता है। कुछ जनजातियों में, जनजाति के हितों में अपने कार्यों का निर्वहन करने में आदिवासी मुखिया की मदद करने के लिए आदिवासी समितियां मौजूद होती हैं।

8) **सामान्य संस्कृति**

एक जनजाति की सामान्य संस्कृति एकता की भावना से उत्पन्न होती है, जो एक सामान्य भाषा, सामान्य धर्म, आम राजनीतिक संगठन को साझा करने पर निर्भर करती है। आम संस्कृति आदिवासियों के बीच एकरूपता पैदा करती है।

9) **नातेदारी का महत्व**

नातेदारी आदिवासी सामाजिक संगठन का आधार बनती है। अधिकांश जनजातियाँ बहिर्मुखी कुलों और वंशों में विभाजित हैं।

10) **समतावादी मूल्य**

आदिवासी सामाजिक संगठन समानता के समतावादी सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रकार कोई संस्थागत असमानताएं नहीं हैं जैसे कि जाति व्यवस्था या लिंग आध ारित असमानताएं। इस प्रकार पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा और स्वतंत्रता मिली। हालाँकि, सामाजिक असमानता के कुछ अंश आदिवासी प्रमुखों या जनजातीय राजाओं के मामले में पाए जा सकते हैं, जो उच्च सामाजिक स्थिति का आनंद लेते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते हैं और धन अर्जित करते हैं।

11) **धर्म का सरल रूप**

जनजातियाँ कुछ मिथकों और धर्म के एक अल्पविकसित प्रकार में विश्वास करती हैं। इसके अलावा, वे उन कुलदेवताओं पर विश्वास करते हैं जो प्रतीकात्मक वस्तु होते हैं और जनजाति के सदस्यों के साथ रहस्यवादी संबंध रखने वाले तत्वों को दर्शाते हैं

बोध प्रश्न 1

नोट :1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) लगभग पाँच पंक्तियों में जनजाति की परिभाषा दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) जनजातियों की कम से कम दो प्रमुख विशेषताओं की सूची बनाएं।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.3 मध्य भारत में आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक संबंध

आदिवासी समुदाय की पहचान विशेष रूप से भारत के केंद्रीय क्षेत्र में आज भूमि विसंवधन और विकास परियोजनाओं के लिए वन और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधनों के बढ़ते वंचन के कारण भूमि और अन्य संसाधनों तक पहुंच में गिरावट के साथ जुड़ी है। जिसके परिणामस्वरूप, जनजातीय आबादी का अनुपातिक रूप से बड़े प्रतिशत उनके रहने के पारंपरिक तरीके से उचित पुनर्वास के बिना विस्थापित हो गया है। (सराप, 2017)

विभिन्न जनजातियों (705) से संबंधित कुल 104.3 मिलियन लोगों में से, प्रत्येक पांचवा व्यक्ति भारत के दिल में निवास करता है जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं (भारत सरकार, 2011)। इन राज्यों में रहने वाले आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कई मायनों में, पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले लोगों से अलग है। इसका कारण यह है कि ये मुख्य रूप से अत्यधिक गरीबी केन्द्रिक वन-आधारित क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आदिवासी उत्तर-पूर्व भारत की तुलना में सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत निचले स्तर पर हैं। ऐसे लोगों के सामने गरीबी की समस्या बहुआयामी है जिसमें आय, और मानव असुरक्षा भी सम्मिलित है। (कन्नन और रवीन्द्रन, 2011, राधाकृष्ण 2015, और सराप 2017)

राज्यों के भीतरी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के लक्षण हैंः संपत्ति के निम्न स्तर, मानव पूंजी के निम्न स्तर, निर्णय लेने की प्रक्रिया में राजनीतिक भागीदारी की कमी और राजनीतिक आवाज (डी हैन एंड दुबे, 2005) की कमी। इसके अलावा, वे कई अभावों (बख्शी, चावला और शाह, 2015) और मानव असुरक्षा से घिरे रहते हैं। (सराप, 2017)।

आदिवासी गरीबी के प्रमुख कारणों में सुरक्षित उत्पादक संसाधनों जैसे भूमि, जंगल, अन्य सामान्य संपत्ति संसाधन जैसे चराई के मैदान, तालाब, टैंक आदि) तक पहुंच का अभाव है, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी अपर्याप्त भागीदारी है। संसाधनों पर हक न होने के नुकसान ने न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित किया है, बल्कि उन्हें गरीब बना दिया है। विभिन्न प्रकार के संसाधनों तक उनकी पहुंच में निरंतर क्षरण हो रहा है, जिस पर आदिवासी अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में मध्य भारत के आदिवासी समुदायों में गरीबी का स्तर अधिक है। (राधाकृष्ण, रवि और रेड्डी, 2013)। भूमि विसंबंधन और ऋणग्रस्तता के कारण वे हाशिए पर हैं (सराप, 2017)। बिचौलियों द्वारा स्थानीय व्यापारियों को उनके कृषि और वन उत्पादों की बिक्री की समस्या है। यहां तक कि आदिवासी श्रम का बाजारीकरण किया गया है (सराप और स्प्रिंगेट-बैगिंस्की, 2013)। राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रदर्शन खराब है। स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे मानव विकास के रूप में उनका प्रदर्शन अप्रभावी है (भारत सरकार 2014)।

राष्ट्र में अन्य समुदायों की तुलना में आदिवासी समुदायों के बीच साक्षरता दर धीमी गति से बढ़ रही है। (सराप 2017) आदिवासी लोगों के पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर के अलावा विभिन्न जनजातीय समुदायों के बीच साक्षरता के स्तर में अंतर है। शिशु मृत्यु दर, रुग्णता, कुशल स्वास्थ्य देखभाल जैसे स्वास्थ्य संकेतक भी बहुत खराब हैं। महिला प्रधान परिवारों को जनजातीय समुदाय के बीच देखा जा सकता है। महिलाओं द्वारा आधारित बाल गरीबी और नुकसान बहुत अधिक हैं। महिलाएं वंचित समूहों में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कई प्रकार के भार से पीड़ित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता तक उनकी पहुंच अपर्याप्त हैं (डी हैन 2004 द वर्ल्ड बैंक, 2011)। आदिवासी परिवार विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों और उनके जनसांख्यिकीय, व्यावसायिक और शैक्षिक स्तरों में बदलावों के बावजूद गरीब होते हैं। (किजिमा, 2006)। मध्य भारत में आदिवासी बहुल क्षेत्रों की विशेषता सड़कों, बाजारों, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं की खराब पहुंच है। जनजातीय क्षेत्रों के अवसंरचना से वंचित होने से वस्तुओं के उत्पादन और विपणन के परिवहन और लेनदेन की लागत में वृद्धि होती है, और जनजातीय लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई पैदा होती है। आदिवासी क्षेत्रों की दूरियां उनकी वाणिज्यिक और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को बढ़ाती है।

इससे जनजातीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन की संभावना कम हो जाती है। कम कृषि उत्पादकता और उनके श्रम के लिए कम रिटर्न को देखते हुए (किजिमा, 2006, सराप 2017 देखें), आदिवासी लोगों के लिए उपलब्ध शुद्ध अधिशेष सीमांत या नकारात्मक है। आदिवासी क्षेत्र खनिज और अन्य संसाधनों से समृद्ध हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से, आदिवासी समुदायों को इस धन का एक हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया है। इस तरह के संसाधनों का स्वामित्व उनके पास होता है क्योंकि वे उस जमीन के नीचे पाए जाते हैं जो आदिवासियों के पास है लेकिन उन्हें छोटे संसाधनों के उपयोग से बाहर रखा गया है। उन्हें बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए खनिजों और जल संसाधनों को निकालने की अनुमति नहीं है। परिणामस्वरूप, उन्हें विस्थापित किया गया है और 'प्रतिकूल समावेश' के अधीन किया गया है, जिसने उन्हें सामाजिक पदानुक्रम (चटर्जी, 2008) के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में, भूमि और निवास के नुकसान और बांधों, खानों और उद्योगों के कारण वासभूमि क्षेत्र के विखंडन के परिणामस्वरूप पूर्ण वंचना होती है, (मुंशी, 2012, देखें सराप, 2017)। इन प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण व्यक्तियों और समुदायों का निर्वासन हुआ है। अवसरों की कमी, अर्थात् विकास कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और लाभों से सामाजिक बहिष्कार के परिणामस्वरूप सापेक्ष अभाव भी है। आदिवासी समुदायों की आजीविका की स्थितियों में गिरावट के लिए जिम्मेदार, नीचे की गई चर्चा नीतियों सहित कई कारक हैं।

6.3.1 आजीविका तक पहुँच से संबंधित मुद्दे

जनजातीय लोगों की आजीविका के स्रोत तक पहुंच क्षेत्रीय संस्थागत और सरकारी (सहायता) पर निर्भर करती है। उन्हें न केवल अपनी आजीविका के स्रोतों में सुधार करना चाहिए, बल्कि मुख्यधारा बनाने की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए यानी उन्हें अन्य लोगों के करीब लाना और अन्य समुदायों और समाजों के साथ जनजातीय समुदायों का एकीकरण करना चाहिए। उनकी क्षमता बढ़ाने की भी जरूरत है। कृषि, वन और विकास नीतियों सहित सरकारी नीतियां इन समुदायों को उनके सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं (डी हैन और दुबे, 2005)

6.3.2 कृषि नीतियां, भूमि कानून और आदिवासियों के बीच भूमि विसंबंध

आजीविका के एक प्रमुख स्रोत के रूप में भूमि कृषि उत्पादन और समृद्धि में प्रत्यक्ष और एक अनिवार्य भूमिका निभाती है, लेकिन जनजातीय आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका के इस स्रोत तक पहुंच को व्यापक बनाने में राज्यों की कृषि नीतियां अपेक्षाकृत अप्रभावी रही हैं। इसका कारण इस तथ्य से माना जा सकता है कि स्वतंत्र भारतीय राज्यों ने निजी संपत्ति शासन को प्रोत्साहित किया है, लेकिन राज्य संपत्ति शासन जारी रहा और सामुदायिक भूमि की प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया। नतीजतन, निजी संपत्ति के रूप में जमीन का निपटान नहीं हुआ, जिससे ये अपने आप से राज्य की संपत्ति बन गई, जिसमें वनभूमि भी शामिल थी (एकहा, 2011, कुमार एंड कं., 2013, सराप और सारंगी, 2010)। हालांकि वनभूमि मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों के स्वामित्व में थी। कई आदिवासी क्षेत्रों में, अपेक्षित सर्वेक्षण कभी नहीं किया गया था। इस प्रकार, वन भूमि के विशाल भाग पर इन लोगों के अधिकारों को कभी मान्यता नहीं दी गई थी, हालाँकि भूमि का स्वामित्व इन आदिवासी समुदायों (खाका , 2007, सराप 2017) के साथ में था। इसके अलावा, किसानों के बढ़ते दरिद्री-करण और हाशिए पर जाने से आदिवासियों की आजीविका प्रभावित होती रही है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों में आदिवासी परिवारों के बीच भूमिहीनता की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया गया है, जिसके कारण उनकी गरीबी बढ़ रही है । बिना किसी खेती की भूमि (भूमिहीनता) वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़ता रहा है। यह उल्लेखनीय है कि जिन परिवारों के पास खेती या कृषि भूमि नहीं है, वे 1987-88 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 (करात और रावल, 2014) में 39 प्रतिशत हो गए हैं। इसी तरह, जिन आदिवासी परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है, वे 13 से 25 फीसदी तक बढ़ गए हैं और ऐसे घर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, उसी अवधि (सराप, 2017) के दौरान 16 से 24 फीसदी तक बढ़ गए हैं।

बोध प्रश्न 2

नोट :1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) मध्य भारत के आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। पांच लाइनों का उपयोग कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) क्या मध्य भारत के आदिवासियों की वन भूमि तक पहुँच है?

.....

.....

.....

.....

6.4 जनजाति और वन

कुछ आदिवासी समूह अपने एकमात्र व्यवसाय के रूप में शिकार और भोजन एकत्र करने का कार्य करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश किसान और खेतिहर मजदूर हैं। बाकी लोग घरेलू उद्योग, निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, खनन और उत्खनन और अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं। उनका एक छोटा वर्ग सरकार के सुरक्षात्मक उपायों से लाभ प्राप्त करता है, जैसे कि, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण, रोजगार और राजनीतिक आरक्षण लेकिन उनमें से अधिकांश स्वतंत्रता के बाद से पिछले सात दशकों के तथाकथित विकास की प्रक्रिया से हाशिए पर हैं। (मुंशी, 2013)।

अधिकांश आदिवासी समूह गैर-आदिवासी कृषि समुदायों की तुलना में कृषि और वन से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। जंगल पर उनकी निर्भरता विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उनके लिए वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता पर्याप्त है। उनकी कृषि गतिविधियाँ जंगल के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। जंगल, भोजन का एक प्रमुख स्रोत के रूप में घर के निर्माण के लिए लकड़ी और कृषि उपकरण, ईंधन लकड़ी, दवाइयां, और रोजमर्रा की जिंदगी की अन्य आवश्यकताओं के लिए रहा है, और आज भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जंगल से पत्ते, फल, फूल, जड़ें, कंद आदिवासियों के आहार के लिए विशेषकर दुबले मौसम और सूखे की अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण पूरक है।

जंगलों से जंगली फल, जामुन और शहद एकत्र किए जाते हैं और खाए जाते हैं। बांस और लकड़ी कृषि और मछली पकड़ने के उपकरण बनाने के लिए आवश्यक हैं। जड़ी बूटी कई बीमारियों के लिए दवा के रूप में काम करती है। तेल और साबुन भी जंगल से इकट्ठा किए जाते हैं। वास्तव में, आदिवासियों की लगभग पचास से अस्सी प्रतिशत खाद्य आवश्यकताएं जंगल द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। बांस, ईंधन की लकड़ी, तेंदू पत्ते (बीड़ी/सिगरेट को लपेटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ियों से ली गई पत्तियां) और सूखे फल मेवे जैसे वन उपज की बिक्री आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आदिवासी लोगों की मान्यता है कि देवता और आत्माएं जंगल, पेड़ों और जानवरों में निवास करते हैं। वे उनकी भक्ति के विषय भी हैं। वन संसाधन आदिवासी समुदायों की सामग्री और आध्यात्मिक अस्तित्व के प्रमुख स्रोत हैं (मुंशी, 2013)।

औपनिवेशिक शासन के दौरान उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में पर्यावरणीय कारणों से वनों की रक्षा और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, राजस्व और शाही उद्देश्यों के लिए, टिकाऊ आधार पर लकड़ी के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई नियम पारित किए गए हैं । वनों और वन उपज के प्रबंधन से संबंधित कानूनों को बाद में 1927 के भारतीय वन अधिनियम में समेकित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ईंधन की लकड़ी और बांस को हटाने और स्थानांतरित खेती को करने पर के बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई उदाहरणों में, चरागाह भूमि को 'अनारक्षित' और 'संरक्षित' जंगलों में शामिल किया गया, जिससे मौजूदा चराई व्यवस्था प्रभावित हुई। राज्य के नियंत्रण में भारत में वनों के बड़े पैमाने पर 'आरक्षित' वनों का निर्माण, जिनकी देखरेख और प्रबंधन वन विभाग करता है, जिसके परिणामस्वरूप वन समुदायों के प्रथागत अधिकारों पर प्रतिबंध उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। इन समुदायों को वन अधिकारियों के हाथों बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने प्रतिबंधों को बहुत गंभीरता के साथ लागू किया और यहां तक कि विनियमन के एक मामूली उल्लंघन को अपराध माना गया।

अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए वन प्रबंधन ने जंगल के संवर्धित वाणिज्यिक मूल्य के परिणामस्वरूप सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत खोल दिया। रेलवे से शहरी केंद्रों, सैन्य छावनियों और हिल स्टेशनों की बढ़ती मांग, और सागौन के बढ़ते वाणिज्यिक

मूल्य और अन्य मामूली वन उपज को जंगलों के आर्थिक मूल्य में जोड़ा गया। वन विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से बढ़ाई गई नियंत्रण की व्यवस्था कारण जंगल पर निर्भर लोगों द्वारा अधिक से अधिक वन अपराध और अपराध किए जाते हैं। आदिवासी नियंत्रण के तहत भूमि और जंगल, राज्य नियंत्रण और प्रबंधन के तहत लाए गए थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद, भूमि के वंशाधिकार/गांव के स्वामित्व को मान्यता नहीं दी गई थी। इसके अलावा, स्थानांतरित कृषि को एक वैध कृषि पद्धति के रूप में करने की गैर-मान्यता उत्तर पूर्व को छोड़कर मौजूद थी। औपनिवेशिक राज के बाद भी भारतीय राज्य ने औपनिवेशिक नीति को विरोधाभासी रूप के साथ जारी रखा है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों स्थानांतरित काश्तकारों का सदियों से अपने खुद के जंगलों पर कोई वैध अधिकार नहीं है।

भूमि और जंगल पर आदिवासी लोगों के पारंपरिक अधिकारों को न तो मान्यता दी गई और न ही दर्ज किया गया। वन भूमि पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के निर्माण ने इन समुदायों को उनके अस्तित्व के आधार से बाहर रखा। वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण को एक तात्कालिक आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन वन और इसके उत्पादन के लिए आदिवासी अधिकारों का निपटान ईमानदारी और गंभीरता के साथ नहीं किया गया था, जो इसके हकदार थे और जो लोग वन भूमि का उपयोग करना जारी रखते हैं, उन्हें 'अतिक्रमणकारी' माना जाता है, उनसे वन छीन लिया गया है तथा उन्हें कोई भी सुरक्षा अधिकार नहीं प्राप्त है (मुंशी, 2013)।

6.4.1 भूमि और आजीविका का नुकसान

जबसे आदिवासियों को स्थानांतरित खेती से दूर रखा गया उनके आजीविका के स्रोत का नुकसान हुआ क्योंकि इसे व्यर्थ और विनाशकारी माना जाता था लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे नियमित राजस्व का स्रोत माना और इसलिए, आदिवासियों को जोतने के लिए जमीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया लेकिन मूल्यांकन की कम दरों पर। हालांकि, कृषि औजार की कमी, मिट्टी की खराब गुणवत्ता, लगातार फसल की विफलता और कठोर राजस्व की मांग, अक्सर किसानों, आदिवासियों और गैर-आदिवासियों, को बीज, उपभोग की वस्तुएं और यहां तक कि सरकार को राजस्व का भुगतान करने के लिए पैसे भी उन्हें ऋण की ऊंची दरों पर उन्हें लेने के लिए मजबूर करते हैं। कई हिस्सों में, ऋणग्रस्त वर्गों के लिए खेती की बढ़ती ऋणग्रस्तता और भूमि के हस्तांतरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। इस तरह, एक शक्तिशाली वर्ग उभरा जिसने धन-उधार, व्यापार और शराब बेचने की संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में भूमि और धन एकत्र किया। इस प्रवृत्ति ने आदिवासियों को बंधुआ मजदूरों और पट्टेदारों की स्थिति में ला दिया है। इस प्रकार, एक कम निर्वाह से, आदिवासी पूरी तरह से अपने अस्तित्व के लिए जमींदार-साहूकारों, व्यापारियों, दुकानदार पर निर्भर हो गए। धन उधार देने वाले वर्ग द्वारा शोषण और उत्पीड़न ने न केवल उन्हें अत्यधिक गरीबी की अवस्था में लाया बल्कि उनके स्वाभिमान को भी कम कर दिया।

6.4.1.1 स्वतंत्र भारत में भूमि और आजीविका का नुकसान

निर्भरता और बंधन के लिए आवश्यक पूर्व-स्थिति का कारण वन और भूमि और अन्य संसाधनों पर निर्वाह से आदिवासियों का विसंबंध था। 19वीं शताब्दी के अंत तक उनका विसंबंध लगभग पूरा हो गया था। देश के कई हिस्सों में, आदिवासी स्थानीय उत्पीड़कों और प्रशासकों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए गैर-आदिवासियों में शामिल हो गए। उन्होंने भूमि, वन औरों के अधिकार कम करने, भोजन की कीमत कम करने आदि की मांग की।

आदिवासियों को अलग-थलग करने से रोकने के लिए बने विधानों के बावजूद, वे अपनी जमीन और अपनी आजीविका के स्रोतों को खोते रहे।

6.4.1.2 स्वतंत्र भारत में भूमि और आजीविका का नुकसान

स्वतंत्रता के बाद के दशक भारत में गहन विकास योजना के दशक थे। यह औद्योगीकरण और शहरीकरण के आसपास केंद्रित राष्ट्र निर्माण के एजेंडे के माध्यम से मुख्यधारा के विकास से आदिवासी समुदायों के हाशिए पर जाने का समय भी था। इस प्रक्रिया के साथ बड़े बांधों, बड़े औद्योगिक परिसरों, बुनियादी ढांचे, बाजार के लिए खानों और जंगलों के विघटन और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण पर आदिवासी बसे हुए क्षेत्रों में बढ़ती हुई शहरी और औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए जहां अधिकांश समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, ऐसी जगह में निर्माण कार्य किया गया था। भारत में आदिवासियों पर इस प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव को उष्णकटिबंधीय जंगलों के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा रिपोर्ट किया गया।

यह बताया गया कि उद्योगों, खानों, नगरनिर्माण, बांधों, वन स्थानों के हानि के प्रतिकूल प्रभाव का दोष आदिवासी लोगों पर थोपा गया।

आदिवासी समुदायों ने राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का भार वहन किया। भूमि अधिग्रहण, औपनिवेशिक कानून का एक भाग था, जो क्राउन यानि शासन के लिए भूमि का अधिग्रहण का काम करता था। यह औपनिवेशिक राज्य के हाथों में एक साधन के रूप में शक्ति थी कि वे अपने लाभों को उन्नत और अग्रिम वर्गों (मुंशी 2013) के पास ले जाएं। 10 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए और जो उनके पास था वे सभी खो गया और लाखों आदिवासी समुदायिक एवं सांस्कृतिक हत्या के कगार पर पहुंचाए गए । लगभग पूरे मध्य भारत में एक असंतोष था जो खुद को आदिवासी क्षेत्र में धकेलता पाया गया, विशेष रूप से भूमि और जंगल के मुद्दों और इन से अलग होने पर। कुछ मामलों में रुक-रुक कर लोगों और राज्य के बीच हिंसक टकराव हुआ। आदिवासी लोग भूमि और राष्ट्रीय संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों की अवहेलना के साथ लगभग सभी मायने में अपने संसाधनों पर लगातार नियंत्रण खोते जा रहे हैं। वस्तुतः विभिन्न विकास परियोजनाओं (मुंशी 2013) के पक्ष में मजबूरन विस्थापन हुआ है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उपक्रमों, विकास परियोजनाओं और उद्योगों ने आदिवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया में योगदान दिया है। जिस राज्य को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए, उसने उनके शोषण में बहुत योगदान दिया है। वन की कमी और विनाश ने आदिवासी समुदायों के पहले से ही नाजुक अस्तित्व के आधार को नष्ट कर दिया है। सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी महिलाएं हैं, जिन्हें अब परिवार और उनके परिवार के ईंधन, पानी, भोजन और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बड़ी संख्या में आदिवासियों को मौसमी या स्थायी रूप से अन्य ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी मैदानों या शहरों में प्रवास करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उनकी आजीविका के पारंपरिक स्रोतों से वंचित होने के कारण काम के अवसरों की तलाश है। वे थोड़ी सुरक्षा और संरक्षण के साथ 'असंगठित क्षेत्र के विस्तार का एक हिस्सा' चलायमान परन्तु अस्थायी श्रमिकों की एक बड़ी सेना का गठन करते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि उत्तर-पूर्व के आदिवासी क्षेत्र की स्थिति मध्य और दक्षिणी भारत से भिन्न है। त्रिपुरा, असम और मणिपुर को छोड़कर, इस क्षेत्र ने औपनिवेशिक दिनों में भी अधिक प्रवास का अनुभव नहीं किया। हालांकि हाल के दिनों में, भूमि और अन्य संसाधनों

का विसंबंध हुआ है। लेकिन यह देश के बाकी हिस्सों की तरह व्यापक नहीं है, विशेष रूप से केंद्रीय जनजातीय क्षेत्र में। इस क्षेत्र के आदिवासी, पैथी के अनुसार, अपने अस्तित्व के लिए संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में आदिवासी बहुसंख्यक हैं। वे यहां भी संघर्ष करते हैं, लेकिन राज्य द्वारा भूमि के अलगाव और संसाधनों के बहिष्कार के साथ उनका बहुत कम संबंध है। वे अपनी राजनीतिक भागीदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। (मुंशी, 2013)।

भूमंडलीकरण और उदारीकरण की नीति ने न केवल आदिवासियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से अलग करने की प्रक्रिया को तेज किया है बल्कि उनके लिए अधिक असुरक्षा पैदा की है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सीमाओं पर मानव संसाधनों, वस्तुओं, वित्त और प्रौद्योगिकी के मुक्त आवागमन ने इन समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह देखा गया है कि आदिवासी भूमि का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है। यह उन्हें अपनी भूमि से अलग करता है। वन प्रबंधन परियोजनाओं की पांचवीं अनुसूची और संरचना में संशोधन करने के लिए अब प्रयास हो रहे हैं और आंध्र प्रदेश में भारतीय तंबाकू कंपनी जैसी बड़ी निजी कंपनियों के हितों को शामिल करने के लिए संसाधन तैयार किये जा रहे हैं। जिंदलों ने अपने इस्पात संयंत्र के लिए छत्तीसगढ़ में बेनामी लेनदेन के माध्यम से आदिवासी जमीन खरीदी है। सहारा हाउसिंग लिमिटेड ने एक पर्यटन परियोजना (मुंशी, 2013) के लिए महाराष्ट्र के 3,760 एकड़ आदिवासी और वन क्षेत्रों को हड़प लिया।

सरकार ने बड़ी बहुराष्ट्रीय खनन कंपनियों और उनके भारतीय भागीदारों के लिए रास्ता साफ करने के लिए आदिवासी लोगों को बड़े पैमाने पर निष्कासित किया है, जो भारत में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट यूरेनियम और अन्य जैव-विविधता का दोहन करने के लिए आ रहे हैं। ओडिशा सरकार ने पहले ही 35 कंपनियों को लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए खनन अधिकार दे दिए हैं, जिनमें पोस्को को अनुदान और बड़ी संख्या में एल्यूमीनियम कंपनियां शामिल हैं। खनन और उत्खनन ने हाल ही में बहुत ध्यान आकर्षित किया है। यह एक प्रमुख लाभ के रूप में उभरा है – उद्योग को अक्सर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बल और धोखाधड़ी, कानूनी और अवैध साधनों का संयोजन करना पड़ता है। हालांकि, खनन क्षेत्र एक तरफ स्थानीय लोगों के बीच हिंसक राजनीतिक झड़पों का स्थान है, और दूसरी ओर निजी पूंजी और राज्य के पारिस्थितिक विनाश, आदिवासियों की पारंपरिक आजीविका का नुकसान और उनके विस्थापन का स्थान है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प देखी गई है। वास्तव में, इस जगह ने क्षेत्र में माओवादी प्रभाव को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर राज्य दमन देखा है। यह बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद पहले साढ़े चार दशकों में, खनन ने लगभग ढाई करोड़ लोगों को विस्थापित किया था, और उनमें से 25 प्रतिशत से भी कम का पुनर्वास हुआ था। इसमें 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी समुदायों के थे। यह अनुमान लगाया गया था कि देश में खनन के लिए 1,64 लाख हेक्टेयर वन भूमि पहले ही हटा दी गई है (मुंशी, 2013)।

माओवादियों के नेतृत्व में आदिवासियों के विरोध प्रदर्शनों ने केंद्र के साथ-साथ राज्य के साथ-साथ निजी हितों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों से भूमि के अवैध अधिग्रहण को जारी रखने की समस्याओं को केंद्र में लाया है और परिणामस्वरूप जनजातीय समुदायों को उनके संसाधन आधार से अलग कर दिया है। अधिकांश राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्र वे हैं जो अन्य प्राकृतिक संसाधनों में वन और समृद्ध हैं, और जो आदिवासी समुदायों के लिए घर हैं (मुंशी, 2013)।

बॉक्स 6.2: औद्योगिकीकरण का प्रभाव

संथाल बहुल क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापित होना, परिवर्तन और आधुनिकीकरण का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारक था। इन उद्योगों ने शिक्षित और निरक्षर दोनों को रोजगार दिया और गतिशीलता का एक नया स्रोत पेश किया।

इसके अलावा, ये उद्योग एक या दूसरे धार्मिक वर्चस्व से मुक्त थे। उन्होंने जाति-मुक्त और वर्ग-मुक्त व्यवसाय को बढ़ावा दिया। बड़ी संख्या में संथालों ने उनमें रोजगार पाया। ये उद्योग, स्थानीय आदिवासियों की भर्ती कर रहे हैं। लोगों को अपने पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। वास्तव में, ये उद्योग 'परिजनों की दुनिया' थी। आदिवासी-श्रमिकों द्वारा संथाल पहचान को और मजबूत किया गया।13:11)।

संविधान का पांचवां अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि और जंगलों पर पूरा अधिकार देता है और निजी कंपनियों को उनकी जमीन पर खनन करने से रोकता है। राज्य के कल्याणकारी उपायों से केवल कुछ ही आदिवासी लाभान्वित हुए हैं। युवा आदिवासी पुरुषों और महिलाओं का एक छोटा हिस्सा अपनी पारंपरिक जीवन शैली को जारी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश आदिवासियों को लगता है कि वे अपनी इच्छाओं के खिलाफ अपनी आजीविका के पारंपरिक स्रोतों से वंचित हैं। उन्हें रोजगार लेने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें जीवन की थोड़ी सुरक्षा और गुणवत्ता प्रदान करते हैं।

इस प्रकार, पिछले कुछ दशकों में लाखों आदिवासी विस्थापित हुए हैं, जो विकास परियोजनाओं, औद्योगिक गतिविधियों, वन संरक्षण और विकास की प्रक्रियाओं को अनदेखा करने के लिए रास्ता बना रहे हैं। हालाँकि, ये घटनाक्रम आदिवासियों की कीमत पर हैं। राज्यों की अदूरदर्शी नीतियों ने प्राकृतिक संसाधनों और विस्थापन को नष्ट कर दिया है। आदिवासी समुदायों के अनुभवों को सर्वश्रेष्ठ रूप से 'तंत्रों की हानि' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विस्थापन के बाद, आदिवासियों का पुनर्वास एक दर्दनाक अनुभव है। पुनर्वास स्थलों में स्थितियाँ अक्सर इतनी लचर होती हैं कि बहुसंख्यक आदिवासी अपने गाँव, परिजन समूह, वन क्षेत्रों में लौट जाना चाहते हैं जहाँ वे संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। वे बागान और उद्योगों में आकस्मिक श्रम के रूप में और घरेलू नौकरों, रिक्शा-चालक और अपरिचित स्थानों (मुंशी, 2013) में निर्माण श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए वे अपने पुनर्वास से बाहर रहना भी पसंद कर सकते हैं।

6.4.2 अधिनियम और प्रतिरोध

देश के सामने पर्यावरणीय समस्याओं के बारे विशेष रूप से हमारे वन संसाधनों के ह्वास में देर से जागरूकता बढ़ी है, संसाधनों और संसाधनों की कमी और अभाव के कारण आदिवासी समूहों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ रहा है। (गुहा, आर. 2013)।

आदिवासी अधिकारों को पूर्ण करने के कार्य और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण खोने से होने वाले नुकसान ने आदिवासी वन समुदायों से एक तीव्र प्रतिक्रिया पैदा की है। वन प्रशासन के शुरुआत से ही जंगलों के सवाल पर, जंगलों के आसपास केंद्रित विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह हुए हैं। उदाहरण के लिए, गढ़वाल में, 1913 में वनों का आरक्षण, 1916 और 1921 में व्यापक सामाजिक आंदोलनों के बाद, पहला गैर-सहयोग आंदोलन था, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं के बड़े क्षेत्र शामिल थे। इन उतार-चढ़ावों ने सरकार को बड़े वन क्षेत्रों को आरक्षित करने के लिए मजबूर किया।

वन प्रतिबंधों के कारण आदिवासी लोगों के बीच जो असंतोष उभरा उसने ग्रामीणों की अनिच्छा होने पर भी वन संरक्षण (गुहा, आर. 2013) के कार्य में वन विभाग के साथ सहयोग करने में व्यक्त हुआ।

कई क्षेत्रों में राज्य ने ग्रामीणों द्वारा उपयोग के लिए बस्ती के तहत गांव के जंगलों के रूप में कुछ जंगलों को बनाया है, लेकिन जंगलों के सामुदायिक स्वामित्व के नुकसान ने प्रभावी रूप से आदमी और जंगल के बीच की कड़ी को तोड़ दिया है। जंगल से आदमी के इस अलगाव की तुलना उत्पादन के साधन से अलग किए जा रहे प्राथमिक उत्पादक के अलगाव से की जा सकती है। नतीजतन, टिहरी गढ़वाल में शताब्दी के शुरुआती वर्षों से छिटपुट वन आंदोलन हुए। संघर्ष और संघर्ष के इस इतिहास को अनिवार्य रूप से अलगाव, संपत्ति के अधिकार और दायित्व द्वारा निकलते हुए देखा जा सकता है (गुहा, आर. 2013)।

6.4.3 भूमि के मुद्दे पर नए तरह का संघर्ष

जमीन के मुद्दे पर संघर्ष का एक नया रूप कुछ आदिवासी समुदायों के भीतर शुरू हुआ है जहाँ आदिवासी महिलाएँ जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आदिवासियों/आदिवासी महिलाओं को भूमि अधिकारों से वंचित करना बहुत चिंता का विषय रहा है। किश्वर द्वारा किया गया आदिवासी समुदाय पर अध्ययन (1987: 200) का तर्क है कि 'हो' जनजाति के पुरुषों का भूमि और अन्य आय सृजन गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के परिवार की आजीविका में अधिक से अधिक योगदान के बावजूद ''हो'' महिलाओं का अधिक शोषण हुआ है। बिहार के संथाल जैसे आदिवासी महिलाओं के उदाहरण हैं, जिन्हें आदिवासी समुदाय के पुरुषों द्वारा जमीन के अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए समर्थन दिया जाता है (मुंशी, 2013)।

6.4.4 जनजातीय अशांति

वनों के शोषण में वृद्धि के साथ, वन जनजातीय समुदायों ने अपने निवास स्थान पर अपने नियंत्रण खोने के नुकसान का अनुभव किया है। यह अभाव आंदोलनों की एक श्रृंखला में प्रकट हुआ है जो पचास और साठ के दशक में रुक-रुक कर बार-बार हुये। वर्तमान में हम अधिकांश क्षेत्रों में अशांति पाते हैं। उत्तर में उत्तराखंड से लेकर पूर्व में झारखंड और पश्चिम में ठाणे धूलिया तक इन आंदोलनों का अध्ययन किया गया है। तेजी से उग्रवादी संघर्ष भूमि और जंगल पर सामुदायिक नियंत्रण हासिल करने के सवाल पर केंद्रित है। राज्य की प्रतिक्रिया में वृद्धि हुई है, इन आंदोलनों को दबाने के लिए सशस्त्र बल का उपयोग किया गया है जैसा कि 1980 की गुआ फायरिंग के मामले में था। राज्य ने सशस्त्र बलों, वन विभाग और पुलिस नौकरशाही को अधिक अधिकार दिए हैं। (गुहा, आर.2013)।

6.5 सारांश

इस इकाई में आपको भारत में आदिवासियों की स्थितियों का पता चला। जनजातियों के अर्थ और विशेषता का वर्णन किया गया था। उनके पास प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपने मिथक, लिंग, समस्याएं और पहचान की भावना है। हमने बताया कि कैसे विकास कार्यक्रमों ने आदिवासी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसमें उनके कृषि के पारंपरिक तरीके स्वरूप और उनकी आजीविका के प्राकृतिक स्रोत भी शामिल हैं। आरक्षित वन के बड़े पथों के बाड़ के द्वारा सीमांकन ने आदिवासी वनवासियों को उनके आवास और उनके अस्तित्व के संसाधनों पर नियंत्रण के प्रभावी नुकसान पहुंचाया है। आदिवासी समुदायों और उनके

प्राकृतिक संसाधनों के आधार, उनके कौशल, प्रथाओं, परंपराओं, ज्ञान, योग्यता और इच्छाओं का विकास अवरुद्ध हुआ है।

बोध प्रश्न 3

नोट :1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) भारत में आदिवासी लोगों की प्रमुख आजीविका जागरूकता के बारे में संक्षेप में बताएं। दस पंक्तियों का उपयोग करें

.....

.....

.....

.....

.....

2) भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जंगलों में रहने वाली जनजातियों को कैसे प्रभावित करती है?

.....

.....

.....

.....

.....

6.6 संदर्भ

बेली, एफ.जी. 1961. भारतीय में 'जनजाति और भारत में जाति', नागरिक शास्त्र , वॉल्यूम -5। पृ.7-19.

घुर्ये, जी.एस. (1963). अनुसूचित जनजाति, लोकप्रिय प्रकाशन, प्रा. लिमिटेड, बॉम्बे।

हेमेन्दोर्फ , सी.वी.फ. C.V.F. (1977). भारत में जनजातीय समस्याएं भारत में जाति और धर्म में संपादन द्वारा रोमेश थापर मैकमिलन, दिल्ली।

कायरप साराप 2017। मध्य भारत के जनजातीय बेल्ट में संसाधन, गरीबी और सार्वजनिक कार्रवाई तक पहुंच का क्षरण। समाजशास्त्रीय बुलेटिन 66 (1) 22 पृ. 41। भारतीय समाजशास्त्रीय समाज, साधु प्रकाशन।

मुंशी, इंद्र। 2013. आदिवासी प्रश्नः भूमि, वन और आजीविका के मुद्दे, ओरिएंट ब्लैक स्वान, नई दिल्ली।

पुरकायस्थ, नबरुन, 2016. भारतीय जनजाति की अवधारणाः एक सिंहावलोकन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज वॉल्यूम 5,. नंबर 2, फरवरी 2016

गुहा, रामचंद्र 2013: ब्रिटिश और वानस्पतिक भारत में वानिकीः एक ऐतिहासिक विश्लेषण।

टीबा, आर, (संपादन) 2010. पूर्वोत्तर भारत और विकास की अनुसूचित जनजाति, बी. आर, प्रकाशन निगम, दिल्ली।

ठाकुर, शीतल 2012, भारतीय जनजातियों के सामाजिक समावेशन और बहिष्करण का मुद्दा, कला, प्रबंधन और मानविकी पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 1 (1): 14-19 (2012)

खाका, वर्जीनियस 1999. भारत में जनजातियों का परिवर्तनः प्रवचन की शर्तें। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक। वॉल्यूम। 34, नंबर 24 (जून 12-18, 1999), पृ. 1519-1524.

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) यह शब्द लैटिन शब्द 'ट्राइबर्स' से लिया गया है, जो एक निवास स्थान को संदर्भित करता है। यह उन लोगों के एक समूह को दर्शाता है जो एक समुदाय से संबंधित है जो एक आम 33 से एक सामान्य वंश का दावा करते हैं। वे सभी एक ही भाषा, सांस्कृतिक विशिष्टता और सापेक्ष बाहरीपन को साझा करते हैं।

2) एकता की भावना और एक सामान्य बोली या भाषा जनजातियों की दो प्रमुख विशेषताएं हैं।

बोध प्रश्न 2

1) आदिवासी लोगों को विशेष रूप से मध्य भारत से संबंधित भूमि के अलगाव और विकास की बहुत प्रक्रिया में आजीविका के अपने पारंपरिक स्वरुप के विघटन का सामना करना पड़ा क्योंकि औद्योगिक और खनन जैसी बड़ी परियोजनाओं ने भूमि ने उनके प्रवेश को रोक दिया।

3) मध्य भारत में कोई भी आदिवासी औपनिवेशिक काल के साथ-साथ समकालीन समय के दौरान वन भूमि तक पहुंचने के अपने पारंपरिक अधिकारों को नहीं खोता था।

बोध प्रश्न 3

1) कुछ आदिवासी शिकार और भोजन एकत्र करने पर रह रहे थे, लेकिन बहुसंख्यक लोग कृषक और खेतिहर मजदूर थे। कई लोग घरेलू उद्योग, खनन कार्य, वृक्षारोपण आदि में लगे हुए थे।

2) स्वतंत्र भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाओं ने उन आदिवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिनके वन ऋणों पर प्रथागत अधिकार उन्हें वंचित और उनके पर्यावरण से वंचित और विस्थापित कर दिया गया था। वे या तो मजदूरों/नाबालिगों /अधिवासियों आदि के रूप में काम कर रहे थे या शहरों और अन्य क्षेत्रों में प्रवास के लिए मजबूर थे जो आजीविका के स्रोत की तलाश कर रहे थे।

इकाई 7 गांव, कस्बा और नगर

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 गांव और इसकी विशेषताएं

- 7.2.1 ग्राम स्वायत्तता का मुद्दा
- 7.2.2 गांव और उसकी सामाजिक संरचना
- 7.2.3 जजमानी व्यवस्था
- 7.2.4 ग्राम शक्ति संरचना और नेतृत्व में परिवर्तन

7.3 ग्राम एवं वृहद राजनितिक व्यवस्था

- 7.3.1 पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव
- 7.3.2 ब्रिटिश भारत में गाँव
- 7.3.3 समकालीन भारत में गाँव

7.4 भारत में कस्बे और नगरः नगरीकरण के स्वरूप

- 7.4.1 एक नगर या नगर की परिभाषा
- 7.4.2 जनसांख्यिकी पहलू
- 7.4.3 स्थानिक स्वरूप

7.5 कस्बों और नगरों का विकास

- 7.5.1 प्रवास
- 7.5.2 सामाजिक-सांस्कृतिक चरित्र

7.6 नगरीकरण की वर्तमान प्रक्रिया के संबंध में समस्याएं

7.7 सारांश

7.8 संदर्भ

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस इकाई से गुजरने के बाद, आप निम्न कार्य कर पाएंगेः

- भारत में गाँव की विशेषताओं का वर्णन;
- गाँव की सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं;
- नगरीकरण और नगरी क्षेत्रों की प्रक्रिया को परिभाषित करना;
- कस्बों की विशेषता पर चर्चा;
- नगरों की विशेषताओं को रेखांकित करना और अंत में;
- कस्बों और नगरों की सामाजिक संरचना की विशेषताएं बताना।

7.1 प्रस्तावना

आपने भारत में जनजातियों की विशिष्ट विशेषता के बारे में सीखा था। हमने भारत में आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और बदलती आजीविका का वर्णन किया। यहां, इस इकाई, इकाई-07 गांव, कस्बा और नगर में, हम गाँव के विभिन्न पहलुओं यानि ग्रामीण समाज और कस्बों और नगरों की व्याख्या करेंगे जो भारतीय समाज के नगरी सामाजिक ढांचे का हिस्सा हैं।

गाँव, कस्बा और नगर मानव बस्तियों की श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। बहुत बार गाँव के लोग नई आजीविका और व्यवसायों की तलाश में नगरों और नगरों की ओर पलायन करते हैं। ग्रामीण अपने कृषि उत्पादों को पास के कस्बों और नगरों में बेचते हैं और आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं, जिन्हें वे खुद नहीं उगा सकते हैं और न ही पैदा कर सकते हैं। वे कई वस्तुओं और सेवाओं के लिए कस्बों और नगरों पर निर्भर हैं। नगरवासी सब्जियों, खाद्यान्नों, दूध, मानव श्रम आदि जैसे खाद्य उत्पादों के लिए गाँवों पर निर्भर हैं। यहाँ उल्लेख करने वाली बात यह है कि मानव बंदोबस्त की श्रेणियां गांव और नगर पर कच्चे माल के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं और नगर अन्य सुसज्जित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें उच्च प्रौद्योगिकी और अधिक संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए, वे सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं लेकिन कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। इस इकाई में हम मानव बस्तियों की इन तीन श्रेणियों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगेरू गाँव, नगर और कस्बा। इससे छात्रों को इन श्रेणियों की स्पष्ट समझ हो सकेगी।

7.2 गांव और उसकी विशेषताएं

भारत एक ऐसा देश है जहाँ अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 640,887 गांव हैं। इनमें से ज्यादातर गांवों में 1000 से कम निवासी हैं। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हाल के समय में भी, 31 प्रतिशत नगरी निवासियों की तुलना में 69 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में रहते हैं। इसलिए, हम कह सकते हैं कि भारत गांवों का देश है। जैसा कि गाँव ग्रामीण समाज की मूल इकाई है और भारतीय आबादी का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, भारतीय समाज की बेहतर समझ रखने के लिए आपको भारतीय गाँवों की मूल विशेषताओं, उनके विकास, उनकी प्रकृति और संरचना, संस्कृति और ग्रामीण जीवन पद्धति की व्याख्या करना अनिवार्य है।

7.2.1 ग्राम स्वायत्तता का मुद्दा

भारत में औपनिवेशिक शासन के शुरुआती दौर में हेनरी मेन (1881), चार्ल्स मेटकाफ (1833) और बाडेन-पॉवेल (1896) के अध्ययनों ने ग्राम स्वायत्तता की एक अतिरंजित धारणा दी। भारतीय गांव को 'बंद' और 'पृथक' प्रणाली के रूप में चित्रित किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड की प्रवर समिति की एक रिपोर्ट में, भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक चार्ल्स मेटकाफ (1833) ने भारतीय गांव को एक अखंड, एकाकी और अपरिवर्तनीय इकाई के रूप में चित्रित किया। उन्होंने कहा, 'गाँव के समुदाय थोड़े गणतंत्रीय हैं, उनके पास लगभग हर चीज जो वे अपने भीतर चाहते हैं और लगभग किसी भी विदेशी संबंधों से स्वतंत्र हैं'। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि युद्ध इस पर गुजरते हैं, शासन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक समाज के रूप में गाँव हमेशा स्थिर, अपरिवर्तित और आत्मनिर्भर 'रहा है।

हाल के ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय गाँव शायद ही कभी गणतंत्र था। यह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं था। इसका व्यापक समाज के साथ संबंध है, गाँव की पलायन, कार्य और व्यापार के लिए आंदोलन, प्रशासनिक संबंध, अंतर्राज्यीय बाजार, अंतर-ग्रामीय आर्थिक और जाति संबंध और धार्मिक यात्रा अतीत में प्रचलित थे, जो गाँव को पड़ोसी गाँवों और व्यापक से जोड़ते समाज थे । इसके अलावा, आधुनिक काल में आधुनिकीकरण की नई ताकतों ने अंतर-गाँव और ग्रामीण-नगरी सहभागिता को बढ़ाया है।

लेकिन बाहरी संपर्क बढ़ने के बावजूद गाँव अभी भी एक बुनियादी सामाजिक इकाई हैं (मैंडेलबाउम 1972, ओरेनस्टीन 1965)। एक गाँव में रहने वाले लोगों में आम पहचान की भावना होती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिक्षेत्र में पारिवारिक, जाति और वर्ग के स्तर पर उनके पास अंतरा -ग्रामीण संबंध हैं। वास्तव में, ग्राम जीवन पारस्परिकता, सहयोग, प्रभुत्व और प्रतिस्पर्धा की विशेषता है।

भारत प्राचीन सभ्यता का एक देश है जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखा जाता है, जो तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. तब से जब ऋग-वैदिक काल (लगभग 1500-1000 ई.पू.) के दौरान एक छोटे से अंतराल को छोड़कर जब नगरी केंद्रों को खत्म कर दिया गया था, भारत में ग्रामीण और नगरी केंद्रों का सह-अस्तित्व था। ग्रामीण और नगरी केंद्र जीवन के कुछ सामान्य पहलुओं को साझा करते हैं। वे विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, नगरी प्रवास, और कस्बों या नगरवासियों या विभिन्न उत्पादों (जैसे खाद्यान्न, दूध, सब्जियां, उद्योग के लिए कच्चे माल) के लिए गांवों पर निर्भरता और विनिर्मित वस्तुओं और बाजार के लिए कस्बों के ग्रामीणों की बढ़ती निर्भरता पर निर्भर करते हैं। । दोनों के बीच इस अंतर-निर्भरता के बावजूद कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें उनके आकार, जनसांख्यिकीय संरचना, सांस्कृतिक जीवन, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक संबंधों के संदर्भ में एक-दूसरे से अलग करती हैं। (इग्नू: 191 19: ईएसओ -12 इकाई: 2 ग्रामीण सामाजिक संरचना, पृष्ठ 35)

7.2.2 गाँव और इसकी सामाजिक संरचना

परिवार लगभग सभी समाजों की मूल इकाई है। यह भारत में विशेष रूप से सच है जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसकी और उसके परिवार की स्थिति और सामाजिक स्थिति पर निर्भर है।

ग्रामीण भारत में परिवार

परिवार सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो ग्रामीण समाज का गठन करती है। यह जरूरतों को पूरा करता है और कार्य करता है, जो सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता, एकीकरण और परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि, प्रजनन, उत्पादन और समाजीकरण।

मोटे तौर पर दो प्रकार के परिवार हैं : (i) एकाकी परिवार जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं, और (ii) संयुक्त या विस्तारित परिवार में एकाकी प्रकार की तुलना में कुछ अधिक परिजन शामिल हैं। परिवार संयुक्तता 'के महत्वपूर्ण आयाम हैं साथ -साथ रहना, संयुक्त सम्पत्ति, सहभोजन, पीढ़ीगत जुड़ाव (तीन पीढ़ी तक), और परिजनों और भावुक पहलू के प्रति दायित्व की पूर्ति। साथ-साथ रहना का मतलब है कि एक परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। सहभोजन का तात्पर्य है कि वे एक साथ भोजन करते हैं यानी, एक सामान्य रसोईघर है। संयुक्त सम्पत्ति का मतलब है कि उनके पास संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है। इसके अलावा, पीढ़ी की गहराई में तीन पीढ़ियों या अधि

ाक, यानी दादा, पिता और पुत्र या अधिक शामिल हैं। परिवार के सदस्यों के भी अपने परिजनों के प्रति दायित्व होते हैं। इसके अलावा, उन्हें संयुक्त परिवार के आदर्श के लिए एक भावुक लगाव है।

ग्रामीण परिवार आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों की इकाई के रूप में काम करता है। सामाजिक जीवन में परिवार की सामूहिकता पर जोर दिया जाता है, और व्यक्तिगत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावनाएं बहुत सीमित हैं। विवाह को एक अंतर-व्यक्तिगत मामले के बजाय एक अंतर-पारिवारिक मामला माना जाता है। यह रिश्तेदारी के नियमों द्वारा शासित है।

इसे ग्राम बहिर्मुखी और उत्तर में 'गोत्र बहिर्मुखी' के नियमों के प्रसार में देखा जाता है, लेकिन दक्षिण में नहीं। उत्तर में, किसी को अपने गाँव में विवाह करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह के जाति के अन्य गांवों के लोगों के साथ विवाह गठबंधन संपन्न होता है। लेकिन दक्षिण में ऐसा कोई भी प्रतिबंध मौजूद नहीं है। इसके अलावा, उत्तर में वह अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता। इसके विपरीत, क्रॉस कजिन मैरिज यानी भाई और बहन के बच्चों के बीच शादी, दक्षिण में पसंद की जाती है। इस प्रकार, उत्तर भारत में एक केन्द्रापसारिक प्रवृत्ति है, अर्थात, शादी की दिशा समूह से बाहर या दूर है। दक्षिण भारत में इसके विपरीत हम विवाह गठजोड़ बनाने और रिश्तेदारी संबंध बनाने में एक केंद्रित प्रवृत्ति पाते हैं। दूसरे शब्दों में, विवाह समूह के भीतर या भीतर होते हैं। (इग्नू: 201 2017: पृष्ठ 26 -2) गाँव की सामाजिक संरचना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता जजमानी प्रणाली थी।

आपने इस खंड में इकाई 5 जाति में गाँव की इस संस्था के बारे में समझ लिया है । अगले भाग में हम इस सामाजिक संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं।

7.2.3 जजमानी व्यवस्था

भारत में पारंपरिक गाँव के जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता पारम्परिक 'जजमानी प्रणाली' है। इसका अध्ययन विभिन्न समाजशास्त्रियों, अर्थात, विलियन वाइजर (1936), एस. सी. दूबे (1955), ओप्लर और सिंह (1986), के. ईश्वरन (1967), लुईस और बार्नव्यू (1956) ने किया है। ''जाजमन'' शब्द विशेष सेवाओं के संरक्षक या प्राप्तकर्ता को संदर्भित करता है और ''जजमानी'' शब्द पूरे संबंध को संदर्भित करता है। वास्तव में, जजमानी प्रणाली एक गांव में विभिन्न जाति समूहों के बीच आर्थिक, सामाजिक और अनुष्ठान संबंधों की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत कुछ जातियां संरक्षक हैं और अन्य जातियां हैं। सेवारत जातियाँ जमींदार ऊपरी और मध्यवर्ती जाति को अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं और बदले में उन्हें नकद और तरह दोनों तरह से भुगतान किया जाता है। संरक्षक जातियाँ भूमि पर हावी होने वाली जातियाँ हैं, जैसे, उत्तर में राजपूत, भूमिहार, जाट और आंध्र प्रदेश में कम्मा, लिंगायत और रेड्डी और गुजरात में पटेल। सेवा जातियों में ब्राह्मण (पुजारी), नाई, बढ़ई, लोहार, जल-वाहक, चमड़े के काम करने वाले आदि शामिल हैं।

जजमानी संबंध अनिवार्य रूप से पारिवारिक स्तर पर संचालित होते हैं (मंडेलबाम 1972)। राजपूत भूमि के मालिक परिवार में ब्राह्मण, नाई, बढ़ई आदि के एक-एक परिवार के साथ अपने जजमानी संबंध होते हैं, और सेवा जाति का एक परिवार जाजमनों के विशिष्ट परिवारों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। हालांकि, जजमानी नियम जाति पंचायतों द्वारा लागू किए जाते हैं।

जजमानी संबंध माना जाता है और अक्सर टिकाऊ, अनन्य और एकाधिक होता है। जजमानी संबन्ध को दोनों ओर अर्थात् संरक्षक और ग्राहक (जजमान और कामिन) विरासत

में मिला है। रिश्ता विशिष्ट परिवारों के बीच होता है। इसके अलावा, यह सेवा के बदले अनाज और धन के आदान-प्रदान से अधिक है। शादी, जन्म और मृत्यु जैसे विभिन्न अनुष्ठानों के अवसर पर, सेवा-जातियां अपने जजमान को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं और प्रथागत भुगतान के अलावा उपहार प्राप्त करती हैं। गुटीय प्रतियोगिताओं में प्रत्येक पक्ष अपने जजमानी सहयोगियों के समर्थन को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए जजमानी प्रणाली में गांवों में जाति और परिवारों के बीच परस्पर निर्भरता, पारस्परिकता और सहयोग शामिल है।

लेकिन जजमानी प्रणाली में प्रभुत्व, शोषण और संघर्ष (बीडेलमैन 1959 और लुईस और बार्नव्यू 1956) के तत्व भी हैं। जमींदार प्रमुख संरक्षकों और गरीब कारीगरों और उनकी सेवा करने वाले भूमिहीन मजदूरों के बीच शक्ति के व्यायाम में बहुत अंतर है। अमीर और शक्तिशाली जजमान अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए गरीबों के कामिन (ग्राहक) का शोषण करते हैं और उनका शोषण करते हैं। वास्तव में, जैजमनी प्रणाली में पारस्परिकता के साथ-साथ वर्चस्व भी है।

इसके अलावा, यह विशेष रूप से 1947 में आजादी के बाद देखा गया है, बाजार की ताकतों, नगरी संपर्क, प्रवास, शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के कारण सेवा जातियों की ओर से जजमानी प्रणाली वर्षों से कमजोर हुई है।

7.2.4 ग्राम शक्ति संरचना और नेतृत्व में परिवर्तन

विभिन्न कारकों के कारण जैसे भूमि सुधार, पंचायती राज, संसदीय राजनीति, विकास कार्यक्रम और कृषि आंदोलन के कारण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद गांवों में शक्ति की संरचना और नेतृत्व में सीमांत परिवर्तन हुए हैं जिनकी प्रकृति सामंजस्यपूर्ण रही है । सिंह (1986) के अनुसार, उच्च जातियां अब अपने अधिकार की पारंपरिक वैधता से नहीं, बल्कि निचली जातियों के लोगों के साथ जोड़-तोड़ और सहयोग के जरिए सत्ता का इस्तेमाल करती हैं। पारंपरिक शक्ति संरचना नहीं बदली है। नए अवसर कम शक्तिशाली वर्ग को शक्ति की आकांक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन उनका आर्थिक पिछड़ापन उनकी इच्छाओं को विफल करता है। बी.एस. कोहन (1962), और सिंह आर. (1988) ने भारत के बारह गांवों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में, भूमि-स्वामित्व और समूहों के वर्चस्व के स्तर के करीब पाया। अब युवा और साक्षर लोग तेजी से नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना में बदलाव के स्वरूप में कुछ क्षेत्रीय बदलाव भी देखे गए हैं।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही उत्तर पर टिक मार्क करें।

क) भारत में ग्राम स्वायत्तता 'की अवधारणा किसने प्रचलित की?

i) लॉर्ड वेलेजली

ii) चार्ल्स मेटकाफ

iii) विलियम बेंटिक

iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

ख) निम्नलिखित में से ग्रामीण भारत के महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थानों की पहचान करना।

i) परिवार

ii) जाति

iii) गांव

iv) ये सभी

ग) भारत में परिवार संयुक्तता की विशेषता है :

i) संदायादता

ii) साथ-साथ रहना

iii) सहभोजन

iv) ये सभी

घ) ग्रामीण भारत में जाति की पारंपरिक सांस्कृतिक विशेषताओं में मूल-भूत परिवर्तन हुआ है

1) वैवाहिक आयाम

2) सहभोजी आयाम

3) अनुष्ठान आयाम

4) इनमें से कोई नहीं

ii) लगभग सात लाइनों में जजमानी प्रणाली का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

7.3 गांव और वृहद राजनितिक व्यवस्था

भारतीय गांवों को उन्नीसवीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्व-शासन के अपने सरल रूप के साथ 'छोटे गणतंत्र' के रूप में वर्णित किया गया था, और भूमि के उत्पादन में हिस्सेदारी का दावा करने और युद्धों में सेवा करने के लिए युवा पुरुषों की मांग को छोड़कर उच्च राजनीतिक प्राधिकरण का लगभग कोई हस्तक्षेप नहीं था। गाँव सामान्य रूप से कार्य करते थे, इस बात से असंबद्ध थे जिसका वे भाग थे उन राज्यों में कौन सिंहासन पर बैठा हुआ है । उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के रूप में भी वर्णित किया गया था, जो लगभग हर चीज को अपने भीतर चाहते थे। भारतीय गाँवों का यह वर्णन अति-सरलीकृत है। फिर भी इसने कार्ल मार्क्स और हेनरी मेन जैसे महत्वपूर्ण विद्वानों और महात्मा गांधी जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों के विचारों को प्रभावित किया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही कुछ सामाजिक मानवविज्ञानी, जिन्होंने भारतीय गाँवों का गहन अध्ययन किया, भारतीय गाँव के पारंपरिक विवरण पर सवाल उठाने लगे। अपने निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने प्रदर्शित किया कि भारतीय गाँव व्यापक समाज और सभ्यता का हिस्सा रहा है न

कि श्छोटे गणराज्योंश का, जैसा कि ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा वर्णित है।

7.3.1 पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव

यह कहना कि पूर्व-ब्रिटिश भारत में (अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन के सुदृढ़करण से ठीक पहले की अवधि) सिवाय स्थानीय सरदार या राजा को कर चुकाने के और उसे अपने युद्धों के लिए जवान मुहैया कराने के लिए गाँव राजनीतिक रूप से स्वायत्त था। राजा और उसकी प्रजा के बीच का एक संबंध जटिल था। राजा ने अपनी प्रजा के प्रति कई कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने सिंचाई के लिए सड़कें, टैंक और नहरों का निर्माण किया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण भी किया और भूमि को ब्राह्मणों को और धार्मिक कार्य के लिए उपहार में दिया। वह सभी जाति पंचायतों के प्रमुख थे और आपसी जाति श्रेणियों के बारे में विवादों का अंत उनके द्वारा किया गया था। यह समारोह हिंदू शासकों तक ही सीमित नहीं था, यहां तक कि मुगल राजाओं और सामंतों ने जाति को प्रभावित करने वाले सवालों का निपटारा किया।

पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव उनके राज्य के संबंध में निष्क्रिय नहीं थे (ज्यादातर रियासतें, जिन्हें देश भी कहा जाता है)। वे निश्चित रूप से इस बात से चिंतित थे कि सिंहासन पर कौन बैठा है। वे एक ऐसे राजा को पसंद करेंगे जो उन्हें ठग और दंगाई सैनिकों से बचाएगा। यदि राजा या प्रमुख स्थानीय रूप से प्रभावी जाति के होते हैं, तो उनकी जाति के साथी संकट में उनकी सहायता के लिए आते थे ।

शासकों के साथ उनके संबंध में गाँव असहाय नहीं थे। ग्रामीण विद्रोह कर सकते थे और सिंहासन के लिए एक प्रतिद्वंद्वी का समर्थन कर सकते थे। ग्रामीणों के लिए अपने दमन के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष एक और तरीका था। ऐसी सामूहिक संघर्ष होने पर शासक बहुत बार हारे थे। चूंकि भूमि बंदोबस्त के लिए उपलब्ध थी, जबकि श्रम दुर्लभ था एक शासक को इस दशा में जोत भूमि प्राप्त करना मुश्किल होगा और राजस्व का नुकसान होगा।

इस प्रकार गाँव और शासक के बीच का संबंध एक जटिल था और पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव को एक ष्छोटे गणराज्यष के रूप में वर्णित करना गलत है। हालाँकि इस बात पर ध यान दिया जाना चाहिए कि सड़कों की अनुपस्थिति और खराब संचार के कारण, गाँव ने स्वायत्तता के साथ-साथ राजनीतिक व्यवस्था के उच्च स्तर से कम नियंत्रण का भी भरपूर आनंद उठाया। राजाओं ने ग्रामीणों को दिन-प्रतिदिन के मामलों में खुद को नियंत्रित करने दिया।

ग्राम पंचायत ने मुख्य रूप से प्रमुख जाति का गठन किया जो स्थानीय मामलों में अधिकार का इस्तेमाल करती थी, अंतर-जातीय विवादों को सुलझाती थी और गाँव में कानून व्यवस्था बनाए रखती थी।

7.3.2 ब्रिटिश भारत में गाँव

ब्रिटिश शासन ने गाँव और शासक के बीच के संबंध को बदल दिया। संचार के विकास के बाद राजनीतिक विजय हुई। इसने अंग्रेजों को एक प्रभावी प्रशासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। पुलिस, राजस्व अधिकारी और अन्य जैसे सरकारी कर्मचारी गाँव में आए। अंग्रेजों ने कानून अदालतों की एक प्रणाली स्थापित की। प्रमुख विवादों और आपराधिक अपराधों को अदालत में निपटाना पड़ा। इससे ग्राम पंचायत की शक्ति बहुत कम हो गई।

7.3.3 समकालीन भारत में गाँव

आजादी के बाद से, संसदीय लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार की शुरुआत ने गाँव को व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के साथ और भी अधिक एकीकृत बना दिया है। ग्रामीण न केवल ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के सदस्यों का चुनाव करते हैं, बल्कि राज्य विधानसभा और संसद के सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल गांव में सक्रिय हैं और अपनी पार्टियों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम जैसे सामुदायिक विकास योजनाएं गांव को प्रभावित करती हैं।

हालाँकि गाँव एक राजनीतिक पंचायत है जो दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने के लिए निर्वाचित पंचायत है, यह जिला या जिला का हिस्सा है, जो राज्य का हिस्सा है। राज्य भारतीय संघ का हिस्सा है। राजनीतिक प्रणाली के इन विभिन्न स्तरों के बीच परस्पर अंतः - क्रिया है। (इग्नू: 1919, ईएसओ-12 पृष्ठ 51-53)

बोध प्रश्न 2

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव को लिटल रिपब्लीक लघु गणतंत्र क्यों कहा गया था? अपने उत्तर के लिए लगभग चार पंक्तियों का उपयोग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) बताएं कि गाँव एक ''लघु गणतंत्र'' है, यह एक सरलीकृत कथन था। अपने उत्तर के लिए लगभग छह पंक्तियों का उपयोग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

7.4 भारत में कस्बे एवं नगर : नगरीकरण के बदलते स्वरूप

भारत बीसवीं शताब्दी में तेजी से नगरीकरण के दौर से गुजरा। आधुनिक नगरी केंद्र विविध आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य करते हैं। यहाँ, किसी एक गतिविधि के मामले में कस्बों और नगरों को वर्गीकृत करना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर, लोग कुछ प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं के आधार पर नगरी क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, लोग उल्लेख करते हैं कि दिल्ली, कोलकाता,

वाराणसी, लखनऊ आदि जैसे ऐतिहासिक नगर हैं, औद्योगिक नगर जैसे गाजियाबाद, मोदीनगर, कानपुर, जमशेदपुर, भिलाई आदि, धार्मिक नगर जैसे मथुरा, हरद्वार, मदुरै, इलाहाबाद आदि प्रतिश्ठित नगर हैं। फिल्म बनाने के लिए, मुंबई और चेन्नई नगर , एक ग्रामीण या एक छोटे नगर के निवासी के लिए एक विशेष आकर्षण की तरह है। समाजशास्त्र में, हम इसके जनसांख्यिकीय, स्थानिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में नगरीकरण के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन पहलुओं को उठायें, हमें यह भी संक्षेप में समझते हैं कि हम भारतीय संदर्भ में एक नगर को कैसे परिभाषित करते हैं।

7.4.1 एक नगर या नगर की परिभाषा

भारत में, जनसांख्यिकी और आर्थिक सूचकांक विशिष्ट क्षेत्रों को नगर या नगर के रूप में परिभाषित करने में महत्वपूर्ण हैं। भारत में एक नगरी क्षेत्र के निश्चित मापदंडों ने वर्षों में कई बदलाव और संशोधन किए हैं। 1901 की जनगणना में अपनाई गई नगर की निम्नलिखित परिभाषा का 1961 तक उपयोग किया गया था।

क) प्रत्येक नगरपालिका, छावनी और सभी सिविल लाइन्स (एक नगर पालिका में शामिल नहीं), और

बी) स्थायी रूप से 5,000 से कम व्यक्तियों द्वारा बसाए गए घरों का हर दूसरा निरंतर संग्रह, जिसे जनगणना के प्रांतीय अधीक्षक एक नगर के रूप में मान सकते हैं।

किसी भी क्षेत्र या निपटान को नगरी के रूप में वर्णित करने का मुख्य मानदंड उसका प्रशासनिक ढांचा और आकार था न कि आर्थिक विशेषताएं। इस परिभाषा के परिणामस्वरूप कई कस्बों को वास्तव में केवल अधिक आबादी वाले गांवों के रूप में माना जाता था।

1961 में 'नगरी क्षेत्र' को अन्य प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय सुविधाओं के अलावा आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्परिभाषित किया गया था। 1961 की जनगणना में अपनाई गई परिभाषा का उपयोग 1971 और 1981 में भी किया गया था। और यह 1991 और 2001 में भी अपरिवर्तित रही। इस परिभाषा के अनुसार एक नगरी क्षेत्र हैः

क) एक जगह जो या तो एक नगर निगम या एक नगर निगम क्षेत्र है, या एक नगर समिति या एक अधिसूचित क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड के तहत,

ख) कोई भी स्थान जो निम्न मानदंडों को पूरा करता हैः

- न्यूनतम 5,000 व्यक्ति
- कम से कम 75 प्रतिशत पुरुष कामकाजी आबादी व्यवसायों में होनी चाहिए जो गैर-कृषि है,
- प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति से कम का घनत्व नहीं है, और
- एक जगह पर कुछ स्पष्ट नगरी विशेषताओं और सुविधाएं होनी चाहिए जैसे कि नए पाए गए औद्योगिक क्षेत्र, बड़ी आवासीय बस्तियां, पर्यटन महत्व के स्थान और नागरिक सुविधाएं।

1961 और 1971 के बाद से इस परिभाषा में एक मामूली बदलाव हुआ है। 1991 और 1981 के बाद वानिकी, मछली पकड़ने, पशुधन, शिकार, प्रवेश, वृक्षारोपण और बागों आदि के व्यवसाय में श्रमिकों, जिन्हें पहले औद्योगिक गतिविधि के रूप में माना जाता था। 1981 और 1991 में कृषि गतिविधि के रूप में मान्यता प्राप्त कृषि व्यवसाय के रूप में गिना गया।

अच्छी तरह से परिभाषित कस्बों और/या नगरों के अलावा, नगरों और अधिक बढ़ी हुई आबादी को भी नगरी समूहों के रूप में माना गया है। 1961 की जनगणना में, 'टाउन ग्रुप' की अवधारणा को नगरी प्रसार से संबंधित एक व्यापक चित्र प्राप्त करने के लिए अपनाया गया था। यह 1971 में नगरी निरंतरता, प्रक्रिया और नगरीकरण और अन्य संबंधित मामलों के रुझानों के संबंध में बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए नगरी समुदाय की अवधारणा के साथ परिष्कृत किया गया था। बिना किसी बदलाव या संशोधन के यह अवधारणा 2001 की जनगणना तक संचालित रही।

जो एक नगरी समूह एक निरंतर नगरी प्रसार बनाता है और आम तौर पर एक कस्बे और उसके आस-पास के नगरी वृद्धि या दो या अधिक भौतिक रूप से सन्निहित नगरों के साथ-साथ सन्निहित और अच्छी तरह से संगठित वृद्धि होते हैं, (जनगणना रिपोर्ट 2001)

नगरी स्थानों का वर्णन करते हुए, भारतीय जनगणना रिकॉर्ड में नगरी क्षेत्र को छह वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए जनसंख्या के आकार को लगातार नियोजित करती है जैसा कि तालिका 7.1 में दिखाया गया है।

तालिका 7.1: नगरों का वर्गीकरण

वर्ग स के साथ	1,00,000	और अधिक		जनसंख्या
वर्ग I के साथ	50,000	से	99,999	जनसंख्या
वर्ग II के साथ	20,000	...	49,999	जनसंख्या
वर्ग III के साथ	10,000	...	19,999	जनसंख्या
वर्ग IV के साथ	5,000	...	9,000	जनसंख्या
वर्ग V के साथस	...	5,000 से कम		जनसंख्या

1,00,000 से कम आबादी वाले नगरी स्थानों को 'कस्बों' के रूप में जाना जाता है, जबकि 1,00,000 या अधिक आबादी वाले नगरी स्थानों को 'नगरों' के रूप में जाना जाता है। दस लाख से अधिक आबादी वाले नगरी केंद्रों को महानगरीय नगरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महानगरीय केंद्र बड़े पैमाने पर खपत, और लोगों, सामानों, सेवाओं और सूचनाओं की आमद की बड़ी मात्रा के आधार पर स्वयं में एक वर्ग हैं (प्रकाश राव 1982: 17)। यह वर्णन करने के बाद कि भारत में नगरी क्षेत्र को कस्बों/नगरों की विभिन्न श्रेणियों में कैसे वर्गीकृत किया जाता है, अब हम भारत में नगरीकरण के पैटर्न के कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं।

गतिविधि 1

आप जिस गांव, कस्बे/नगर में रहते हैं, उसकी जनसांख्यिकीय आबादी की पहचान करें और यह पहचानें कि वह किस वर्ग के आकार का है और उसके बुनियादी ढांचे पर एक पृष्ठ की एक रिपोर्ट लिखता है, साथ ही साथ अन्य आवश्यक विशेषताएँ जो आप इसे सोचते हैं और जिसकी जरूरत है। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ चर्चा करें।

7.4.2 जनसांख्यिकी पहलू

भारत में, जनसंख्या एकाग्रता नगरीकरण की प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। नगरी जनसंख्या का प्रतिशत 1901 में 10.8 प्रतिशत से 1981 में दोगुना से थोड़ा अधिक हो गया है। और यह 2001 तक लगभग तीन गुना हो गया है, जब यह 27.8 प्रतिशत दर्ज किया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरी आबादी 217,177,625 है और यह कुल आबादी का 25.72 प्रतिशत है। अब तक देश की नगरी आबादी का संबंध है, 1901 में केवल 25.85 मिलियन कस्बों में रहते थे और 1991 तक यह 8 गुना बढ़कर 217.18 मिलियन हो गई। 1 मार्च 2001 को 1027 मिलियन की कुल आबादी में से, 285 मिलियन नगरी क्षेत्रों में रहते थे। नगरी क्षेत्रों में 1991-2001 के दौरान जनसंख्या का शुद्ध जोड़ 68 मिलियन के बराबर रहा, जहां दशक 1981-1991 के दौरान यह 61 मिलियन था।

स्वतंत्रता काल के बाद नगरी आबादी में काफी वृद्धि हुई है। 1901 से 1941 तक की चालीस वर्षों की अवधि के लिए नगरी आबादी में 25.85 से 44.15 मिलियन की वृद्धि अगले दशक के 62.44 मिलियन की तुलना में काफी मामूली रही है। 1941 से 1981 तक नगरी आबादी में 115.05 मिलियन की वृद्धि हुई है। ध्यान दें कि इस जनसंख्या का 64.8 प्रतिशत 1961 से 1981 के बीच दो दशकों में बढ़ा है। इसी तरह नगरी आबादी लगभग 1971 (109.11 मिलियन) में दोगुनी हो गई है। 1991 (217.18 मिलियन)।

शुरुआती दशकों (1901-21) में नगरी लोगों की कुल आबादी के अनुपात में धीमी वृद्धि (और 1911 में भी गिरावट) थी। यह ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक और आर्थिक विकास की धीमी दर के कारण है। 1941-51 के दौरान नगरी आबादी का तेजी से विकास ज्यादातर देश के विभाजन और अन्य राजनीतिक कारणों से हुआ है, जिसके कारण नगरी क्षेत्रों में शरणार्थी प्रवासन हुआ। 1981 से पहले के दशकों में नगरी आबादी में लगातार वृद्धि नियोजित आर्थिक विकास और औद्योगीकरण के कारण नहीं हुई, बल्कि असंतुलित कृषि विकास के कारण हुई। 1981-19991 के दौरान 1971-1981 के दौरान नगरी आबादी की वार्षिक वृद्धि दर 3.83 प्रतिशत से घटकर 3.09 प्रतिशत हो गई। दशक 1971-1981 के दौरान नगरीकरण के स्तर में 3.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1981-1991 दशक के दौरान वृद्धि केवल 2.38 प्रतिशत रही है। 1991-2001 के दौरान नगरीकरण में वृद्धि और घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई। परिणामस्वरूप, नगरी जनसंख्या के प्रतिशत में लाभ की वार्षिक दर भी 1981-1991 के दशक के दौरान 1.72 से घटकर 1.02 हो गई है। यह दर्शाता है कि भारत में 1981 से नगरीकरण की गति धीमी हो गई है। (IGNOU, 2017 (पुनर्मुद्रित) BDP, ESO-12, Block-1, पृष्ठ 10)

नगरीकरण की दर में धीमी वृद्धि, हालाँकि, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर तेजी से बढ़ी। उच्च आर्थिक विकास और अन्य कारकों के कारणय नगरी क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या 377 मिलियन या 31.1 प्रतिशत हो गई। (भगत, आर.बी. 2011)

7.4.3 स्थानिक स्वरूप

स्थानिक असमानताओं ने भारतीय नगरी परिदृश्य को चिह्नित किया है। ये असमानताएं मुख्य रूप से क्षेत्रीय असमानताओं, असंतुलित जनसंख्या एकाग्रता और कुछ समय के कारण 'नगरी क्षेत्रों' की जनगणना परिभाषा में बदलाव के कारण उभरी हैं। इस संदर्भ में हमें दो अवधारणाओं के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता है, अर्थात् अति-नगरीकरण और उप-नगरीकरण।

i) **अति नगरीकरण**

कस्बों या नगरी क्षेत्रों में आबादी को समायोजित करने की कुछ सीमाएँ हैं, स्कूली शिक्षा, अस्पताल आदि जैसी आवश्यकताओं के लिए नागरिक सुविधाएं या खानपान प्रदान करना, कुछ विशिष्ट क्षमताओं से परे, बढ़ती जनसंख्या के लिए सुविधाएं प्रदान करना नगर प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता है। मुंबई और कोलकाता नगरों के दो ऐसे उदाहरण हैं जिनकी प्रबंधन करने की क्षमता से परे नगरी-जनसंख्या वृद्धि है। यह सुविधा अति नगरीकरण के रूप में संदर्भित है।

ii) **उप-नगरीकरण**

किसी नगर के अति-नगरीकरण के साथ निकटता से संबंधित एक विशेषता है जिसे उप-नगरीकरण कहा जाता है। जब नगर आबादी से अधिक भीड़ वाले हो जाते हैं, तो इसका परिणाम उप-नगरीकरण हो सकता है। दिल्ली एक विशिष्ट उदाहरण है (दूसरों के बीच) जहां इसके चारों ओर उप-नगरीकरण की प्रवृत्ति हो रही है। उप-नगरीकरण का अर्थ है निम्नलिखित विशेषताओं की विशेषता वाले नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीकरण :

क) भूमि के नगरी (गैर-कृषि) उपयोगों में तेज वृद्धि हुई है

बी) नगर के आसपास के क्षेत्रों को अपनी नगरपालिका सीमा के भीतर शामिल करना, और

ग) नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों के बीच सभी प्रकार के गहन संचार।

अब, हम भारत में नगरीकरण के पैटर्न में पाई जाने वाली स्थानिक असमानताओं में कुछ बदलावों को भी देख सकते हैं।

7.5 कस्बों और नगरों की वृद्धि

नगरी कस्बों के विकास ने भारत में एक दिशाहीन प्रगति नहीं दिखाई दी है । नगरी 'क्षेत्रों की जनगणना परिभाषा में भिन्नता के कारण नगरी केंद्रों की संख्या में गिरावट आई। 1901 में मौजूद कुल 1,914 कस्बों में से केवल 1,430 कस्बे 1961 तक बचे थे। 1901 में कस्बों की नई परिभाषा के कारण 1901 में लगभग 480 क्षेत्रों को कस्बों के रूप में माना जाने वाला नगरी क्षेत्र खो दिया। यह इस कारण से है कि कोई व्यक्ति 1961 में 3060 की तुलना में 1961 में 2700 कस्बों में कमी देख सकता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में 1951 में 227 नगर थे, जबकि 1981 में यह संख्या घटकर 201 हो गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी देखा गया। 1991 की जनगणना में 4 ,689 स्थानों की पहचान 1941 की जनगणना के अनुसार 4 ,029 के रूप में की गई थी। 1991 के 4,689 नगरों में से 2,996 के रूप में कई वैधानिक नगर थे और 1981 में क्रमशः 2,758 और 1,271 के मुकाबले 1,693 जनगणना या गैर-नगरपालिका नगर थे। अखिल भारतीय स्तर पर, 1981 की जनगणना के 4029 नगरों में से 93 अघोषित थे और 103 थे जिन्हें 1981-1991 के दौरान संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन की वैधानिक अधिसूचनाओं द्वारा कस्बों को अन्य नगरों के साथ पूरी तरह से मिला दिया गया था। 1991 के नगरी सीमा में 856 नए नगर जोड़े गए थे। अवर्गीकृत नगरों की अधिकतम संख्या पंजाब (21), कर्नाटक (19) और आंध्र प्रदेश (13) राज्यों से थी और 1991 की जनगणना में जोड़े गए वैधानिक नगरों की अधिकतम संख्या मध्य प्रदेश (91) से थी।

हालाँकि 2011 की जनगणना जिसने नगरी आबादी में 2001 में पूरे देश में 27.7% की वृद्धि और 2011 में 31.1% तक वृद्धि दर्ज कीय जो कि 3.3% प्रतिशत अंकों की वृद्धि है।

2011 की इस जनगणना के दौरान भी कई गांवों को कस्बों के रूप में मान्यता दी गई थी, वहां भारत में कस्बों की संख्या में वृद्धि हुई।

ii) राज्यों में नगरीकरण में परिवर्तन

भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नगरीकरण का स्वरूप राज्यों में नगरी प्रभुत्व की एक दिलचस्प विशेषता को दर्शाता है। भारत के कुल नगरी आबादी में पांच राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का कुल मिलाकर 56 प्रतिशत (1961 में) 55 प्रतिशत (1971 में) था। इसके विपरीत छह राज्यों ओडिशा (उड़ीसा), हरियाणा, असम (मेघालय सहित), जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में 5 प्रतिशत (1961 में) भारत की कुल नगरी आबादी का 5.5 प्रतिशत (1971 में) हिस्सा है। 1991 की जनगणना में 25.72 प्रतिशत के राष्ट्रीय जनसंख्या की तुलना में कुल जनसंख्या में नगरी आबादी का अधिक अनुपात वाले कुछ राज्य महाराष्ट्र (35. 73 प्रतिशत), गुजरात (34.40 प्रतिशत), तमिलनाडु (34.20 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (27.39 प्रतिशत) थे।)। 2001 की जनगणना के अनुसार, महाराष्ट्र (42.4 प्रतिशत) और गुजरात (37.4 प्रतिशत) के बाद तमिलनाडु (43.9 प्रतिशत) सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। नगरी आबादी का अनुपात बिहार में सबसे कम 10.5 प्रतिशत है, उसके बाद असम (12.7 प्रतिशत) और ओडिशा (14.9 प्रतिशत) है। हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत राज्य है। स्पष्ट है कि कुछ राज्यों में नगरी प्रभुत्व इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में भी जारी है।

1961 और 1971 के बीच भारतीय राज्यों के लिए नगरी घनत्व का प्रकार कुछ इसी तरह का रुझान दिखाता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम और केरल के राज्यों में 1961 में प्रति वर्ग किलोमीटर 2948 व्यक्तियों के अखिल भारतीय औसत से अधिक घनत्व है। 1971 में भी इसी तरह की प्रवृत्ति पाई गई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान राज्यों में 1961 में अखिल भारतीय औसत 2,048 से कम घनत्व था।1971 की जनगणना में 1961 में देखी गई उसी प्रवृत्ति को दर्षाया गया था, जो उपरोक्त राज्यों के संबंध में थी। गुजरात, मध्य प्रदेश और असम के लिए नगरी घनत्व 1961-71 दशक के दौरान संभवतः लोगों के बाहरी प्रवास के कारण कम हो गया । वर्ष 1991 में, पश्चिम बंगाल राज्य में नगरी घनत्व सबसे अधिक था, इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब थे। तमिलनाडु, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान राज्यों में 1991 के अखिल भारतीय औसत 3,370 से भी कम घनत्व था। इस प्रकार जब हम जनगणना के आंकड़ों को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि नगरी घनत्व के संदर्भ में वर्ष 1991 तक परिवर्तन लगभग अपरिवर्तित रहा।

iii) नगरों में जनसंख्या एकाग्रता

बड़े नगरी केंद्रों (1,00,000 या अधिक) के साथ जनसंख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। 1981 में भारत में 60 प्रतिशत से अधिक नगरी आबादी इस श्रेणी के नगरों में रहती थी। 1991 तक उनकी दर लगभग 65 प्रतिशत तक पहुंच गई। 1991 की जनगणना के अनुसार, 300 नगरों में जनसंख्या की कुल संख्या 1,00,000 से अधिक है। ये 300 नगरी समूह/नगर देश की नगरी आबादी का 64.89 प्रतिशत हैं। महाराष्ट्र और

पश्चिम बंगाल के मामले में नगरी आबादी में वर्ग स नगरी समूह/नगरों का हिस्सा क्रमशः 77.85 प्रतिशत और 81.71 प्रतिशत अधिक है। श्रेणी-स, नगरी समूह/नगर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मेघालय और तमिलनाडु राज्यों में नगरी आबादी का लगभग दो तिहाई योगदान करते हैं।

iv) महानगरीय नगरों का विकास

भारत में, कोलकाता 1901 में एक मिलियन से अधिक की आबादी वाला एकमात्र नगर था। 1911 तक मुंबई ने एक मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 1941 तक इस श्रेणी में केवल दो नगर थे, यानी, जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक थी। दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद ने 1951 तक इस श्रेणी में प्रवेश किया। अहमदाबाद और बैंगलोर ने 1961 तक, और कानपुर और पुणे ने 1971 तक। लखनऊ, नागपुर और जयपुर ने 1981 में एक मिलियन का आंकड़ा पार किया, जो कि 12 मिलियन से अधिक नगरों की संख्या को 12 तक ले आया। 1991 की जनगणना की गणना के समय 23 महानगरीय समूह/नगर थे जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक थी। दशक 1981-1991 के दौरान संख्या लगभग दोगुनी हो गई। 2001 की जनगणना के समय इसकी संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है। 1981 की जनगणना के समय कुल नगरी आबादी का 25 प्रतिशत मिलियन-प्लस नगरों में केंद्रित था। वर्ष 1991 तक यह 32.54 प्रतिशत हो गया। इसका मतलब है कि 1991 में इन नगरों का देश की नगरी आबादी का लगभग एक तिहाई और देश की कुल आबादी का बारहवां हिस्सा था।

1981 में दिल्ली को छोड़कर जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का हिस्सा है, शेष 11 नगर 8 राज्यों में स्थित हैं। 1991 में, 23 महानगरीय नगर भारत के 13 राज्यों में बिखरे हुए थे। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में उनकी एकाग्रता अधिक थी, प्रत्येक में 3 ऐसे महानगरीय नगर थे। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में दो और 7 बिहार, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच वितरित थे। कोलकाता में 1971-81 के दशक में नगरी आबादी की सांद्रता अन्य महानगरीय नगरों की तुलना में अधिक थी। इसके बाद बैंगलोर, चेन्नई और अहमदाबाद थे।

1981-1991 के दौरान 23 महानगरीय नगरों ने जनसंख्या के विकास के काफी विविध स्वरूप का प्रदर्शन किया। इन महानगरीय नगरों में जनसंख्या का उच्चतम विकास विशाखापत्तनम नगरी ढेर (74.27 प्रतिशत) में दर्ज किया गया, इसके बाद हैदराबाद नगरी समूह (67.04 प्रतिशत), जोकि दोनों आंध्र प्रदेश में थे। सबसे कम वृद्धि दर कोलकाता नगरी समूह (18.73 प्रतिशत) द्वारा दर्ज की गई थी, उसके बाद पटना नगरी समूह था। कोलकाता नगरी संकुलन जिसने 1901 के बाद से ही जन्षंख्या की दृस्टि से प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लिया था १९९१ में यह स्थान ग्रेटर मुंबई का हो गया और कोलकत्ता दूसरे स्थान पर आ गया। इस प्रविति्त का अनुकरण करने वाले चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर रहे हैं । 1988 में, भारतीय नगरी परिदृष्य को स्पष्ट करने वाली विषमताओं का वर्णन करते हुए, राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग ने दो मुख्य पहलुओं को बतायारू (ए) जबकि भारत में नगरी केंद्र 1970 के दशक के दौरान 46.2 प्रतिशत की औसत दर से बढ़े, मिलियन-प्लस इसी अवधि के दौरान महानगरीय केंद्रों में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर केवल 29.6 प्रतिशत थी, और (इ) नगरीकरण प्रक्रिया की प्रकृति में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता थी। वास्तव में, भारतीय नगरीकरण का स्थानिक स्वरूप अत्यधिक स्थानीयकृत रहा है। (इग्नू, 2017: पृष्ठ 6, 2017)

7.5.1 प्रवास

भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में, ग्रामीण लोगों का नगरी क्षेत्रों में प्रवास निरंतर रहा है और यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के नगरी आयोग ने ग्रामीण नगरी प्रवास को 'ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण महत्वश के रूप में देखा। आयोग आगे बताता है कि भूमिहीन मजदूरों, ब्राह्मणों और आदिवासियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से अधिशेष श्रम जारी करने के अलावा, ये नगर अवसर प्रदान करते हैं, जो हमारे संविधान में निहित हैं। इन लाखों लोगों के लिए, हमारे नगरी केंद्र आशा के केंद्र बने रहेंगे, जहां वे एक नया भविष्य बना सकते हैं (मेहता 1984: 778)।

भारत में, नगरी स्थानों पर प्रवास में यह वृद्धि हाल ही में हुई है जो 1930 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी। नगरी क्षेत्रों के कुल प्रवासियों में से 20 प्रतिशत व्यक्ति पाकिस्तान से, 51 प्रतिशत उसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से और 2.5 प्रतिशत अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित हैं। नगरी क्षेत्रों में आप्रवासी धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका मुख्य रूप से पुरुष चरित्र है (सरिकवल 1978: 25)।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने के कारण, अधिशेष ग्रामीण श्रम शक्ति रोजगार पाने की आशा के साथ नगरी केंद्रों में धकेल दी जाती है। अन्य कारक, जिन्होंने नगर की ओर ग्रामीण आबादी (समृद्ध वर्गों सहित) के वर्गों को खींचा है, वे विभिन्न प्रकार की आकर्शक नौकरियों, अच्छे आवास, चिकित्सा, शैक्षिक और संचार सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं।

यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिकीकरण को नगरीकरण के लिए शर्त के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब कृषि के क्षेत्र में एक रिश्तेदार उच्चतम पर बिंदु पहुंच जाता है, तो गांव से पलायन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह देश में असंतुलित भूमि / मानव अनुपात का परिणाम है।

गतिविधि 2

यदि आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो पता करें कि गाँव में आपके कितने रिश्तेदार नगरी क्षेत्रों में चले गए हैं। यह सर्वेक्षण करने के बाद, उनके प्रवास के कारण पर एक नोट लिखें।

या

यदि आप एक नगरी क्षेत्र में रहते हैं, तो एक झुग्गी पर जाएँ और उस क्षेत्र में लगभग बीस परिवारों के प्रवास के कारणों पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

7.5.2 सामाजिक-सांस्कृतिक चरित्र

नगरीकरण की प्रक्रिया ने भारत के नगरों और नगरों ने जातीयता, जाति, नस्ल, वर्ग और संस्कृति के संदर्भ में विषम चरित्र को प्राप्त किया है। नगरी क्षेत्रों में हमेशा विभिन्न संस्कृतियों का सह-अस्तित्व रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न जातीय और/या जाति समूहों ने नगर में एक दूसरे के साथ खुद को समायोजित किया है, उन्होंने अपनी पारंपरिक पहचान को बनाए रखने की भी कोशिश की है। प्रवासियों ने नगरों में विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखा है। विभिन्न प्रवासी समूहों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी है। एन.के. बोस (1968: 66) बताते हैं कि प्रवासियों को ऐसे लोग परेशान करते हैं जिनके साथ उनकी भाषाई, स्थानीय, क्षेत्रीय, जातिगत और जातीय संबंध हैं। जगन्नाथन और हलधर (1989: 315) द्वारा कोलकाता (कलकत्ता) में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के एक अध्ययन से पता चलता है कि वे गाँव से जानकारी और संचार या

संचार के लिए रिश्तेदारी और जाति समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक-बहुलतावाद नगरी लोगों का एक महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम रहा है।

कई भारतीय नगरों में एक 'मिश्रित' चरित्र है, अर्थात, वे राजधानी नगर, व्यापार और वाणिज्य के केंद्र, महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन आदि हैं। इन प्रकार के नगरों में हम एक 'केंद्रीय' क्षेत्र पाते हैं, जिसमें पुराने निवासी होते हैं (श्रीनिवास 1986)। यह क्षेत्र नगर में सबसे पुराना है और इसके किनारे पर हम नए प्रवासियों को पाते हैं। इस 'केंद्रीय' आबादी के निवास का पैटर्न भाषा, जाति और धर्म के बीच एक करीबी रिश्ता दर्शाता है। बंबई को इस प्रकार के नगर के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है।

लिंच (1974) यह भी बताते हैं कि कई भारतीय नगरों में, विशेष रूप से आगरा जैसे पारंपरिक नगरों में, जाति और धार्मिक समूहों के मामले में पड़ोस सजातीय बने हुए हैं। वहां जाटव विशेष क्षेत्रों में केंद्रित हैं जिन्हें मुहल्ला (वर्ल्ड) कहा जाता है। लेकिन बदलाव ज्यादातर राजनीतिकरण, शिक्षा के प्रसार और व्यावसायिक विविधीकरण के कारण हुए हैं। लेकिन डिसूजा (1974) ने देखा कि योजनाबद्ध नगर में चंडीगढ़ पड़ोस की तरह जातीयता, सामान्य हित और अन्य समानताओं के आधार पर विकसित नहीं किया गया है। इस नगर में धार्मिक गतिविधियां, मित्रता और शैक्षिक संबंध अक्सर एक ही पड़ोस में अलग-अलग होते हैं।

सामाजिक स्तरीकरण ने नगरी समाज में एक नया रूप ले लिया है। यह माना जाता है कि नगरीकरण के साथ जाति नगरी क्षेत्रों में खुद को वर्ग में बदल देती है। लेकिन नगरों में जाति व्यवस्था मौजूद है, हालांकि महत्वपूर्ण संगठनात्मक मतभेद हैं। रामकृष्ण मुखर्जी प्रदर्शित करते हैं कि कोलकाता में लोग जाति-पदानुक्रम के मामले में खुद को श्रेणीबद्ध करते हैं। व्यावसायिक श्रेणियों के आधार पर स्तरीकरण भी हुआ है। उदाहरण के लिए, हेरोल्ड गॉल्ड (1965) बताते हैं कि लखनऊ के कई धार्मिक और जाति समूहों से संबंधित रिक्षावाला अपने सामान्य व्यवसाय के संबंध में बातचीत और दृष्टिकोण के पैटर्न में एकरूपता प्रदर्शित करते हैं। फिर से यह पाया गया है कि नगरी क्षेत्रों में व्यवसाय के विकल्प का निर्धारण करने में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समय और स्थान और स्थितिगत ध्यान (राव 1974: 275) के आधार पर जाति और वर्ग दोनों का अपना-अपना महत्व है।

विवाह और परिवार सामाजिक जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। नगरी क्षेत्रों में साथी के चयन के संबंध में जाति मानदंड लचीले रहे हैं। युवा पुरुषों और महिलाओं के मुक्त मिश्रण के अवसर बढ़ रहे हैं। स्वैच्छिक संघों ने भी अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया है। परिणामस्वरूप नगरी क्षेत्रों में पहले की तुलना में अधिक अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह हुए हैं। हालांकि यह बताया गया है कि नगरी क्षेत्रों में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, देश के कई हिस्सों में किए गए अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि संयुक्त परिवार नगरों में कुछ जातियों जैसे कि दिल्ली के खत्रियों और मद्रास के चेट्टियारों में मौजूद हैं (विवरण के लिए देखें कपूर 1965, सिंगर 1968)।

भारत के नगरों का सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में अध्ययन किया जाना है। नगरों में प्रवासियों द्वारा कई छोटी परंपराएँ लाई गई हैं और महान परंपराओं ने भी बहु आयामी परिवर्तन प्राप्त किया है। यह तर्क दिया जाता है कि आधुनिक नगरों में महान परंपराओं के कई रूपों को संशोधित किया गया है। मिल्टन सिंगर (1968) से पता चलता है कि श्भगवान के लिए बौद्धिक और कर्मकांड के दृष्टिकोण को भक्ति दृष्टिकोण के पक्ष में खारिज

किया जा रहा है, जो मद्रास (चेन्नई) नगर में अधिक कैथोलिक और नगरी परिस्थितियों के अनुकूल है। धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोफोन, सिनेमा, ऑटोमोबाइल आदि जैसे तकनीकी नवाचारों का उपयोग किया जाता है। महानगरीय नगर मद्रास (चेन्नई) में धार्मिक गतिविधियाँ घट नहीं रही हैं, बल्कि इनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है "।

7.6 वर्तमान नगरीकरण से संबन्धित समस्याएं

नगरीकरण की वर्तमान प्रक्रिया ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कई समस्याओं का सामना किया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नगरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का विकास रहा है। गंदी बस्तियों की जनसंख्या भारत में सभी प्रकार के नगरों में नगरी आबादी का पर्याप्त हिस्सा है। यहां तक कि चंडीगढ़ जैसा योजनाबद्ध नगर भी मलिन बस्तियों से नहीं बचा है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में झुग्गी आबादी का प्रतिशत क्रमशः 32, 25 और 24 है। झुग्गियों में घटिया आवास, अधिक भीड़ और विद्युतीकरण, निकास , स्वच्छता, सड़कों और पीन के पानी की सुविधाओं की कमी की विशेषता है। मलिन बस्तियां बीमारियों, पर्यावरण प्रद षण, विध्वंस और कई सामाजिक तनावों का प्रजनन स्थल रही हैं। किशोर अपराधी, जुआ, जै अपराध भी झुग्गी क्षेत्रों में संख्या में बढ़े हैं। इन स्थानों पर गरीबी के संकेत सबस अधिक दिखाई देते हैं। गंदी बस्तियों का चित्रमय प्रतिनिधित्व चित्र 7.1 में दिखाया गया है।

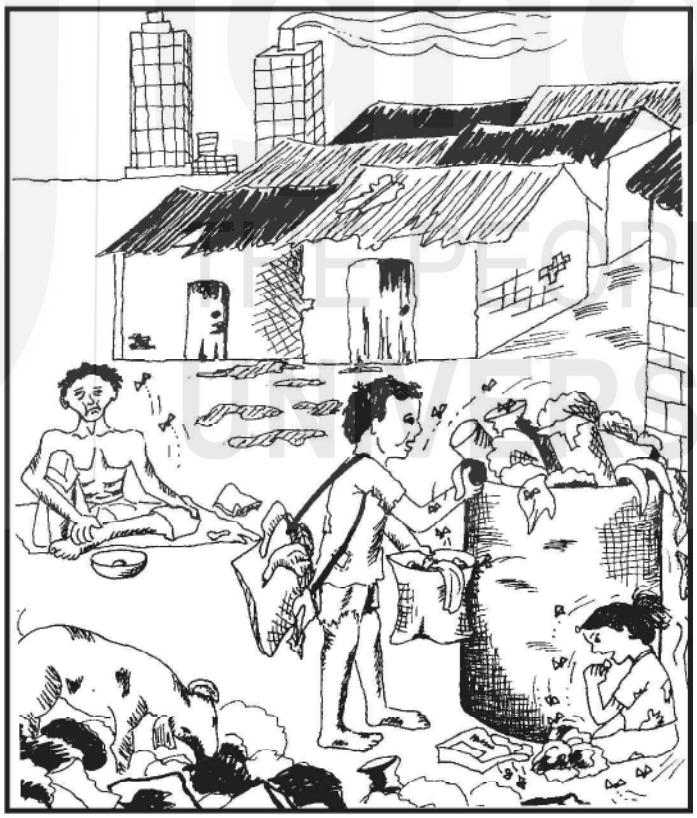

भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में आवास की कमी एक और महत्वपूर्ण समस्या रही है। दस लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में यह समस्या तीव्र है। आवास से संबंधित नगरी भूमि के नियोजित उपयोग पर समस्याएँ हैं। पर्याप्त आवास की कमी को विशेष रूप से निम्न आय वर्ग और नगरी गरीबों के लिए चिह्नित किया गया है। इस समस्या की गंभीरता के मद्देनजर, सरकार ने नगरी भूमि सीमा अधिनियम, किराया नियंत्रण अधिनियम आदि को पारित कर दिया है। नगरीकरण पर राष्ट्रीय परिषद ने भी सिफारिश की है कि सभी नए विकासों में से कम से कम 15 प्रतिशत का उपयोग नगरी आबादी के आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

भारत के अधिकांश नगरी केंद्रों में यातायात और परिवहन के लिए नियोजित और पर्याप्त व्यवस्था की अनुपस्थिति एक और महत्वपूर्ण समस्या है। यद्यपि हमारे महानगरों में परिवहन और उन्नत तकनीक के विभिन्न नए साधनों का उपयोग लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है, फिर भी ये वहां की बढ़ती जनसंख्या के साथ अपर्याप्त हैं। इसी प्रकार, भारत में अधिकांश नगरी केंद्रों में चिकित्सा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली-आपूर्ति की मात्रा अपर्याप्त है।

भारत की नगरी विकास नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि नगरी और राष्ट्रीय विकास में नगरी केंद्रों की सकारात्मक भूमिका हो, ताकि ग्रामीण-नगरी निरंतरता को बढ़ावा दिया जा सके और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जा सके। भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में आवास, स्लम निकासी, झुग्गी सुधार, भूमि अधिग्रहण और विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम शामिल थे।

छठी योजना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (छब्) के विकास पर विशेष जोर दिया, ताकि दिल्ली के मूल से क्षेत्रीय नगरों (राव 1983) में आर्थिक गतिविधियों को केंद्रित किया जा सके। छब् की अवधारणा का उद्देश्य दिल्ली के आसपास के एक विशाल क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में बेहतर क्षेत्रीय समानताएं लाना है। इसे राजधानी की वृद्धि और विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यह योजना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के एकीकृत विकास को शामिल करती है। 1985 में संसद के एक अधिनियमित के माध्यम से एक सांविधिक निकाय का गठन किया गया है और एक मसौदा क्षेत्रीय योजना तब से एनसीआर के विकास के लिए तैयार की गई है (भारत सरकार 1987: 597)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (छब्च्ठ) के संसाधन आधार में योजना प्रावधान के माध्यम से बजटीय आवंटन और ऋण की लाइन के रूप में उधार लेने वाले संस्थान, वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण और कर योग्य और कर-मुक्त बॉन्ड अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में शामिल हैं। एनसीआरपीबी के लिए नौवीं योजना का प्रावधान 200 करोड़ रुपये का था और नौवीं योजना के दौरान बोर्ड ने पूंजी बाजार से जुटाए जाने के लिए रु .120 करोड़ के आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों की परिकल्पना की थी। छब्च्ठ ने सड़क, पुल, पानी की आपूर्ति, सीवरेज निपटान सुविधाओं आदि सहित क्षेत्र के विभिन्न नगरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास की सुविधा प्रदान की है। हाल के वर्षों में सरकार ने नगरी लोगों को विशेष रूप से गरीबों को विभिन्न आवास योजनाओं के तहत मकान बनाने में मदद करने की योजना बनाई है। स्मार्ट सिटी का आइडिया भी विकसित किया गया है

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें

1) भारत में नगरी आबादी के प्रवाह में क्या रुझान है? सही उत्तर पर टिक मार्क करें।

क) एक स्थिर वृद्धि

ख) ठहराव की स्थिति

ग) उपरोक्त दोनों

घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

2) नीचे दिए गए विकल्प में से एक का चयन करके निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरें।

भारत में नगरीकरण की स्थानिक विशेषता रही है

क) स्थानीय

ख) संतुलित

ग) स्थानीय और संतुलित

घ) न तो संतुलित और न ही स्थानीयकृत

3) चार पंक्तियों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

7.7 सारांश

इस इकाई में हमने गाँव, कस्बे और नगर की बुनियादी विशेषताओं पर चर्चा की है। हमने गाँव की अवधारणा पर भी विस्तार से गौर किया है और एक गाँव की प्रकृति और सामाजिक संरचना को समझाने की कोशिश की है। हमने कस्बों और नगरों को परिभाषित किया है। हमने उनकी केंद्रीय विशेषताओं पर चर्चा की। हमने आखिरकार एक नगर की वृद्धि और सामाजिक संरचना दी है। समस्याओं के साथ-साथ इसका सामना करना पड़ता है, जैसे, मलिन बस्तियों आदि में हमने नगरीकरण और सरकार की योजनाओं के परिणामों का उल्लेख किया है ताकि लोगों की समस्याओं, जैसे, बेघर, कमजोर वर्गों के लिए रोजगार आदि को हल करने में मदद मिल सके।

7.8 संदर्भ

अटल योगेश 2016. भारतीय समाज निरंतरता और परिवर्तन, पियर्सन, दिल्ली, चेन्नई ।

देसाई, ए. आर. 1961. ग्रामीण समाजशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र के लिए भारतीय समाज। बंबई।

मदन, वंदना (सम्पादन) 2002. द विलेज इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस, नई दिल्ली।

मैंडेलबाउम, डेविड जी. 1972. सोसाइटी इन इंडिया वॉल्यूम 1 कंटीन्यूइंग एंड चेंज, वॉल्यूम 2 ,निरंतरता और परिवर्तन य लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे

शर्मा के. एल. 2007. भारतीय सामाजिक संरचना और परिवर्तन, रावत प्रकाशन।

शर्मा, आर. के. 2004, अर्बन सोशियोलॉजी, अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, नई दिल्ली।

सिंह, वाई 1986 भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिशर्स, जयपुर।

इग्नू 2017 (पुनर्मुद्रण), ईएसओ -12, सोसाइटी इन इंडिया, ब्लॉक 1 (च्च26-27)

सिंह, आर। 1988. भूमि, पावर एंड पीपल, सेज, दिल्ली

श्रीनिवास, एम. एन. 1972. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, ओरिएंट लैंगमैन, नई दिल्ली

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

अपनी प्रगति की जाँच करें 1

क) (ii)

ख) (iv)

ग) (iv)

घ) (iv)

ii) भारतीय गांवों में जजमानी 'प्रणाली पाई जाती है। यह संरक्षक और ग्राहकों, या जाजमान और विभिन्न जातियों के कामिन के बीच का संबंध है, जो कि आमतौर पर एक गांव के भीतर। यह जातियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान की एक प्रक्रिया है। कुछ जातियां संरक्षक हैं और कुछ ग्राहक हैं। यह एक विरासत में मिला हुआ रिश्ता है। जजमानी नियम ग्रामीण भारत में जाति पंचायतों द्वारा लागू किए जाते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें 2

प) गाँव ने राजनीतिक व्यवस्था के उच्च स्तर से बहुत अधिक स्वायत्तता के साथ-साथ पृथकता का भी आनंद लिया। राजाओं ने दिन-प्रतिदिन के मामलों में ग्रामीणों को खुद पर शासन करने दिया। सड़कों की अनुपस्थिति और खराब संचार भी इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक रहे हैं ।

पप) गाँव को ष्छोटा गणतंत्रष् मानना गलत है क्योंकि राजा ने गाँव के संबंध में कई कार्य किए जैसे कि कुछ सड़कों और नहरों का निर्माण करना, ठगों और दमनकारी सैनिकों से सुरक्षा प्रदान करना और जाति क्रम के में विवादों को निपटाने के लिए अंतिम सत्ता का होना आदि । जो सत्ताधारी थे उनकेलिए ग्रामीण निष्क्रिय और असंयमी नहीं थे। वे एक बुरे राजा के खिलाफ विद्रोह करते थे और एक शासक को मदद करते थे जो उनकी जाति के थे।

अपनी प्रगति की जाँच करें 3

प) अ

पप) अ

पपप)राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवधारणा को दिल्ली की राजधानी नगर की विकास और विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली के एकीकृत विकास के लिए, इस क्षेत्र में 30,000 वर्ग मीटर है जिसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं।

इकाई 8 मजदूर और उद्योग*

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 भारत में कृषि गतिविधियाँ और कृषक वर्ग

8.2.1 भारत में पूंजीवादी कृषक वर्ग संरचना

8.2.2 भारत में गैर-पूंजीवादी कृषक वर्ग संरचना

8.3 सारांश

8.4 संदर्भ

8.5 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्न कार्य कर सकेंगे :

- भारत में कृषि वर्गों की प्रकृति का वर्णन;
- भारत में कृषि वर्गों को परिभाषित करने के विभिन्न उपागमों पर चर्चा; और
- भारतीय कृषि में उत्पादन संबंधों की व्याख्या।

8.1 प्रस्तावना

आपने पिछली इकाई में मानव, आबादी के बारे में पढ़ा। गांव, कस्बा और शहर की तीन अलग-अलग श्रेणियों में सीखा। इस इकाई में हम आपको भारत में कृषि वर्गों की मूल प्रकृति के बारे में बताएंगे। समाजशास्त्रियों द्वारा वर्गीय संरचना के आधार पर समाजों को प्रमुख आर्थिक गतिविधियों, जैसे कि औद्योगिक और कृषि गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि इन गतिविधियों का सुझाव है, औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक समाजों की आर्थिक गतिविधियों पर हावी है और कृषि उत्पादन कृषि समाजों में आर्थिक गतिविधियों को प्रमुखता देता है। उपनिवेशवाद ने उन समाजों को जन्म दिया जिसमें दोनों का अजीब मेल देखा जाता है जो स्थिति को जटिल बनाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ ये मिश्रण मौजूद हैं और आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक और आर्थिक दोनों कारकों द्वारा निर्धारित है। इसलिए, समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने भारतीय कृषि और कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन किया है। भारतीय समाज में कृषि अभी भी एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। इस पृष्ठभूमि में, यह इकाई भारत में कृषि और कृषि वर्गों की प्रकृति पर विभिन्न सैद्धांतिक पदों पर चर्चा करेगी। विचार के विभिन्न मतों से संबंधित विद्वान इस संबंध में अपने स्वयं के विचारों के साथ सामने आए हैं।

8.2 भारत में कृषि संबंधी गतिविधियाँ और कृषि क्षेत्र

भारत में कृषि गतिविधियों और कृषि वर्गों की प्रकृति क्या है, इस पर चल रही और अनसुलझी बहस जारी है। बहस दो दिशाओं में चली गई है (i) भारतीय कृषि उत्पादन की

*डॉ. ओतोजित क्षेत्रिमयुम, एन.एल.आई,नोएडा / अनु. डॉ. शास्वतकुमार

प्रकृति पूरी तरह से पूंजीवादी है। (ii) भारतीय कृषि पूरी तरह से पूँजीवादी नहीं है, बल्कि अर्ध-सामंती है। इन दोनों स्थितियों का असर है कि हम भारत में कृषि वर्ग संरचना को कैसे देखते हैं। उनके मतभेदों के बावजूद, इस बहस के माध्यम से चलने वाला एक सामान्य विषय यह है कि दोनों ही परिवर्तनों की प्रकृति को संबोधित करते हैं अर्थात् ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद से भारतीय कृषि में परिवर्तन। आइए हम एक-एक करके उनकी चर्चा करें।

8.2.1 भारत में पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना

भारतीय कृषि में पूंजीवाद के विकास का प्रश्न भारतीय विद्वानों के बीच विवाद या बहस का प्रमुख स्थल रहा है। अशोक रुद्र और उत्सा पटनायक ऐसे सामाजिक वैज्ञानिक हैं जिनके लेखन से इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या भारतीय कृषि में पूंजीवादी वर्ग के संबंध हैं। दोनों ही इस स्थिति को बनाए रखते हैं कि भारतीय कृषि में वर्ग संबंध प्रकृति में पूंजीवादी हैं, हालांकि दोनों भारतीय कृषि में पूंजीवादी वर्ग संबंधों को भिन्न मापदंडों या आयामों पर परिभाषित करते हैं।

अशोक रुद्र (1978 बी) कहता है कि किसानों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने की सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत है - छोटे, मध्यम और बड़े, भारतीय कृषि में केवल दो वर्ग हैं:

i) बड़े जमींदार और

ii) खेतिहर मजदूर

इसका मतलब यह है कि कृषि पूँजीपतियों (बड़े जमींदारों) का एक वर्ग है और खेतिहर मजदूरों और मजदूरों का एक वर्ग है। पूंजीपति शासक वर्ग के होते हैं। वे शेष कृषि पर शासन करते हैं। पूँजीपति और पूर्व-पूँजीपति वर्ग संबंधों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

पूँजीपति वर्ग संबंध	पूर्व-पूंजीवादी वर्ग संबंध
1) बाजार में बेचे गए श्रम से निकाला गया अधिशेष। उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को वस्तु माना जाता है।	1) अतिरिक्त शोषण के माध्यम से निकाले गए अधिशेष। श्रम स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। यह पराधीन है और यह पैसे के लिए बेची जाने वाली वस्तु नहीं है।
2) वस्तु विनिमय प्रक्रिया में विनिमय के माध्यम से अधिशेष का अनुभव होता है।	2) अधिशेष किसी भी बाजार के सीधे हस्तक्षेप के साथ विनियोजित है।
3) अधिशेष (सरप्लस) ने पूँजी संचय और निरंतर उत्पादन के विस्तार की प्रक्रिया को जन्म दिया।	3) अधिशेष विलासिता की खपत में और विभिन्न अनुत्पादक निवेशों में चला जाता है, जिससे उत्पादन के विस्तार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्पादक पूंजी का स्टॉक नहीं रह जाता है या बहुत थोड़ा ही उपलब्ध होता है ।
4) लाभ का पीछा करने से पूंजी की मूलभूत संरचना में परिवर्तन होता हुआ है और तकनीकी प्रगति की एक सतत प्रक्रिया प्रारंभ होती है	4) तकनीक का उपयोग उत्पादन में सीमित रहता है।

इस तालिका में पहला मानदण्ड इस तर्क को संदर्भित करता है कि उपनिवेशों द्वारा भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण ने वस्तु के रूप में मजदूरी को जन्म दिया है, जिसे न केवल एक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, बल्कि उत्पादन के पूंजीवादी संबंधों वाले भारतीय कृषि को परिभाषित करने के लिए एक पर्याप्त मानदंड भी है। मजदूरी-श्रम का अर्थ

है कि जमींदार भूमिहीन किसानों के श्रम को खरीदते हैं या वे जो जमीन मालिकों की भूमि पर काम करते हैं। इस अर्थ में श्रम किसी अन्य वस्तु की तरह पैसे के लिए बेची जाने वाली वस्तु है। पूंजीवादी वर्ग संरचना में मजदूरी की इस अजीबोगरीब प्रकृति को समझने के लिए, इसे पूर्व-पूंजीवादी चरित्र से अलग करना अत्यावश्यक है। कृषि के पूर्व-पूंजीवादी प्रकृति में, श्रम पैसे के लिए बेचा जाने वाला एक वस्तु नहीं था। उदाहरण के लिए, दासता में दास अपने श्रम को बेचने के लिए ''स्वतंत्र'' नहीं था। दास ने अपने श्रम को गुलाम मालिक को नहीं बेचा जैसे कि पूंजीवादी कृषि में मजदूर अपने श्रम को भूस्वामियों को बेचते हैं। दास को उसके मालिक को उसके श्रम के साथ बेचा जाता है। किसी भी अन्य वस्तु (कमोडिटी) की तरह वह एक वस्तु है, जो एक मालिक के हाथों से दूसरे के पास जा सकती है। वह स्वयं में एक वस्तु है। लेकिन उसका श्रम उसकी वस्तु नहीं है। कृषि-मजदूर अपने श्रम का कुछ हिस्सा ही बेचता है। जमीन के मालिक से बदले में उसे वेतन नहीं मिलता हैय बल्कि भूमि के मालिक को उससे उपहार मिलता है। कृषि-मजदूर जमीन का होता है और जमीन के मालिक को उसके श्रम का फल देता है। दूसरी ओर, मुक्त मजदूर, खुद को बेचता है और वास्तव में, कृषि की पूंजीवादी व्यवस्था में खुद को बेचता है। (मार्क्स, 2010: 203)

> ड्रेज, सेन (1997: पृष्ठ .17) कहते हैं कि जमींदारी उन्मूलन' और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि पद्धतियों में विकास दो प्रकरण थे, जो अपने आप, प्रभाव में बहुत नाटकीय नहीं थे (उदाहरण के लिए भूमि सुधार और उत्पादकता वृद्धि के साथ तुलना में) अन्य विकासशील क्षेत्र, भारत के कुछ हिस्सों सहित) वे जनसंख्या विस्तार के आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के व्यापक मापदंडों को परिभाषित करते हैं। भूमि सुधारों ने बड़े सामंती जमींदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया और बहुसंख्यक काश्तकार, जो पहले जमीन के मालिक नहीं थे, को मालिकाना हक दिया।

एक अन्य विशेषता जिसे अशोक रुद्र द्वारा पूंजीवादी के रूप में भारतीय कृषि में वर्ग संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक विशिष्ट विशेषताओं के रूप में जाना जाता है, उत्पादन के साधनों के मालिकों द्वारा विनियोजित अधिशेष के पुनर्निवेश के माध्यम से उत्पादक पूंजी का संचय है।

अधिशेष की उत्पत्ति और विनियोग प्रत्येक समाज की विशेषता है। अधिशेष का निर्माण और उपयोग अलग-अलग प्रणालियों में भिन्न होते हैं। सामंती विनियोगकर्ता आमतौर पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए अधिशेष का उपयोग करता है। अधिशेष ने विलासिता में उसकी आधिक्य का समर्थन किया। इसके विपरीत, पूंजीवादी विनियोजक आम तौर पर पुरुत्पादन को विस्तारित करने की दृष्टि से पुनरू निवेश के लिए अधिशेष का उपयोग करता है, जो कि लाभ की मात्रा का लगातार विस्तार करने का एक साधन है। पूँजीवादी उत्पादन का विशिष्ट प्रतिमान कभी-न-फायदा देने वाला होता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ की निरंतर खोज होती है (रुद्र, 1978: 918)। आपने अपने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा कि किस प्रकार भारतीय राजाओं ने अपने खजाने का पुनर्निर्माण करने के विचार के बिना विलासिता के उपभोग में अपने अधिशेष को खर्च करके एक भव्य जीवन का आनंद लिया था। यह केवल इस वजह से है कि प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में मंदिर, खजानों के रूप में उभरे हैं। जबकि आज जब आप बड़े पूँजीपतियों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनका खजाना कुछ स्थानों में नहीं रखा गया है बल्कि उनकी पूँजी को और बढ़ाने के लिए विभिन्न रूपों में पुनर्निर्माण किया गया है। वास्तव में, लोग जो मंदिरों में चढ़ाते हैं, जैसे कि, तिरुमाला मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बालों और अन्य महंगी वस्तुओं को व्यापार में डाल दिया जाता है और दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। इसी तरह जब आप भारत में सुदूर कृषि भूमि का दौरा करते हैं तो आपको आम या लीची बैगान या बाग से फल ले जाने का

लालच होता है। आपकी उत्तेजना यह पता लगाने में कम हो गई होगी कि इसे पेड़ों से फल गिराने की अनुमति नहीं है। इसके पीछे सरल कारण यह है कि उन फलों को स्थानीय खपत के उद्देश्य से नहीं उगाया जाता है बल्कि उन्हें बाजार में बेचा जाता है। पूंजीवादी और पूर्व-पूंजीवादी संरचना में अधिशेष के उपयोग के बीच अंतर को समझने का यह एक बहुत ही मूल तरीका है। इसके अलावा, उत्पादन के पूंजीवादी संबंधों से जुड़ी कुछ अन्य विशिष्ट विशेषताएं हैं। 'इस प्रकार, विस्तारित पुरुत्पादन में, लाभ एक नित्य-विस्तार पूंजी की मूलभूत संरचना में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है जो अपनी प्रकृति में मशीन द्वारा मानव श्रम के बढ़ते प्रतिस्थापन और कभी-निरंतर तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है। (रुद्र ए 1978) : 916) आपने एक किसान को फसल की कटाई और नलकूप से सिंचाई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते हुए देखा होगा। तकनीक के इस प्रयोग को पूंजीवादी संबंधों को भी बढ़ावा मिलता है।

रुद्र की अवधारणा के विपरीत, जैसा कि ऊपर दिया गया है, उत्सा पटनायक (1976) भारत में निम्नलिखित कृषि वर्गों की सूची देता है :

शोषक वर्ग

i) जमींदार
   - क) पूंजीवादी
   - ख) सामंत

ii) अमीर किसान
   - क) आद्य-बुर्जुआ
   - ख) आद्य-सामंती

शोषित वर्ग

iii) गरीब किसान
   - क) कृषि मजदूर संचालन भूमि
   - ख) छोटे काश्तकार

iv) पूर्णकालिक मजदूर

वह इन आर्थिक वर्गों को परिभाषित करने के लिए दो मानदंडों का उपयोग करती हैं - उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व , और श्रम का शोषण। वह कहती हैं कि कृषि में, उदाहरण , भारत में, दो/रुवों को आसानी से पहचाना जाता हैरू भूमिहीन और भूमिहीन जिनके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं है। वे मुख्य रूप से या पूरी तरह से दूसरों के लिए काम करने पर निर्भर हैं। भूमि-स्वामी और पूंजीपति उत्पादन के पर्याप्त साधनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे खुद श्रम नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को रोजगार देते हैं। वह कहती है कि कोई भी एकल सूचकांक पूर्ण सटीकता के साथ वर्ग की स्थिति पर कब्जा नहीं कर सकता है। पारिवारिक श्रम के उपयोग के सापेक्ष बाहरी श्रम का उपयोग, किसान को वर्गीकृत करने के लिए सबसे विश्वसनीय एकल सूचकांक होगा बाहरी श्रम का उपयोग। परिवार के श्रम का उपयोग के सापेक्ष भारतीय कृषि में वर्गों को वर्गीकृत करने के लिए विश्वसनीय सूचकांक बन जाता है, क्योंकि जो लोग अपने हाथों में उत्पादन और श्रम के साधनों को केंद्रित करते हैं, वे दूसरों के श्रम का शोषण करने पर निर्भर होंगे, जबकि उन लोगों के पास उत्पादन का कोई साधन नहीं है (भूमिहीन) दूसरों के लिए काम करने के लिए बाध्य होगा।

पटनायक शोषणकारी वर्गों (जमींदारों और अमीर किसानों) और शोषित वर्गों (गरीब किसानों और मजदूरों) के बीच अंतर करते हुए, शोषण के प्रमुख रूप के आधार पर दो अलग-अलग विभाजनों को निर्दिष्ट करता है, अर्थात् मजदूरी या किराया। वह इन वर्गों की विशेषताओं के बारे में बताती हैंः (थोर्नर 1982ः 1993-1999)

जमींदार बड़े जमींदारों के मामले में, चाहे सामंती हो या पूँजीपति, परिवार के सदस्य प्रमुख कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। पर्यवेक्षण या ऑपरेटिंग मशीनरी, शारीरिक श्रम नहीं माना जाता है।

अमीर किसान: वे शारीरिक काम में भाग लेते हैं, हालांकि, उनकी संसाधन स्थिति ऐसी है कि दूसरों के श्रम का विनियोग कम से कम परिवार के श्रम के उपयोग के रूप में महत्वपूर्ण है। मध्यम किसान मुख्य रूप से स्व-नियोजित है क्योंकि औसतन प्रति व्यक्ति संसाधन केवल पर्याप्त रूप से परिवार के श्रम की आपूर्ति को रोजगार देने के लिए और एक प्रथागत निर्वाह स्तर पर जीवनयापन प्रदान करने के लिए पर्याप्त है'।

गरीब किसान: गरीब किसान परिवार को अपने सदस्यों को मजदूरी या भूमि में पट्टे के लिए किराया देना चाहिए चाहे वह कितना भी मजदूरी या किराया हो। आमतौर पर ये परिवार साध्य को समाप्त होने को पूरा नहीं कर सकते हैं और प्रथागत स्तरों के नीचे खपत मानकों के मूल्य को कम करना पड़ता है।

पूर्णकालिक मजदूर : वही पूर्णकालिक श्रमिक परिवारों का सच है। इनमें से कुछ के पास जमीन के छोटे टुकड़े हो सकते हैं, जो वे खेती नहीं करते हैं बल्कि पट्टे पर देते हैं। प्राप्त किराए के बराबर श्रम संतुलन के लिए पर्याप्त नहीं है।

यदि आप रुद्र के भारत में कृषि वर्गों के वर्गीकरण को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि वह उन बड़े भूस्वामियों के बीच कोई विरोधाभास नहीं देखता है जो पूंजीवादी विशेषताओं के साथ काम करते हैं और जो दोनों की सहअस्तित्व को स्वीकार करने के बावजूद वे सामंतों की तरह काम करते हैं। पटनायक पूँजीपति और सामंती जमींदारों को एक अंतर बनाकर स्वीकार करते हैं कि पूँजीवादी जमींदार किराए से अधिक श्रम रखता है जबकि सामंती जमींदार अधिक से अधिक किराए पर श्रम को काम पर रखता है। दूसरे, रुद्र जमींदारों और अमीर किसानों के बीच के अंतर को खारिज करते हैं जिसे पटनायक स्वीकार करते हैं। रुद्र ने खेती के शारीरिक काम में भागीदारी के आधार पर इस अंतर को खारिज कर दिया। भारत में, उन्होंने कहा कि यह मानदंड जाति के कारक से नकारात्मक है। ऐसे उदाहरण हैं जहां बहुत छोटे और गरीब भूमिधारक हल के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि वे उच्च जाति के हैं। इसके विपरीत, आप पाएंगे कि कई सौ एकड़ जमीन रखने वाले परिवारों की महिला सदस्य पंजाब में अपने स्वयं के ट्रैक्टर चलाने में संकोच नहीं करती हैं। बड़े भूस्वामियों का वर्ग 'एकल वर्ग' और 'संकर वर्ग' भी है । संकर वर्ग(हाइब्रिड वर्ग) का अर्थ है कि वे आंशिक रूप से सामंती और आंशिक रूप से पूंजीवादी हैं। रुद्र इसे भारतीय कृषि में शासक वर्ग 'के रूप में संदर्भित करते हैं। रुद्र द्वारा बड़े भूस्वामियों और खेतिहर मजदूरों के अलावा, बाकी आबादी की किसी भी वर्ग के गठन या उससे संबंधित न होने के लिए अवहेलना की जाती है। यह वर्गहीनता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि, जबकि उनमें आपस में विरोधाभास है, उनके पास दो मुख्य वर्गों के साथ स्पष्ट विरोधाभास नहीं है। वर्गविहीनता इस तथ्य के कारण भी उभर सकती है कि विरोधाभास एक सहायक प्रकृति के हैं। केवल दो मुख्य वर्गों के बीच संघर्ष कृषि संरचना में किसी भी बदलाव के लिए प्रेरणा बल प्रदान कर सकता है '। (थॉर्नर, 1982 एः 1995)

रुद्र और पटनायक, दोनों ही वर्गों को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कसौटी पर भिन्न हैं, लेकिन शोषण और शोषित वर्गों के संबंध में समान बिंदु बनाते हैं। रुद्र वर्ग विरोधाभास पर प्रकाश डालते हैं जबकि पटनायक वर्ग शोषण के बारे में बात करते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि भारतीय कृषि में पूंजीवादी वर्ग संबंधों पर बहस की शुरुआत करने वाले दो लोगों को वर्ग विरोधाभासों के लिए वर्ग शोषण की व्याख्या की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकता है। भारतीय कृषि में वर्ग संबंधों को दो विरोधी/रुवों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। रुद्र का सिद्धांत 1968-69 में पंजाब के ग्यारह जिलों में 261 खेतों के सर्वेक्षण अध्ययन पर आधारित है, जबकि पटनायक ने 1969 में पांच राज्यों - उड़ीसा, आंध्र, मैसूर, मद्रास और गुजरात में 66 बड़े किसानों को शामिल किया।

रुद्र और पटनायक के बाद, जॉन हैरिस तमिलनाडु में अपने क्षेत्र के काम के आधार पर भारतीय कृषि में एक प्रकार की पूंजीवादी वर्ग संरचना की पड़ताल करते हैं। 'वह अपने वर्गों को दो मानदंडों के अनुरूप परिभाषित करता है - घरेलू आजीविका आवश्यकताओं और श्रम संबंधों के संबंध में उत्पादन संसाधनों का आकार (भूमि सहित)। (थॉर्नर, ए 1982: 1996) हैरिस कृषि वर्ग को निम्नानुसार वर्गीकृत करते हैं:

i) **पूंजीवादी किसान** : उनके पास ऐसी संपत्ति है जिसके साथ वे बुनियादी आजीविका के लिए आवश्यकता से चार गुना से अधिक का अनुभव कर सकते हैं। वे एक स्थायी श्रम शक्ति को रोजगार दे सकते हैं और वे बहुत कम पारिवारिक श्रम के बाद व्यक्तिगत रूप से योगदान नहीं देते हैं।

ii) **धनी किसान**: उनके पास पूंजीवादी किसानों के समान विशेषताएं हैं सिवाय इसके कि वे काफी हद तक पारिवारिक श्रम पर निर्भर हैं।

iii) **स्वतंत्र मध्यम किसान** : उनके पास 1-2 प्रकार की घरेलू आवश्यकताओं की उपज होती है। वे मुख्य रूप से पारिवारिक श्रम को नियोजित करते हैं और कभी-कभी दूसरों के लिए मजदूरी में संलग्न हो सकते हैं।

iv) गरीब किसान : उनके पास अपनी आजीविका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपत्ति नहीं है। हालांकि, वे मुख्य रूप से मजदूरी पर निर्भर हैं। इनमें सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर शामिल हैं।

सोचें और करें 1

पास के किसी भी क्षेत्र में जाएं जहां लोग कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं और जाति और वर्ग की तर्ज पर भूमि और संपत्ति आदि के स्वामित्व के आधार पर उनके बीच के वर्ग अंतर का पता लगायें ये एक पृष्ठ की एक रिपोर्ट लिखें और इस इकाई में उपलब्ध कराए गए सिद्धांतों के साथ-साथ अपने के साथ अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों की रिपोर्ट के साथ अपने उत्तर का मिलान करें।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1. भारत में पूंजीवादी कृषक वर्गों पर अशोक रुद्र जैसे विद्वानों की क्या राय है? 10 लाइनों में चर्चा करें

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) जॉन हैरिस भारत में कृषि में पूंजीपति वर्ग संरचना को कैसे परिभाषित करते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

8.2.2 भारत में गैर-पूंजीवादी कृषि संरचना

पूर्व-पूंजीवादी अभिव्यक्ति का उपयोग करने के बजाय, हम इस तथ्य को उजागर करने के लिए गैर-पूंजीवादी अभिव्यक्ति का उपयोग कर रहे हैं कि जो लोग उत्पादन के अर्ध-सामंती या अर्ध-सामंती अर्ध-औपनिवेशिक तरीकों के लिए बहस करते हैं, वे उस स्थापना से इनकार नहीं करते हैं कि पूंजीवाद ने भारतीय कृषि में बढ़त बनाई है। और इसके वर्ग रूप जो 'अर्ध' शब्द के उपयोग में स्पष्ट हैं। पूर्व-पूंजीवादी अभिव्यक्ति पूंजीवाद के प्रभाव को उजागर नहीं करती है। गैर-पूंजीवादी पदों का अर्थ है कि भारत ने पूंजीवाद के सीमित और विकृत विकास को देखा है।

अर्ध सामंती

अर्ध सामंत की बात करने वाले पहले प्रख्यात विद्वान अमित भादुड़ी हैं। एक सर्वेक्षण के आधार पर जो उन्होंने 1970 में पश्चिम बंगाल के 26 गांवों में आयोजित किया था, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि "इन गांवों में मौजूदा उत्पादन संबंधों के प्रमुख चरित्र को-अर्ध-सामंती' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। (भादुड़ी ए 1973रू 120) उनका कहना है कि ष उनका कहना है कि 'अर्द्ध-सामंतवाद' शब्द का अर्थ है कि श्उत्पादन के मौजूदा संबंध मास्टर-सर्फ प्रकार के क्लासिक सामंतवाद के साथ अधिक सामान्य हैं, जैसे कि औद्योगिक पूंजीवाद से संबंध की तुलना में यूरोपीय जमींदार और कृषक मजदूर के संबंध। (भादुड़ी 1973: 121) उन्होंने इन अर्ध-सामंती संबंधों की चार प्रमुख विशेषताएं सूचीबद्ध कीं।

बटाईदारी छोटे काश्तकारों की निरंतर ऋणग्रस्तता एक ही आर्थिक वर्ग के हाथों में शोषण के दो तरीके, अर्थात् सूदखोरी और जमीन का स्वामित्वय और छोटे काश्तकरों के लिए बाजार तक पहुंच की कमी। इससे पहले कि हम संबंधित कृषि वर्गों पर चर्चा करें, आइए हम पहले इन विशेषताओं की व्याख्या करें जिनके बिना अर्ध-सामंतवाद में कृषि वर्गों के वर्गीकरण का कोई मतलब नहीं होगा।

बटाईदारी जमींदार कम से कम एक पूर्ण उत्पादन चक्र के लिए अपनी जमीन को पट्टे पर देता है और फिर शुद्ध फसल को कुछ कानूनी रूप से निर्धारित आधार पर काश्तकार और भूस्वामी के बीच बांटता है। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें अला-अलग जटिल

मुद्दों का एक ढांचा शामिल है जैसे (i) कि क्या किरायेदार के पास अपनी खुद की कुछ जमीन है या पूरी तरह से अन्य लोगों की जमीन पर काम करता है, (ii) कि क्या किरायेदार कोई काम करता है या तय करता है पूंजी या पूरी राशि की आपूर्ति भूस्वामी द्वारा की जाती है और (iii) व्यवहार में किरायेदारी का अधिकार कितना सुरक्षित है। "इस कसौटी के आधार पर, भादुड़ी किशन और खेतिहर मजदूर की दो श्रेणियों पर चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल में हिस्सेदारी के अपने अध्ययन के आधार पर, भादुड़ी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारक हैं। सबसे कम विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणी को किसान कहा जाता है। किसान के पास कोई जमीन का स्वामित्व नहीं है। उनके पास एक से अधिक उत्पादन चक्रों के किरायेदारी की सुरक्षा नहीं है। वह दो आधारों पर किसान और खेतिहर मजदूरों के बीच अंतर करता है। सबसे पहले, खेतिहर मजदूर दैनिक या साप्ताहिक मजदूरी के आधार पर काम करता है (नकद या थोड़े या दोनों तरह से भुगतान किया जाता है) और आमतौर पर केवल कृषि के उच्चतम मौसम के दौरान जमीन पर रोजगार पाता है। इस प्रकार, जबकि शेयरधारक को भूमि से उत्पादन बढ़ाने में स्पष्ट आर्थिक रुचि है, लेकिन एक अनुबंध मजदूरी के आधार पर काम करने वाले कृषि मजदूर का ऐसा कोई सीधा हित नहीं है और जिसकी बारीकी से निगरानी की आवश्यकता है । दूसरे, अधिकांश कृषि श्रमिकों के विपरीत, एक किशन के पास अपनी खुद की जमीन का एक छोटा सा भूखंड हो सकता है। लेकिन जब तक उसकी आय का प्रमुख स्रोत उसकी अपनी भूमि से नहीं है, लेकिन अन्य लोगों की भूमि पर खेती करने से है, और उसके पास उत्पादन करने के लिए बहुत कम या कोई पूंजी नहीं है, उसे किसान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। "(भादुड़ी 1973: 121-122) ये वास्तव में पश्चिम बंगाल में किसान वर्ग के गरीब वर्ग हैं।

बटाईदारी को दीपांकर गुप्ता द्वारा एक संस्था के रूप में देखा जाता है, जिसके अस्तित्व से पता चलता है कि पूंजीवाद अभी तक अपने सभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हुआ है। उनके अनुसार पूंजीवाद भारत में समान रूप से विकसित नहीं हुआ है। (थॉर्नर 1982 बीः 2062)

निरंतर ऋणी : भादुड़ी के अनुसार, किसान लगभग हमेशा भारी ऋणी होते हैं। "फसल के कानूनी हिस्से में किसान का एक बड़ा हिस्सा फसल के तुरंत बाद निकाल दिया जाता है क्योंकि ब्याज के साथ पिछले कर्ज की अदायगी होती है, इस प्रकार फसल के अपने कानूनी हिस्से से फसल के वास्तविक उपलब्ध संतुलन को कम कर देता है। यह आमतौर पर इस फसल से अगले तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन के साथ किसान को नहीं छोड़ता है और फसल से कटाई तक जीवित रहने की गंभीर समस्या को केवल उपभोग के लिए उधार लेने से दूर किया जा सकता है। यह उपभोग-ऋण की उसकी नियमित आवश्यकताओं के आधार पर किसान की ऋणग्रस्तता को समाप्त करता है। यह अर्ध-सामंतवाद के मॉडल में एक आवश्यक तत्व है। "(1982: 2062) आपने विदर्भ और हमारे देश के अन्य हिस्सों में किसानों की आत्महत्या के बारे में सुना होगा। स्थायी ऋणग्रस्तता उनके आत्महत्या के प्रमुख कारणों में से एक है।

उपभोग-ऋणों के ऋणदाता के रूप में भूस्वामी: किसान की सतत ऋंणग्रस्तता के अलावा, एक और महत्वपूर्ण कारक है जो अर्ध-सामंतवाद को एक निश्चित चरित्र देता है। यह चरित्र है कि ऋण के प्रयोग का ऋणदाता भी किशान का जमींदार है। ऐसे भूस्वामियों के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थानीय शब्द, जो एक साथ उधार गतिविधियों को भी पूरा करता है, उसे जोतदार कहते हैं । इससे किसान की स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है, क्योंकि वह उसी व्यक्ति को भूमि को पट्टे पर दे रहा है, जिसे वह नियमित रूप से ऋणी है। यह किसान को कृत्रिम रूप से लगभग किसान मजदूर (सर्फ) के करीब ला देता है क्योंकि वह जोतदार को तब तक बांधे रखता है जब तक कि वह जोतदार चाहता

है। किसान अपने कर्ज का निपटारा किए बिना एक नए भूस्वामी की तलाश में बाहर जाने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त, निष्ठा का पहलू किसान को मुक्त न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसं इस आशंका के तहत रहते हैं कि वह नए भूस्वामी के साथ उसी उधार के भरोसे का आनंद नहीं ले सकता है जो वर्तमान भूस्वामी के पास है।इस प्रकार एक भूस्वामी द्वारा को किसान बांधे रखने कासामंती तत्व इन विशेष विधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संचालित होता है। यद्यपि, कानूनी रूप से, किसान कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी ओर, अर्ध-सामंती भूस्वामी अपनी परंपरागत संपत्ति के माध्यम से भूमि पर और सूदखोरी के माध्यम से किशन का शोषण करता है और शोषण के ये दोनों तरीके इस प्रकार की अर्ध-सामंती कृषि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। (भादुड़ी, 1973: 122-123)) इसको समझने के लिए आप एक शास्त्रीय हिंदी फिल्म 'मदर इंडिया' देख सकते हैं जिसने फिल्म की कहानी में इस पहलू को उजागर किया है।

बॉक्स 8.2: 'हरित क्रांति' और सामाजिक गतिशीलता

1960 और 1970 के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और हरियाणा और पंजाब क्षेत्रों के अन्य भागों में उनके प्रसार को ''हरित क्रांति' के रूप में जाना जाने लगा। इसने क्षेत्र की एक सामान्य समृद्धि को जन्म दिया। योगेंद्र सिंह (1988: 5) बताते हैं कि 'हरित क्रांति' न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि का संकेत है, बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं में नई तकनीक और नए सामाजिक संबंधों का उपयोग भी है। ये घटनाक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तनों के इस चरण को विशिष्ट बनाते हैं। प्रौद्योगिकी, सामाजिक संबंध और संस्कृति के बीच एक नई बातचीत अब ग्रामीण समाज में हो रही है। इससे सामाजिक गतिशीलता, नई शक्ति संरचना का उदय और वंचित वर्गों के शोषण के तरीके सामने आए हैं। इसने समाज में नए अंतर्विरोध पैदा किए हैं।

बाजार के लिए दुर्गमता: अर्ध-सामंती आर्थिक संबंधों में भूस्वामियों के हाथों में किसानों के शोषण की गंभीरता तब बढ़ जाती है जब ऋण पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। आपको बंगाल और बिहार के कई गाँवों में इस तरह के पर्याप्त मामले देखने को मिलेंगे। दो मुख्य कारक हैं जो असाधारण उच्च ब्याज दर के कारणों की व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले, किसान आमतौर पर किसी भी वाणिज्यिक बैंकिंग अर्थ में क्रेडिट-योग्य नहीं है क्योंकि उसके पास उधार लेने के लिए कोई संपत्ति नहीं है। उसका एकमात्र ऋणदाता आमतौर पर उसका जमींदार होता है। जमींदार भविष्य की फसल के खिलाफ किसान को पैसे उधार देता है। किसान को अपने नियम और शर्तों पर जमींदार से पैसा उधार लेना पड़ता है। जमींदार किशन का आगे शोषण करने के लिए सभी अतिरिक्त-आर्थिक जबरदस्त तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि किसान के पास ''पूंजी बाजार'' की कोई पहुंच नहीं है। दूसरे, किशन भी आमतौर पर अपने उत्पाद के विक्रेता के रूप में वस्तु -बाजार (कमोडिटी मार्केट) 'तक नहीं पहुंच पाता है। एक उचित व्यापारी के विपरीत, वह अपनी फसल बेचने में आमतौर पर मूल्य में उतार-चढ़ाव का लाभ नहीं उठा सकता है। इसके विपरीत, किसान खुद ही ऐसी कीमत में उतार-चढ़ाव का शिकार है। आपने भारत में किसानों की दुर्दशा के बारे में सुना होगा जहाँ वे बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण अपनी फसल को नष्ट करने के लिए मजबूर थे। मूल्य में उतार-चढ़ाव किसानों के शोषण के प्रमुख साधनों में से एक है। यदि आप जानते हैं कि किसान आमतौर पर जमींदारों से ऐसे समय में उधार लेते हैं, जब मौजूदा बाजार मूल्य अधिक होते हैं, तो यह दुर्दशा होती है, जबकि उन्हें फसल के बाद वापस भुगतान करना होता है, जब बाजार की कीमतें अपने सबसे निचले स्तर पर होती हैं।

सभी जोतदार (यानी, धान का जमींदार-सह-ऋणदाता) वर्तमान बाजार कीमतों पर गणना की गई राशि में पुनर्भुगतान का एक अनुबंध करते हैं। यह अक्सर उच्च ब्याज दर का शामिल है। (भादुड़ी, 19 73 य 123) भादुड़ी ने एक उदाहरण के साथ एक वास्तविक उदाहरण के साथ यह समझायाः चावल के एक ''मांड'' (लगभग 2 पाउंड) की कीमत फसल के बाद स्थानीय गांव में 20 रुपए थी जब यह विशेष रूप से किसान उधार लेता है तो लगभग तीन महीने के समय में 60 रुपए तक बढ़ जाता है। उनके जोतदार ने वर्तमान बाजार कीमतों का इस्तेमाल तरह-तरह से बकाया तय करने के लिए किया, ताकि उच्च मूल्य के मौसम में उधार लिए गए चावल के प्रत्येक ष्मांडष् के लिए, (रुपए 60 रुपए 20) - चावल के 3 ''माउन्ड का भुगतान फसल,बाद वापस किया जाए जोकि कुछ महीनों में ब्याज की 200ः की दर को लागू करता है! हालांकि यह एक अतिवादी उदाहरण है, लेकिन यह उपभोग-ऋण पर ब्याज की देखी गई उच्च दर का सुराग प्रदान करता है। "कमोडिटी मार्केट' में विक्रेता के रूप में अपनी पहुंच की कमी के साथ आधुनिक ष्पूंजी बाजार 'के लिए किसान की दुर्गमता, मूल्य में उतार-चढ़ाव का फायदा नहीं उठा पाने के अर्थ में-बड़े पैमाने पर देखी गई खपत-ऋण पर ब्याज की दर की व्याख्या करती है। । किशन की आधुनिक पूंजी बाजार 'तक पहुंच की कमी ने उसे लगभग पूरी तरह से अपने जमींदार की दया पर रखा है जो समय और भुगतान की शर्तों को अपने लाभ के अनुसार ठीक करता है। इसका परिणाम खपत-ऋण पर अत्यधिक ब्याज दर है जो बदले में अर्ध-सामंती भूस्वामी को आय का एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त स्रोत बनाता है। (भादुड़ी 1973ः 123-124)

प्रधान प्रसाद बिहार के पूर्णिया, सहरसा और मोंगहिर जिलों में किए गए अपने क्षेत्र के काम से भादुड़ी के निर्माण के समर्थन में डेटा प्रस्तुत करते हैं, जहां उन्होंने 1970 और 1972 में 2000 घरों का सर्वेक्षण किया था। भादुड़ी के विपरीत, प्रसाद का दावा है कि 'उनका ''अर्ध-सामंती'' मॉडल है जो ग्रामीण भारत के अधिकांश भाग के लिए प्रमाणिक, 'थार्नर 1993ः 1999 में उद्धृत) है। वह कृषि वर्गों के निम्नलिखित सारणी प्रदान करते है। (थॉर्नर 1982)

i) **शीर्ष किसान,** जिनमें भू-स्वामी भी शामिल हैं, जो अपनी गरिमा से कम भूमि पर भी शारीरिक श्रम करते हैं।

ii) **मध्य और गरीब**-मध्यम किसान, जो अपने खेतों पर शारीरिक श्रम करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए श्रम नहीं करते हैं। मध्यम किसान कृषि मजदूरों में काम पर रखते हैं। गरीब-मध्यम नहीं - ये मूल रूप से मध्यम जाति के हिंदू हैं (यानी, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ी जातियां)।

iii) **कृषि मजदूर,** छोटे परिचालन रखने वालों की एक आकार-सक्षम संख्या। ये ज्यादातर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुछ मध्यम जाति के हिंदुओं से लिए गए हैं।

प्रसाद मध्यम किसानों के बीच एक तीव्र अंतर बताते हैं, जिनकी भूमि में वृद्धि हुई है और जिनकी समग्र आर्थिक स्थिति पिछले तीस वर्षों में मजबूत हो गई है, और शीर्ष किसान। ऊंची जातियों में शामिल ''मध्यम'' जातियों और ''पारंपरिक रूप से प्रभावी'' शीर्ष किसानों के बीच परस्पर विरोधी संबंध है। वह ''जमींदारों, खेती करने वालों और एक तरफ बड़े किसानों और दूसरी तरफ गरीब किसानों'' के बीच एक ''उभरते विरोधाभास'' की बात करते हैं। यह विरोधी संबंध अर्द्ध-सामंती बंधन 'से निकलता है। वह अर्द्ध-सामंती ढांचे के विघटन की भविष्यवाणी करते हैं, जिसे नई उच्च जाति के हिंदू कुलकों और गरीब किसानों

के बीच एक और विरोधाभास के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। वह यह भी भविष्यवाणी करते हैं कि जमींदारों और बड़े किसानों ने आधुनिकीकरण के लिए अपने पुराने प्रतिरोध को आगे बढ़ाया और अपनी खेती को गतिशील करने के लिए कदम उठाए। (थॉर्नर, 1982 एः 1996)

हालाँकि, अर्ध-सामंती प्रमेय की एक विशेषता यह है कि सभी विद्वान जो इस स्थिति में हैं कि कृषि अर्ध-सामंती है, जाति की भूमिका को उजागर करती है। लेकिन इससे उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं गया जो इस स्थिति के पैरोकार हैं कि भारत में पूंजीवादी कृषि वर्ग मौजूद है। कृषि में पूंजीवाद और अर्ध-सामंतवाद की थीसिस के विद्वान भारत में कृषि वर्गों के अपने विश्लेषण में शोषण और विरोधाभास के पहलुओं को उजागर करते हैं।

सोचें और करें

हिंदी फीचर फिल्में - मदर इंडिया और 'दो बीघा जमीन' इंटरनेट पर देखें और भारतीय कृषि में अर्ध-सामंतवाद के तत्वों को सूचीबद्ध करें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ अपनी सूची की तुलना करें।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) अर्द्ध सामंतवाद के मुख्य पात्र क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2. भारतीय कृषि में पूंजीवाद और अर्ध-सामंतवाद की मुख्य विशेषता की तुलना करें।

.....

.....

.....

.....

.....

8.3 सारांश

आपने भारतीय कृषि में पूंजीवाद या अर्ध-सामंतवाद पर बहस के माध्यम से भारत में कृषि वर्गों की प्रकृति का अध्ययन किया है। आपने भारत में कृषि वर्गों की प्रकृति और कृषि गतिविधियों के बारे में सीखा। यहाँ पूंजीवादी वर्गों और अर्ध-सामंती वर्गों के बारे में बहस आपको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शोध के योगदान के माध्यम से समझाई गई थी, जैसे कि अशोक रुद्र, उत्सव पटनायक, अमित भादुरी और अन्य। आपको दोनों पदों के समर्थकों से

परिचित कराया गया है और वे कृषि वर्गों की विभिन्न श्रेणियों और उन मापदंडों को रेखांकित करते हैं, जिनका उपयोग वे अपने संबंधित पदों की रक्षा के लिए करते हैं।

8.4 संदर्भ

भादुड़ी, अमित, 1973.ए स्टडी इन एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस अंडर सेमी-फ्यूडलिज्म ', *द इकोनॉमिक जर्नल,* वॉल्यूम। 83, नंबर 329, .पृष्ठ 120-137.

रुद्र, अशोक, 1978. भारतीय कृषि में वर्ग संबंधः, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, खं, 13, नंबर .2, पृष्ठ. 916-923.

रुद्र, अशोक, 1978, भारतीय कृषि में वर्ग संबंध,इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, खंड। 13, छव.23, पृष्ठ. 963-968.

रुद्र, अशोक, 1978, भारतीय कृषि में वर्ग संबंध, ,इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, खंड। 13, नंबर 24, पृष्ठ. 998-1004.

मार्क्स, कार्ल, 2010. मार्क्स और एंगेल्स कलेक्टेड वर्क्स, वॉल्यूम 9. लॉरेंस और विष्ट इलेक्ट्रिक बुक्स में, वेज लेबर एंड कैपिटल'.

पटनायक, उत्सव, 1976. किसान के भीतर वर्ग भेदभावः भारतीय कृषि का विश्लेषण करने के लिए एक दृष्टिकोण ',इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, टवस.11, छव.39, पृष्ठ .83-।85 ।87-।101.

थॉर्नर, ऐलिस,1982. अर्ध-सामंतवाद या पूंजीवाद? वर्गों और भारत में उत्पादन के मोड पर समकालीन बहस ष्इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, टवस.17, नंबर 49, .पृष्ठ1961-1968.

थॉर्नर, ऐलिस। 1982, अर्ध-सामंतवाद या पूंजीवाद? वर्गों और भारत में उत्पादन के मोड पर समकालीन बहस 'इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, टवस.17, नंबर 50, .पृष्ठ1993-1999.

थॉर्नर, ऐलिस, 1982, अर्ध-सामंतवाद या पूंजीवाद? वर्गों और भारत में उत्पादन के मोड पर समकालीन बहस 'इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, टवस.17, नंबर 51, पृष्ठ.2061-2066.

8.5 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) अशोक रुद्र के अनुसार, भारत में किसानों को छोटे, मध्यम और बड़े वर्ग में विभाजित करने के बजाय (i) बड़े भूमि मालिकों और (ii) खेतिहर मजदूरों के दो वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, उसके लिए कृषि पूँजीपति वर्ग और खेतिहर मजदूरों और मजदूरों का एक वर्ग है। बड़े भूमि मालिक भारतीय कृषि में शासक वर्ग हैं।

2) जॉन हैरिस भारतीय कृषि में पूंजीवादी वर्ग संरचना को दो मानदंडों के आधार पर परिभाषित करता है, (i) घरेलू आजीविका आवश्यकताओं और श्रम संबंधों के संबंध में उत्पादन संसाधनों का आकार (यानी भूमि)। उनका अध्ययन तमिलनाडु में

उनके क्षेत्र के काम पर आधारित है। वह कृषिविदों को (ii) पूंजीवादी किसानों (iii) समृद्ध किसान के रूप में वर्गीकृत करता हैय (iv) स्वतंत्र मध्यम किसानय और (v) गरीब किसान।

बोध प्रश्न 2

1) अर्द्ध-सामंतवाद की मुख्य विशेषताएं अमित भादुड़ी द्वारा दी गई हैं, जो मानते हैं कि भारत के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि, पश्चिम बंगाल के 26 गाँव उत्पादन के मौजूदा संबंध यूरोपीय जमींदार और सर्फ के सामंती संबंध या पूर्व पूँजीवादी युग के मास्टर और सर्फ संबंध , के स्वरूप समान हैं। उन्होंने अर्ध-सामंती विशेषताओं की पहचान की, जैसे कि फसल काटना, छोटे किरायेदारों की सतत ऋणीता, सूदखोरी के दो शोषक वर्गों की एकाग्रता और एक ही आर्थिक वर्ग के हाथों में भूमि स्वामित्वय और बाजार में छोटे किरायेदार की पहुंच की कमी है।

2) पूंजीवादी कृषि वर्ग, साथ ही साथ, अर्ध-सामंती कृषि वर्ग के अधिवक्ताओं, दोनों के लिए भारत में कृषि वर्ग संरचना की मुख्य विशेषता कृषि समाज की शोषणकारी और विरोधाभासी स्वभाव वाली प्रकृति है।

इकाई 9 कृषक वर्ग*

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्योग की अवधारणा

9.3 उद्योग और इसके प्रकार

9.4 भारत में उद्योगों का विकास

- 9.4.1 प्राचीन उद्योग
- 9.4.2 मध्यकालीन उद्योग
- 9.4.3 आधुनिक उद्योग
  - 9.4.3.1 ब्रिटिश काल के दौरान आधुनिक उद्योगों का परिचय
  - 9.4.3.2 आजादी के बाद के उद्योग
  - 9.4.3.3 पोस्ट उदारीकरण उद्योग

9.5 औद्योगिक नीतियों के विभिन्न परिणाम

9.6 श्रम शक्ति की प्रकृति

- 9.6.1 औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार
- 9.6.2 भारत में व्यापार संघों की उत्पत्ति
- 9.6.3 श्रम कल्याण और कानून

9.7 सारांश

9.8 संदर्भ

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

इस इकाई से गुजरने के बाद, आप समझने में सक्षम होंगे –

- उद्योग और इसके प्रकारों की अवधारणा।
- भारत में उद्योगों का उद्विकास।
- श्रम शक्ति की प्रकृति, और इसके प्रकार
- भारत में ट्रेड यूनियन और अंत में
- श्रम कल्याण के उपाय और विधान।

9.1 प्रस्तावना

आपने भारत में विभिन्न कृषि वर्गों और इकाई 08 कृषि वर्गों में उनकी विशेषताओं के बारे में सीखा। यहाँ इस इकाई में हम आपको विभिन्न प्रकार के उद्योग की अवधारणा के बारे में समझाएंगे। जब हम भारत में विभिन्न उद्योगों के बारे में बात करते हैं, तो हम इसके

*डॉ कुसुमलता, सी.सी.एम.जी (CCMG), जे.एम.आई / अनु.श्री एम.पी कंवल

ऐतिहासिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। औपनिवेशिक काल में विभिन्न प्रकार के औजारों और तकनीकी विकास ने आधुनिक उद्योगों को विकसित करने में कैसे मदद की। अंग्रेज भारत में अपनी तकनीक लाए जैसे, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ आदि। हमने भारत में श्रम शक्ति की प्रकृति के बारे में बताया है। शुरू में फैक्ट्री के अधिकांश मजदूर, मिल मजदूर पड़ोस के जिलों और क्षेत्रों से कैसे आए। बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और इसी तरह के दूरदराज के क्षेत्रों से लोगों के फैलने के कारण विभिन्न राज्यों और ध या उन क्षेत्रों में पलायन शुरू हो गया जहाँ इन कारखानों/उद्योगों को अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता थी। हमने कपड़ा मिलों आदि का उदाहरण दिया है और फिर भारत में ट्रेड यूनियनों की उत्पत्ति कैसे हुई है इस बारे में बताया गया है । अंत में, हमने श्रम कल्याण उपायों और विधानों के बारे में बात की है।

9.2 उद्योग की अवधारणा

उद्योग को उच्च स्तर के स्वचालन और विशेषज्ञता के साथ अच्छी तरह से संगठित कारखानों में माल के सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर विनिर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालाँकि, यह उद्योग की एक सामान्य अवधारणा है, लेकिन इसमें अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ भी शामिल हो सकती हैं जो कृषि, परिवहन, आतिथ्य और इसी तरह की अन्य सेवाएँ प्रदान करती हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या

पेशा (अंग्रेजी में कॉलिंग या ऑकुपेशन (Occupation)) के रूप में ''उद्योग'' को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति की नौकरी या व्यवसाय, जैसे कि, किसी शिक्षक या चिकित्सक की नियुक्ति, कोई सेवा, सेवा , रोजगार, हस्तकला या औद्योगिक व्यवसाय या काम करने वाले लोगों का व्यवसाय आदि ।

एक उद्योग केवल तभी मौजूद होता है जब नियोक्ताओं (employee) और कर्मचारियों के बीच संबंध होता है, पूर्व व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, नियोक्ताओं की विनिर्माण व्यवसाय में लगा होता है, जबकि बाद वाला अर्थात कर्मचारी पेशा , सेवा, रोजगार, हस्तकला या औद्योगिक व्यवसाय में श्रमिकों के रूप में लगे होते हैं।

9.3 उद्योग और इसके प्रकार

जब हम उद्योगों की प्रकृति और अवधारणा पर चर्चा करते हैं तो हम आम तौर पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में चर्चा करते हैं। यहां हम आपको उद्योग के कुछ प्रकारों का विवरण देंगे

1) **प्राथमिक उद्योग**

प्राथमिक उद्योगों द्वारा हम उन लोगों का उल्लेख कर रहे हैं जो जमीन या समुद्र से कच्चे माल (जो प्राकृतिक उत्पाद हैं) निकालते हैं। तेल, लौह अयस्क, लकड़ी, मछली, खनन, उत्खनन, मछली पकड़ने, वानिकी और खेती आदि ये सभी प्राथमिक उद्योगों के उदाहरण हैं।

2) **द्वितीयक उद्योग** (कभी-कभी विनिर्माण उद्योग के रूप में संदर्भित)

इन उद्योगों में शारीरिक श्रम या मशीनों द्वारा कच्चे माल का निर्माण, साबुन, वस्त्र, खिलौने आदि जैसे उत्पादों का निर्माण शामिल है।

द्वितीयक उद्योग अक्सर कार कारखाने की तरह असेंबली लाइन उत्पादन का उपयोग करते हैं। यहां अमेरिका में फोर्ड कार कंपनियों द्वारा कारों के उत्पादन के लिए सबसे पहले शुरू की गई कन्वेयर बेल्ट प्रणाली एक अच्छा उदाहरण है। इससे एक ओर औद्योगिक श्रमिक का अलगाव होता है, लेकिन दूसरी ओर पूंजीवादी मालिकों को बढ़ावा मिलता है। इस तरह के औद्योगिक उत्पादन को नए औद्योगिक समाज के उद्‌भव के रूप में देखा जा सकता है।

3) **तृतीयक उद्योग** (कभी-कभी सेवा उद्योग के रूप में संदर्भित)

ये उद्योग न तो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं और न ही कोई उत्पाद बनाते हैं।

इसके बजाय वे लोगों और उद्योगों को सेवाएं प्रदान करते हैं।

तृतीयक उद्योगों में डॉक्टर, दंत चिकित्सक, बैंक आदि जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

4) **चतुर्थक उद्योग**

ये उद्योग उच्च तकनीकी उद्योगों के उपयोग को शामिल करते हैं।

जो लोग इन कंपनियों के लिए काम करते हैं, वे अक्सर अपने कार्यक्षेत्र में अत्यधिक योग्य होते हैं।

अनुसंधान और विकास कंपनियां इस क्षेत्र में सबसे आम प्रकार के व्यवसाय हैं।

5) **पंचम (क्विनरी) उद्योग**

इन उद्योगों में वे शामिल हैं जो औद्योगिक और सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।

इन उद्योगों में उद्योग के अधिकारी, प्रबंधन, नौकरशाह और सरकार में निर्वाचित अधिकारी शामिल हैं। इस स्तर पर नीतियां और कानून बनाए और लागू किए जाते हैं।

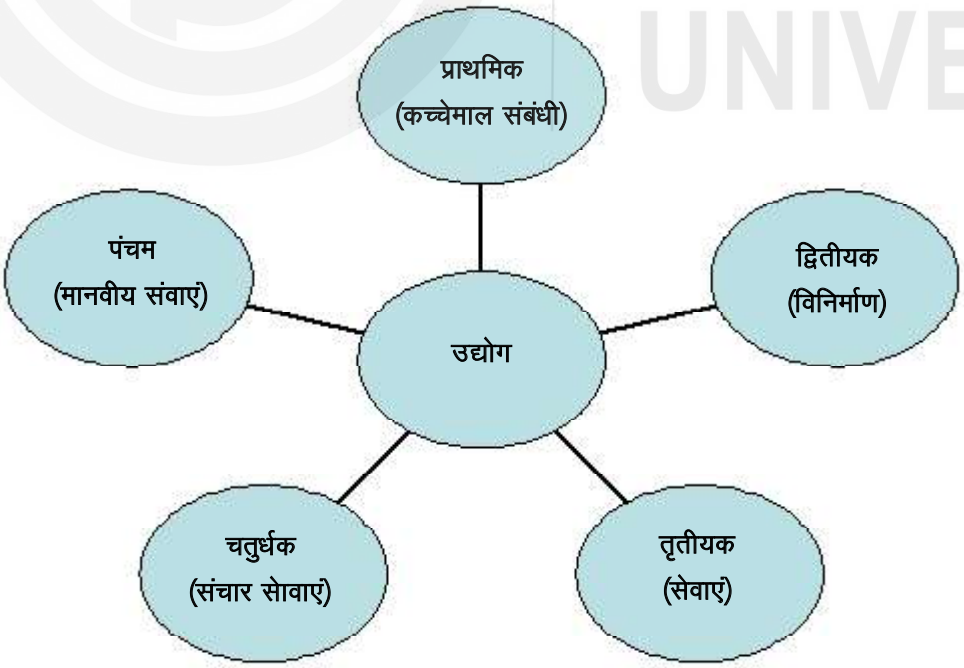

चित्र : उद्योग के प्रकार

9.4 भारत में उद्योगों का उद्विकास

भारत में औद्योगिक विकास के इतिहास को तीन अवधियों के माध्यम से रेखांकित किया जा सकता हैः प्राचीन उद्योग, मध्यकालीन उद्योग और आधुनिक उद्योग।

9.4.1 प्राचीन उद्योग

प्राचीन या आदिम काल में उद्योग को उन कार्यों को शामिल करने के लिए समझा जा सकता है जो मानव द्वारा किए गए थे, जब वे जंगलों या रेगिस्तानों में जीवन जीने के लिए बहुत ही सरल उपकरणों और विधियों पर निर्भर थे। इस अवधि में कोई व्यवस्थित उद्योग विकसित नहीं हुआ था। इस प्रकार इन दिनों के दौरान लोगों की मुख्य चिंता भोजन और शारीरिक सुरक्षा हासिल करने की थी। वे साधन, जो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनके द्वारा अपनाया गया था, उनके औद्योगिक प्रयास का प्रतीक थे। भोजन के लिए आदिम लोग जानवरों का शिकार करते थे और जंगली सब्जियां और फल इकट्ठा करते थे। शिकार के लिए उसने धनुष और तीर और पत्थर से बने कुछ उपकरण लगाए। सभी आदिम हथियार लकड़ी या पत्थर के बने होते थे। ये हथियार उस काल के औद्योगिक विकास के प्रतीक थे। इसके अलावा, पत्थर या बांस के घर्षण से आग बनाना उस युग का औद्योगिक चमत्कार था। यहां हम उन आदिम लोगों की बात कर रहे हैं जो प्राचीन काल में गुफाओं और जंगलों में रहते थे।

9.4.2 मध्यकालीन उद्योग

मध्यकाल के दौरान उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ था। इस अवधि में मनुष्यों के प्रयासों में उद्योग के संकेत काफी दिखाई देने लगे। रूप रूप से संचालित मशीनों की एक संख्या गढ़ी गई थी। मनुष्य ने भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पशु शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। औद्योगिकीकरण के संकेत, खपत से अधिक वस्तुओं का उत्पादन यानी अधिशेष खाद्यान्न और अन्य उत्पाद शुरू हुए और इनका संग्रहण इस समय में साक्ष्य के रूप में आया। वस्तुओं का आदान-प्रदान और श्रम विभाजन भी प्रचलन में आया। इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न उद्योगों ने अलग-अलग काम करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, लोहार, बढ़ई और बुनकरों ने स्वतंत्र इकाइयाँ स्थापित किया । इस प्रकार, नौकरियों की विशेषज्ञता शुरू हुई। कारीगरों की कलात्मक भावना जागृत हुई। पश्चिम में मध्यकालीन औद्योगिक युग को तीन अलग-अलग औद्योगिक प्रणालियों में विभाजित किया जा सकता है। यह विभाजन औद्योगिक प्रणाली की प्रकृति पर आधारित था। ये औद्योगिक प्रणाली सामंती प्रणाली, गिल्ड प्रणाली और घरेलू प्रणाली हैं।

9.4.3 आधुनिक उद्योग

भारत में आधुनिक उद्योग का उद्भव आम तौर पर 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जुड़ा हुआ है, जब उद्योग में व्यापारी पूंजी का चलन तीव्र गति से बढ़ा । 19 वीं शताब्दी के अंत में, एक भारतीय व्यवसायी के पास आधुनिक उद्योगों का एक परिसर था, जो पश्चिमी भारत में फैला हुआ था। बंबई और अहमदाबाद की कपास मिलें इसके उदाहरण हैं। दो विश्व युद्धों के बीच आधुनिक उद्योग द्वारा बाद में लगभग आधी सदी के बाद इस विकास का अनुसरण किया गया। यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से औद्योगिक और विनिर्माण क्षमता में सुधार किया जाता है और साल दर साल उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ उन्नत होता जाता है और यह किसी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन जाता है।

इतिहासकारों ने औद्योगिकीकरण और औद्योगिक क्रांति को इतिहास के आधुनिक काल की शुरुआत के रूप में देखा है, जो क्रांति और उत्पादन के पूंजीवादी मोड की परिपक्वता के साथ संबद्ध है। परंपरागत रूप से इतिहासकारों ने इंग्लैंड को दुनिया की पहली कार्यषाला के रूप में देखा है जहां कई स्थितियों में पूंजीवादी उद्यम के विकास की सुविधा मिली जो एक भरोसेमंद घरेलू बाजार और एक विदेशी विस्तार पर निर्भर हो सकता था । कृषि में पूंजीवादी संबंधों के उद्भव, व्यापार के विस्तार और प्रौद्योगिकी के विकास और उद्योग और नवाचार के लिए पूंजी की आवाजाही का मतलब था कि 18 वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड पहली औद्योगिक क्रांति का अनुभव कर रहा था। इसी अवधि में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का उदय हुआ, जहां 18 वीं शताब्दी के अंत तक, औपनिवेशिक शासकों द्वारा अधीनता के संबंध में दो अर्थव्यवस्थाओं को बांधने के लिए विकास की एक श्रृंखला शुरू हुई थी और खुद के उद्योग के लिए भारत के धन का दोहन करने के लिए उनका शोषण होने लगा। भारत अशहरीकरण और अपनी स्वयं की संपन्न कला, वाणिज्य, हस्तकला आदि के विनाष की प्रक्रिया से गुजरा और जब बड़े पैमाने पर पलायन गाँवों की तरफ हुआ तो इसके कारण कृषि क्षेत्र पर अधिक बोझ बढ़ गया।

आमतौर पर दो प्रकार के औद्योगीकरण होते हैं, एक बड़े पैमाने पर आधारित उद्योग है जो श्रम उत्पादकता में तेजी से वृद्धि करने में सक्षम है, और इसलिए औसत आय उत्पन्न करते हैं। यह पूंजी गहन प्रौद्योगिकी और संसाधनों के कुशल संगठन के माध्यम से ऐसा करता है। दूसरी ओर लघु उद्योग एक अन्य प्रकार का उद्योग विकसित हुआ लेकिन अधिक श्रम गहन होने के कारण इसमें समान स्तर के रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन केवल एक सीमित तरीके से इसका विकास हुआ और इसके लिए औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव और सस्ते श्रम की उपलब्धता का संयोजन और तुलनात्मक रूप से पूंजी की लागत और की कमी थी।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें

1) लगभग 5 लाइनों में उद्योग की अवधारणा को परिभाषित और चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) उन उद्योगों के प्रकारों की सूची बनाएं जिनके बारे में आपने सीखा है।

.....

.....

.....

.....

.....

9.4.3.1 ब्रिटिश काल के दौरान आधुनिक उद्योगों का परिचय

भारतीय व्यापार की दीर्घकालिक गिरावट और 1830 और 40 में भारतीय अर्थव्यवस्था में मन्दी (यानी कीमतों में गिरावट) और साथ ही सस्ते वस्त्रों के ब्रिटिश आयातों द्वारा इसके प्रतिस्थापन को ''विऔद्योगीकरण'' की अवधि के प्रारम्भ रूप में देखा गया है, इसका मतलब था कि स्थानीय या घरेलू कारीगर (हस्तकला व्यवसाय) उद्योगों में गिरावट। ''विऔद्योगीकरण (डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन)एक विवादास्पद बहस रही है या नहीं, इसका विवरण यहां ध्यान केंद्रित करना नहीं है। हालाँकि, हमारे पास रोजगार के जो सबूत हैं, उनसे पता लगता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में आधुनिक उद्योग के उद्‌भव से कारीगरों के उद्योगों में गिरावट नहीं आई।

कारखानों को श्रमिकों की जरूरत थी। कारखानों के विस्तार के साथ, यह मांग बढ़ गई। 1901 में, भारतीय कारखानों में 584,000 श्रमिक थे। 1946 तक यह संख्या 2,436, 000 से अधिक थी। श्रमिक कहां से आए थे? अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक क्षेत्रों और इन क्षेत्रों के आसपास के जिलों से आए थे और कारीगरों को, जो गाँव में कोई काम नहीं करते थे, काम की तलाश में औद्योगिक केंद्रों में जाते थे। 1911 में बॉम्बे कॉटन उद्योगों में 50 प्रतिशत से अधिक श्रमिक पड़ोसी जिले रत्नागिरी से आए थे, जबकि कानपुर के मिलों ने अपने टेक्सटाइल के अधिकांश हिस्से कानपुर जिले के गाँवों से प्राप्त किए थे। फसल और त्यौहारों के दौरान अपने गाँव के घरों को लौटते हुए, ज्यादातर श्रमिक गाँव और शहर के बीच चले जाते थे । समय के साथ, जैसे ही रोजगार की खबर फैली, श्रमिकों ने मिलों में काम की उम्मीद में बहुत दूरियां तय कीं। उदाहरण के लिए, संयुक्त प्रांत से, वर्तमान में उत्तर प्रदेश से, वे बंबई की कपड़ा मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में काम करने गए थे। नौकरी मिलना हमेशा मुश्किल था, यहां तक कि जब मिलें कई गुना बढ़ गयी और श्रमिकों की मांग बढ़ गई तब भी काम मांगने वालों की संख्या हमेशा उपलब्ध नौकरियों से अधिक थी ।

9.4.3.2 स्वतंत्रता के बाद उद्योग

1953 में समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि में पारंपरिक उद्योगों के बाद की निर्भरता अवधि के उदाहरणों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन आधुनिक उद्योगों जैसे मोटर, डीजल इंजन, बैटरी, ट्रांसफार्मर, रेडियो और विभिन्न अन्य वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण में इसी अवधि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई । तब से, अन्य क्षमता और उत्पादन आनुपातिक गति से बढ़ रहे हैं। इस अवधि के दौरान औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगम जैसी कई संस्थाओं और एजेंसियों की स्थापना की गई ताकि उद्योग के विकास में मदद की जा सके। आजादी के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत और 1948 के 'औद्योगिक नीति प्रस्ताव' में व्यक्त की गई जोकि उद्योग में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी थी। तब से राष्ट्र अर्थव्यवस्था के विकास में में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के मिश्रित स्वरूप अनुसरण कर रहा है।। 1956 में 'नई औद्योगिक नीति प्रस्ताव' प्रकाशित होने पर उद्योग के लिए यह दोहरा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी हो गया। इसके अनुसार, उद्योगों को तीन श्रेणियों यानी ए, बी और सी श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणी ए के अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जिन्हें केवल सरकार ही संभाल सकती है।

ए - इनमें से कुछ परमाणु ऊर्जा, विद्युत, लोहा और इस्पात जैसे हैं।

बी - श्रेणी बी में वे उद्योग शामिल हैं जो निजी हाथों में हैं, लेकिन राज्य द्वारा सड़क और

समुद्री परिवहन, मशीन टूल्स, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक और उर्वरकों सहित रसायनों, फेरो मिश्र और कुछ प्रकार के खनन पर उत्तरोत्तर रूप से लिया जा सकता है।

सी - सी श्रेणी के अन्तर्गत उद्योग आते हैं जिन्हें निजी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, जैसे, कृषि, होटल, सौंदर्य मनोरंजन आदि।

9.4.3.3 उदारीकरण–पश्चात उद्योग

मिश्रित अर्थव्यवस्था ने शुरुआती चरण में देश को भारी उद्योगों जैसे स्टील प्लांट्स-भिलाई और राउरकेला को विकसित करने में मदद की थी, और परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम आदि जिसके लिए निजी क्षेत्र प्रवेश नहीं कर सकता था। इस युग को ष्परमिट राज 'के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि इस चरण के दौरान सरकार का औद्योगिक विकास परियोजनाओं पर पूरा नियंत्रण था। कई निजी निकाय/एजेंसियां उचित प्रमाण पत्र या परमिट प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश कर सकते हैं। अक्सर, यह कहा जाता है कि किसी कागजात को प्राप्त करने के लिए काला धन का प्रयोग बढ़ा और इससे परियोजनाओं में बिलम्ब हुआ । इस दौरान निजी पहल को हतोत्साहित करने का यह भी एक बड़ा कारण है। यह 1990 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया चरण सरकार द्वारा पेश किया गया जब अर्थव्यवस्था कुछ हद तक उदारीकृत, निजीकृत और वैष्वीकृत हो गई थी। इसे ही एलपीजी (LPG) कहा जाता है । इस चरण के कारण अर्थव्यवस्था भी उदारीकृत हो गई और विदेशी निवेश का प्रवेश अपेक्षाकृत आसान हो गया।

भारत में औद्योगिक नीति को विभिन्न निम्न अवधियों के द्वारा समझया जा सकता है (i) 1991 से पहले के सुधार की अवधि और 1991 के बाद (ii) उत्तर-सुधार की अवधि। 1991 के पूर्व की औद्योगिक नीतियों ने देश में तेजी से औद्योगिक विकास के लिए माहौल बनाया। इसने व्यापक आधारभूत संरचना और बुनियादी उद्योगों को बनाने में मदद की थी। बड़ी संख्या में वस्तुओं पर आत्मनिर्भरता के साथ एक विविध औद्योगिक संरचना हासिल की गई थी। आजादी के समय उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग में औद्योगिक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा था। 1991 में ऐसे उद्योगों का लगभग 20 प्रतिशत ही था। इसके विपरीत पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कुल औद्योगिक उत्पादन के 4 प्रतिशत से कम था। 1991 में यह 24 प्रतिशत हो गया था। नए उद्योगों की एक बड़ी विविधता में औद्योगिक निवेश हुआ। आधुनिक प्रबंधन तकनीकों की शुरुआत की गई। उद्यमियों का एक नया वर्ग सरकार से समर्थन प्रणाली के साथ आया है, और देश के लगभग सभी हिस्सों में बड़ी संख्या में नए औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं। वर्षों से, सरकार ने उद्योग द्वारा आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और बिजली, संचार, सड़क आदि की बहुत आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। उद्यमिता विकास में मदद करने, उद्योग के लिए वित्त प्रदान करने के लिए अच्छी संख्या में संस्थानों को बढ़ावा दिया गया और उद्योग द्वारा आवश्यक विभिन्न कौशलों के विकास को सुविधाजनक बनाया गया है ।

9.5 औद्योगिक नीतियों के विभिन्न परिणाम

हालाँकि, औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन में कमियों का सामना करना पड़ा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह तर्क दिया जाता है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली ने अक्षमता को बढ़ावा दिया है और इसका परिणाम उच्च लागत वाली अर्थव्यवस्था है। लाइसेंसिंग को प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुसार क्षमताओं के निर्माण को सुनिश्चित करना था।

हालांकि, लाइसेंसिंग अधिकारियों में निहित विवेकाधीन शक्तियों के कारण प्रणाली भ्रष्टाचार और कर की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इसने नए उद्यमों के प्रवेश को हतोत्साहित किया और प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है । इसके विपरीत प्रणाली ने बड़े उद्यमों का समर्थन किया और पिछड़े क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया। सरकार ने 1970, 1973 और 1980 की औद्योगिक नीति में कई उदारीकरण उपायों की घोषणा की। हालांकि, 1991 के दौरान औद्योगिक नीति में नाटकीय उदारीकरण के प्रयास किए गए थे।

जुलाई 1991 में भारत की नई औद्योगिक नीति की घोषणा उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं के मामले में अपनी पहले की औद्योगिक नीतियों की तुलना में रूढ़िवादी थी। इसने पहले से किए गए लाभों को संगठित करने और गड़बड़ियों और कमजोरियों को ठीक करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के आधार पर आगे के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। (उद्योग मंत्रालय, 1991)। उदारीकृत औद्योगिक नीति का उद्देश्य तेजी से और पर्याप्त आर्थिक विकास है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से एकीकरण करना है। औद्योगिक नीति सुधारों ने औद्योगिक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को कम कर दिया है, निवेश और विस्तार पर प्रतिबंध हटा दिया है, और विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान की है। इसने विभिन्न उद्योगों में सार्वजनिक, निजी भागीदारी या पीपीपी को पेश करने में मदद की, जैसे कि, सरकार अपने दम पर रियलिटी सेक्टर द्वारा आवास और कार्यालय विकास प्रदान नहीं कर सकी। इसलिए, निजी बिल्डर्स ने अपने निवेश के साथ बाजार में प्रवेश किया। रियलिटी सेक्टर या उद्योग लोगों को रोजगार का भारी स्रोत प्रदान करता है, साथ ही साथ बुनियादी ढाँचे की विकास की जरूरतें भी पूरी होती हैं।

9.6 श्रम बल की प्रकृति

वे व्यक्ति जो या तो कार्यरत हैं या रोजगार मांग रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं लेकिन उस विसेश अवधि के दौरान बेरोजगार, एक साथ श्रम बल का गठन करते हैं। श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) को प्रति 1000 व्यक्तियों पर श्रम बल में व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल मिलाकर, 1991 में श्रम बल 337 मिलियन से बढ़कर 2013 में लगभग 488 मिलियन हो गया। लगभग 22 वर्षों में श्रम बल में 151 मिलियन का विस्तार है। रोजगार का स्तर कमोबेश इसी प्रवृत्ति का पालन करता है जैसा कि श्रम बल द्वारा दिखाया गया है, लेकिन पूरे स्तर में रोजगार स्तर श्रम शक्ति से कम हो गया, जिससे दोनों के बीच एक सुसंगत अंतर पैदा हो गया। दूसरे शब्दों में, अधिक संख्या में लोगों ने अपने पास उपलब्ध रोजगार के रास्ते की तुलना में श्रम बल में प्रवेश किया। 1991 में 337 मिलियन की तुलना में 2013 में भारत में रोजगार 488 मिलियन तक बढ़ गया।

भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जाता है लेकिन देश में रोजगार की स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है। कुल मिलाकर, जनसंख्या अनुपात में श्रम-शक्ति (15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में) भारत में 56 प्रतिशत कम है जबकि शेष विश्व के लिए यह लगभग 64 प्रतिशत है। भारत में भागीदारी काफी हद तक कम है क्योंकि महिला श्रम शक्ति की भागीदारी दर लगभग 31 प्रतिशत है जो दुनिया में सबसे कम है और दक्षिण एशिया में दूसरी सबसे कम है।

आज भी कृषि में लगे श्रमिकों का बड़ा अनुपात (लगभग 49 प्रतिशत) सकल घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत का योगदान देता है। इसके विपरीत, सेवा क्षेत्र जो सकल घरेलू उत्पाद का 58 प्रतिशत योगदान देता है, मुश्किल से 27 प्रतिशत रोजगार पैदा करता है, और रोजगार

में विनिर्माण का हिस्सा (13 प्रतिशत) और सकल घरेलू उत्पाद (16 प्रतिशत) दोनों पूर्व एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तुलना में बहुत कम है । इसका कारण भारत में औद्योगिकीकरण के निम्न स्तर और रोजगारहीन विकास के स्तर में निहित है। इसलिए बहुत कम लोग औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पाने में सक्षम हैं। विकास का यह असंतुलित स्वरूप तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का अनुभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, श्रमिक बड़े पैमाने पर (लगभग 92 प्रतिशत) रोजगार के अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और उनमें से अधिकांश के पास सीमित सामाजिक सुरक्षा के साथ कम आय है। यह संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के पर्याप्त अनुपात के लिए भी सही है। आधे से अधिक कर्मचारी स्व-नियोजित हैं, मोटे तौर पर एक गरीब संपत्ति-आधार के साथ। रोजमर्रा के आधार पर रोजगार पाने के इच्छुक लगभग 30 प्रतिशत मजदूर हैं। नियोजित लोगों में से लगभग 18 प्रतिशत नियमित कर्मचारी हैं, और उनमें से 8 प्रतिशत से भी कम लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा के साथ पूर्णकालिक रोजगार हैं।

गतिविधि 1

अपने पड़ोस में एक स्थानीय कारखाना या कुटीर उद्योग पर जाएँ। वहां काम करने वाले कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों से बात करें और विभिन्न कामकाज या संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस कारखाने के निर्माण इकाई के रोजगार और संगठनों पर एक पृष्ठ की एक रिपोर्ट लिखें और अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ तुलना करें।

भारत में अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक नौकरियों में हैं जैसे कि, सब्जी विक्रेता, चाय स्टाल मालिक आदि। लेकिन कृषि आधारित उद्योग से बदलाव हुआ है , निर्माण ने हाल के वर्षों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक श्रमिकों को शामिल किया है। इनमें से अधिकांश अकुशल मजदूर हैं। जो अधिक गंभीर है, वह यह है कि औपचारिक क्षेत्र में सृजित होने वाली अधिकांश नई नौकरियां वास्तव में अनौपचारिक हैं, क्योंकि श्रमिकों को रोजगार लाभ या सामाजिक सुरक्षा जैसे कि पेंशन या चिकित्सा आदि तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा, उल्लेखनीय असमानताएं यानी पुरुषों और महिलाओं की श्रम बल की भागीदारी दर में अंतर लगातार बना हुआ है।

9.6.1 औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार

रोजगार संबंधों को समझने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। औपचारिक क्षेत्र में श्रमिक कारखानों और वाणिज्यिक और सेवा प्रतिष्ठानों में लगे हुए हैं और कानूनी विनियमन के दायरे में हैं। इस क्षेत्र के लगभग 70 प्रतिशत श्रमिक सरकारी, अर्ध-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र केवल 29 प्रतिशत श्रम को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में लगे लोगों की तुलना में काफी अधिक हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि एक औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक का औसत वेतन अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूरी से 4 या 5 गुना अधिक है। इसके अलावा, श्रम कानूनों की एक श्रृंखला, नौकरियों, स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) 'अनौपचारिक क्षेत्र को परिभाषित करता है जोकि रोजगार पैदा करने और संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिक आय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगी इकाइयाँ शामिल हैं। इकाइयां उत्पादन के कारकों के रूप में श्रम और पूंजी के बीच कम या कोई विभाजन नहीं होने के साथ छोटे स्तर पर इकाइयों का संचालन

करती हैं। ऐसे क्षेत्र में, श्रम संबंध ज्यादातर औपचारिक गारंटी के साथ अनुबंध की व्यवस्था के बजाय रोजगार, रिश्तेदारी या व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की आकस्मिक शर्तों पर आधारित होते हैं। भारत में, असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग (NCEUS) ने संगठित या औपचारिक और असंगठित या अनौपचारिक रोजगार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किया। असंगठित श्रमिकों में असंगठित उद्यमों या घरों में काम करने वाले उद्योग आधारित हैं। उन्हें नियोक्ताओं से सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलता है। वे उदाहरण के लिए नियमित श्रमिक नहीं हैं, चाय-स्टाल के मालिक, 'पान' विक्रेता, गुब्बारे और खिलौने निर्माता आदि।

औपचारिक क्षेत्र में भी ऐसे श्रमिक हैं जो बिना किसी नियमित रोजगार और सामाजिक सुरक्षा लाभ के हैं। ऐसे श्रमिक विनिर्माण, निर्माण और व्यापार (थोक और खुदरा) में अनौपचारिक रोजगार का प्रमुख हिस्सा है। उनके पास लगभग 76 प्रतिशत श्रमिक हैं। अर्थव्यवस्था में लगभग 84.7 प्रतिशत नौकरियां अनौपचारिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में 4. 5 प्रतिशत, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में 2.5 प्रतिशत और 'औपचारिक' घरेलू क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत हैं। 90 प्रतिशत से अधिक महिला कार्यकर्ता अनौपचारिक क्षेत्र में केंद्रित हैं। महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र में लचीलेपन के कारण घरेलू नौकरों, रसोइयों आदि जैसे घरेलू कार्यों में अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है, यह उनके लिए उनकी अन्य जरूरतों और मांगों को देखते हुए लाभकारी होता है। अवैतनिक श्रम। अनौपचारिक क्षेत्र में काम कम पारिश्रमिक है और परिस्थितियाँ संगठित क्षेत्र से निम्न हैं। उनके पास आर्थिक सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा का अभाव है। इसलिए श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण उन श्रमिकों की बहुत अधिक भेदभाव है जो श्रम कानून या ट्रेड यूनियन संगठन की पहुंच से बाहर हैं। विशेष रूप से महिला कार्यकर्ता अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक कमजोर स्थिति में हैं।

9.6.2 भारत में व्यापार संघों की उत्पत्ति

व्यापार संघ बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण, उद्योगों और औद्योगिक समस्याओं की उपज हैं। आधुनिक औद्योगिकीकरण के आगमन के बाद नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच व्यक्तिगत अनुबंध थे (जैसा कि उद्योगों को घरों में और नियोक्ता के औजारों से चलाया जाता था) , इसके अलावा प्राचीन भारत में, साथ ही मध्ययुगीन काल में, गिल्ड्स की प्रणाली थी जो पारंपरिक मानदंडों के अनुसार कला, मूर्तियां, गहने, हस्तशिल्प की संख्या का उत्पादन करती थी। ये गिल्ड बहुत प्रसिद्ध थे (विशेषकर भारत के दक्षिण में)। आधुनिक उद्योगों के रूप में उनके संबंधों को निर्धारित करने के लिए किसी भी मशीनरी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आधुनिक फैक्टरी प्रणाली के तहत कस्बों और शहरों में भारी मशीनरी और बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण व्यक्तिगत संपर्क खो गया, ।

उत्पादन की लागत को कम करने, प्रतिस्पर्धी बाजार की मांग को पूरा करने और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए नियोक्ता या उद्योगपति उत्पादन और परिष्कृत मशीनों से अधिक से अधिक तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया नियोक्ता, कर्मचारी संबंध को नियंत्रित करने के लिए और अधिक योगदान देती है। इसके साथ ही, इस तरह की प्रगति ने उदासीन श्रमिकों के एक नए वर्ग को जन्म दिया है, यानी जिन श्रमिकों को कार्ल मार्क्स अलग-थलग कहते हैं, उन्हें वस्तु (कमोडिटी) बनाने में कोई व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है क्योंकि वे केवल एक कील या कुल वस्तु का हिस्सा डाल रहे हैं जैसे कि , एक कार या वाशिंग मशीन आदि) जो अपनी आजीविका के लिए अपनी मजदूरी पर निर्भर हैं।

श्रमिकों का व्यापार संघ उनकी रुचि, आजीविका की स्थितियों की रक्षा के लिए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है और जो उन्हें एकीकृत करने के लिए औपचारिक रूप से स्थितियां बनाता है।

मजदूर संघ (ट्रेड यूनियन्स) श्रमिकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच एक कड़ी बनाती हैं। वे श्रमिकों को अपनी बात सामने रखने के लिए संस्थागत आधार प्रदान करते हैं। वे अपने हितों की रक्षा के लिए विरोध के संगठित तरिके का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अनुशासित तरीके से मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को नियोजित करते हैं। ये संगठित व्यापारों में श्रमिकों की आवश्यक समझौतों और सौदेबाजी की संस्था हैं। यह नियोक्ता के हित में भी है कि संघ की सदस्यता यथासंभव व्यापक होनी चाहिए। वे देश की आर्थिक उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं।

भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद पैदा हुआ था, जब औद्योगिक हड़ताल का प्रकोप था। पहला संघ 1918 में मद्रास में शुरू किया गया था। इसे मद्रास कपड़ा संघ के नाम से जाना जाता था। इसने श्रमिकों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने में उत्कृष्ट कार्य किया, लेकिन 1921 में नियोक्ताओं के पक्ष में कानून बनाया गया, जिसने मद्रास उच्च न्यायालय से संघ की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक आदेश प्राप्त किया, इस आयोजन ने जनता का ध्यान व्यापार संघ की ओर आकर्षित किया यह वह कानून था जो तब तक देश में मौजूद नहीं था। इस समय में ही (1920) ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एक केंद्रीय संगठन के रूप में हुई थी। श्रमिकों के संघ को ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) से प्रेरणा मिली।

1926 के भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम ने पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को एक कानूनी और कॉर्पोरेट दर्जा दिया और उन्हें व्यापार विवादों के संबंध में कुछ प्रतिरक्षा प्रदान की गयी । अधिनियम पंजीकरण को नियंत्रित करने वाली शर्तों और निर्दिष्ट यूनियनों के अधिकार और विशेषाधिकार को निर्दिष्ट करने का प्रावधान करता है। अधिनियम ने पंजीकृत यूनियनों के धन को व्यापार विवादों के संचालन के लिए और अपने सदस्यों को लाभ के प्रावधान के लिए खर्च करने की अनुमति दी है।

स्वतंत्रता के बाद, देश बढ़ती बेरोजगारी में डूब गया था। उच्च मजदूरी हासिल करने के लिए श्रमिकों को सेवाएं प्रदान करने की उच्च उम्मीदें, राष्ट्रीय सरकार से बेहतर स्थिति और सुविधाएं बिखर गईं। मजदूरों ने पहले जो हासिल किया था, उसे बनाए रखने के लिए भी कठिन संघर्ष करना जरूरी पाया। हमलों की एक श्रृंखला देश में आ गई और इस अवधि के दौरान खोए गए कार्य दिवस जो देस में दर्ज किए थे गए उच्चतम थे। इस अवधि के दौरान चार केंद्रीय संगठनों (नीचे दी गई सूची) की शुरुआत से ट्रेड यूनियन स्तरों में असंगति बढ़ गई थी। स्थानीय स्तर की ट्रेड यूनियन, फर्म-लेवल या इंडस्ट्री-लेवल ट्रेड यूनियन, बड़े संगठनों या यूनियन फेडरेशन से संबद्ध थे। देश में बड़े संघ राष्ट्रीय स्तर पर श्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें केंद्रीय व्यापार संघ संगठनों के रूप में जाना जाता है। अपनी स्थिति प्राप्त करने के लिए, एक ट्रेड यूनियन फेडरेशन के पास कम से कम 500,000 श्रमिकों की सत्यापित सदस्यता होनी चाहिए, जो न्यूनतम चार राज्यों और चार उद्योगों (कृषि सहित) में फैले हुए हैं। केंद्रीय व्यापार संघ संगठनों की सूची निम्न है:

1) ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस
2) ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर
3) भारतीय मजदूर संघ

4) भारतीय व्यापार संघों का केंद्र

5) भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

6) लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन

7) भारतीय व्यापार संघ का राष्ट्रीय मोर्चा

8) स्वरोजगार महिला संघ

9) ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र

10) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस

गतिविधि 2

भारत के कुछ प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेताओं पर एक पुस्तक पढ़ें और भारत में श्रम बलों के कल्याण में उनके योगदान पर दो पृष्ठों का एक निबंध लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ अपने निबंध की तुलना करें।

9.6.3 श्रम कल्याण और कानून

श्रम विधान का उद्देश्य दो गुना है (i) औद्योगिक श्रम की सेवा शर्तों में सुधार करके उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके और (ii) औद्योगिक शांति लाने के लिए जो देश की उत्पादक गतिविधि को गति प्रदान कर सके जो इसकी समृद्धि में वृद्धि कर सके।

भारत के संविधान के तहत, श्रम समवर्ती सूची में एक विषय है जहां केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को विधान बनाने का अधिकार है। इसके परिणामस्वरूप कई श्रम कानून बन गए हैं, जो श्रम के विभिन्न पहलुओं अर्थात् व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण, निर्धारण, समीक्षा और न्यूनतम मजदूरी के संशोधन, मजदूरी के भुगतान के तरीके, मुआवजे के भुगतान के लिए लागू किए गए हैं। ऐसे श्रमिक जिनकी चोटें या मृत्यु हुई थी या विकलांगता, बंधुआ मजदूरी, अनुबंध श्रम, महिला श्रम और बाल श्रम, औद्योगिक विवादों का समाधान और स्थगन, भविष्य निधि जैसे सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेच्युटी, भुगतान का प्रावधान श्रमिकों के लिए काम की परिस्थितियों को बोनस और विनियमित करना ये श्रम कानून भारत के संविधान के प्रावधानों से उनके मूल, अधिकार और शक्ति को प्राप्त करते हैं। मानव श्रम की गरिमा की प्रासंगिकता और मानव के श्रम की रक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में मानव को अध्याय-III (अनुच्छेद 16, 19, 23 और 24) और अध्याय IV (अनुच्छेद 39, 41, 42, 42) में निहित किया गया है। भारत के संविधान के 43 , 43। और 54) मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है। श्रम कानून सुधार एक सतत प्रक्रिया है और सरकार लगातार गतिशील आर्थिक माहौल में श्रमिकों की उभरती जरूरतों के जवाब में नए कानूनों को पेश कर रही है और मौजूदा कानून को संशोधित कर रही है।

श्रम कल्याण एक व्यापक अवधारणा है जो कारखाने के परिसर के भीतर और बाहर एक व्यक्ति या एक समूह के रहने वाले व्यक्ति की स्थिति का कुल पर्यावरण-पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक सद्भाव के साथ स्वीकार्य बातचीत में उल्लेख करती है। कर्मचारियों के कल्याण, श्रम कल्याण और कर्मचारी कल्याण जैसी शर्तें आम तौर पर कर्मचारियों को उनके वेतन के अलावा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और लाभों को संबोधित करने के लिए एक दूसरे के विकल्प के रूप में उपयोग की जाती हैं। श्रम कल्याण का पहलू कल्याण के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं का गठन करता है। यह कल्याण और

उत्पादकता के लिए औद्योगिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग का कहना है कि "श्रम कल्याण का मॉडल अनिवार्य रूप से गतिशील है। इसकी व्याख्या एक देश से दूसरे देश में आर्थिक विकास और श्रमिक वर्ग के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और विकास के संबंध में बदलती है। यह कहा जा सकता है कि श्रम कल्याण सरकारी प्राधिकरणों, नियोक्ताओं, स्वैच्छिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों की उन सभी गतिविधियों को दर्शाता है जो श्रम वर्ग को बेहतर सामाजिक परिस्थितियों में अच्छी तरह से जीने और अधिक उत्पादक होने में मदद करते हैं। इसमें श्रम की सामाजिक स्थिति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और औद्योगिक उत्पादकता में सुधार के प्रावधान हैं। आम तौर पर श्रम कल्याण कार्यों को नीचे दिए गए पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

1) केंद्र सरकार द्वारा लागू विभिन्न कानूनी विधानों द्वारा वैधानिक प्रावधान,

2) राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा दिए गए कल्याणकारी उपाय,

3) नियोक्ताओं द्वारा दिए गए कल्याणकारी उपाय,

4) ट्रेड यूनियनों द्वारा मजबूर कल्याणकारी उपाय, और

5) स्वैच्छिक सामाजिक एजेंसियों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्य किए गए।

केंद्र और राज्य सरकारों ने भी कानून बनाए हैं और सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों की विशिष्ट श्रेणियों के कल्याण के लिए स्थापित योजनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून निम्नलिखित हैं:

i) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923,

ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948,

iii) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1953 और

iv) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961,

v) ग्रेच्युटी अधिनियम का भुगतान, 1972।

श्रम कानून सुधारों के हिस्से के रूप में, सरकार ने मजदूरी पर चार श्रम संहिताओं के प्रारूपण के लिए कदम उठाए हैं, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, और मौजूदा 44 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को सरल, समाहित और तर्कसंगत बनाने के द्वारा क्रमशः सुरक्षा और कार्य की स्थिति।

बॉक्स 9.0

दत्ता सामंत : एक ट्रेड यूनियन लीडर और उनका राजनीतिक कैरियर

दत्ता सामंत महाराष्ट्र के कोंकण तट पर देवबाग में पले-बढ़े, मध्यवर्गीय मराठी पृष्ठभूमि से थे। वह एक योग्य M.B.B.S. जी.एस. सेठ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे और के. ई.एम. अस्पताल, मुंबई और घाटकोपर के पंतनगर इलाके में उन्होंने एक सामान्य चिकित्सक के रूप में कार्य किया। उनके रोगियों के संघर्ष ने, जिनमें से अधिकांश बंबई के कपड़ा मिलों में उद्योग के मजदूर थे, उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के एक इलाके घाटकोपर में, काफी समय बिताया। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत से, शहर की अर्थव्यवस्था का कारण प्रमुख कपड़ा मिलों की उपस्थिति थी, जो भारत के संपन्न कपड़ा और वस्त्र उद्योग का आधार था। पूरे भारत के सैकड़ों लोगों को मिलों में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि वे एक प्रशिक्षित मेडिकल डॉक्टर थे,

सामंत मिल श्रमिकों के बीच ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भी सक्रिय थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में शामिल हो गए। शहर के कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता प्राप्त करते हुए, सामंत का नाम डॉक्टर्साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

1960 और 1970 के दशक में, मुंबई-ठाणे औद्योगिक बेल्ट ने मजदूरों की निष्ठा और राजनीतिक नियंत्रण के लिए कई ट्रेड यूनियनों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए लगातार मजदूर वर्ग के हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों को देखा। इनमें मुख्य रूप से भारतीय व्यापार संघ का केंद्र में जॉर्ज फर्नांडीस शामिल थे। सामंत सबसे प्रमुख INTUC के नेताओं में से एक बन गये , और अपने राजनीतिक विश्वासों और सक्रियता के कारण तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने हड़तालों के आयोजन और कंपनियों से पर्याप्त मजदूरी हासिल करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कंपनी के आँकड़ों और व्यवसाय की जानकारी को नजरअंदाज कर दिया, और लगातार रियायतों पर समझौता करने से इनकार कर दिया। 1972 के चुनावों में, वह महाराष्ट्र विधानसभा, या कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के लिए चुने गए, और एक विधायक के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी से संबंधित होने के बावजूद उन्हें 1975 में भारतीय आपातकाल के कारण एक उग्रवादी संघवादी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। 1977 में उनकी रिहाई और जनता पार्टी गठबंधन की विफलता के साथ सामंत की लोकप्रियता बढ़ गई, जिसके साथ कई प्रतिद्वंद्वी यूनियनों को संबद्ध किया गया। इसने राजनीति में श्रमिकों और उनके हितों को रखने के लिए उनकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को बढ़ाया।

1981 के उत्तरार्ध में, सामंत को मुंबई मिल श्रमिकों के एक बड़े समूह द्वारा बॉम्बे मिलवॉअर्स एसोसिएशन और यूनियनों के बीच एक अनिश्चित संघर्ष में नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, इस प्रकार INTUC (आई.एन.टी.यू.सी.) से संबद्ध राष्ट्रीय मजदूर मजदूर संघ को अस्वीकार कर दिया जिसने दशकों से मिल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया था। सामंत को नेतृत्व करने के लिए मिल श्रमिकों द्वारा अनुरोध किया गया । उन्होंने सुझाव दिया कि वे प्रारंभिक हड़ताल से पहले कार्रवाई के परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे । लेकिन कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्तेजित थे और एक बड़े पैमाने पर हड़ताल चाहते थे। जिसकी शुरुआत में अनुमानित 200,000-300,000 मिल मजदूर बाहर चले गए, जिससे शहर का पूरा उद्योग एक साल के लिए बंद हो गया। सामंत ने मांग की कि वेतन वृद्धि के साथ, सरकार को बॉम्बे औद्योगिक अधिनियम, 1947 को रद्द करना चाहिए और RMMS को शहर उद्योग के एकमात्र आधिकारिक संघ के रूप में मान्यता देनी चाहिए। श्रमिकों के लिए अधिक वेतन और बेहतर परिस्थितियों के लिए संघर्ष करते हुए, सामंत और उनके सहयोगियों ने मुंबई में ट्रेड यूनियन की घटना द्वारा अपनी शक्ति को भुनाने और स्थापित करने की कोशिश की।

बाद का जीवन और हत्या

सामंत को 1984 में भारतीय संसद के निचले सदन, 8वीं लोकसभा के लिए एक स्वतंत्र, कांग्रेस-विरोधी टिकट पर चुना गया था, एक चुनाव जो अन्यथा राजीव गांधी के तहत कांग्रेस द्वारा एकतरफा था। उन्होंने कामगार अघादी संघ, और लाल निशान पार्टी को संगठित किया, जिसने उन्हें साम्यवाद और भारतीय कम्युनिस्ट राजनीतिक दलों के करीब लाया। वे 1990 के दशक में पूरे भारत में ट्रेड यूनियनों और कम्युनिस्ट राजनीति में सक्रिय रहे। अपनी मृत्यु के समय वह संसद के सदस्य नहीं थे। 16 जनवरी 1997 को मुंबई में सामंत की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। (www-wikipedia-com, दिनांक 31-12-2018)

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) लगभग 10 लाइनों का उपयोग करके भारत में श्रम बल की प्रकृति का संक्षेप में वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत में ट्रेड यूनियन का उदय कैसे हुआ? चर्चा कर।

.....

.....

.....

.....

.....

3) संगठित क्षेत्र में काम करने वाली श्रम बल की रक्षा के लिए कम से कम दो विधानों का उल्लेख करें।

.....

.....

.....

.....

.....

9.7 सारांश

वर्तमान इकाई उद्योग की अवधारणा और इसके प्रकारों के बारे में बताती है। यह भारत में उद्योगों के विकास और औपनिवेशिक काल से भारत में आधुनिक उद्योगों के उदय का पता लगाती है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में 1991 में उदारीकरण की अवधि तक हुए परिवर्तनों पर भी चर्चा की गई है।

श्रम बल की प्रकृति, औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार, अर्थात, अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, व्यापार संघ और श्रम कल्याण उपायों और विधानों को भी तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जांचा गया है। विभिन्न कानूनी उपाय और औद्योगिक श्रमिकों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं ।

9.8 संदर्भ

बर्मन, जे. (1996), फुटलूस लेबर : वर्किंग इन इंडियास इनफॉर्मल लेबर, नई दिल्ली, इंडिया : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

दावला, एस. सी, (सं।), (1995, अनप्रोटेक्टेड लेबर इन इंडिया ,नई दिल्ली, इंडियाः फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग।

दत्त, आर. (सं.)। (1997), आर्गनाइज्ड अनऑर्गेनिज्ड लेबर । नई दिल्ली : इंडिया विकास।

गाडगिल, डी. आर. (1982), इंडस्ट्रियल एवोलुशन ऑफ इंडिया ,नई दिल्ली, रूइंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

होल्मस्ट्रोम, एम. (1986), इंडस्ट्री एंड इनक्वालिटी : द सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडियन लेबर , कैम्ब्रिज, यूकेः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

झाबवाला, आर.(2003), ब्रिंगिंग इनफॉर्मल सेक्टर सेंटर स्टेज आर। झबवाला, आर. एम. सुदर्शन और जे. उन्नी (सं.) में, इनफॉर्मल इकोनमी सेंटर स्टेज (पृष्ठ 258-275), नई दिल्ली, भारतरू ऋषि।

लैम्बर्ट, आर. डी. (1963), वर्कर्स, फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज इन इंडिया , प्रिंसटन, एनजेरू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

मेयर, सी. ए. (1958)लबर प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्रीलिजेषन ऑफ इंडिया ,कैम्ब्रिज, यूकेरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

मॉरिस, एम. डी. (1965), दॉ एमेर्जेंस ऑफ लेबर फोर्स इन इंडिया : ए स्टडी ऑफ बॉम्बे कॉटन मिल्स, 1854-1947, बर्कले : कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस।

मुखर्जी, आर.के. (1945), द इंडियन वर्किंग क्लास। बॉम्बे, भारतरू हिंद किताब।

रामास्वामी, ई. ए, और रामास्वामी, यू. (1981), इंडस्ट्री एंड एण्ड लेबर , नई दिल्ली : इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

रेवड़ी, सी. (1958)। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन मूमेंट इन इंडिया, नई दिल्लीः इंडियाओरिएंट लॉन्गमैन।

शर्मा, बी. आर. (1971), इंडियन इंडस्ट्रियल वर्कर रू इष्यूज इन पर्सपेक्टिव , इंडिया, रू विकास।

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

उद्योग को अच्छी तरह से संगठित कारखानों में माल के सामूहिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें उच्च स्तर की स्वचालन और विशेषज्ञता है। यह एक उद्योग को समझने का एक पहलू है। हालांकि, उद्योग के एक अन्य पहलू में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है, जैसे कि, कृषि, सौंदर्य उद्योग, फिल्म उद्योग, आदि। एक उद्योग तब अस्तित्व में आता है जब नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध होता है। नियोक्ता व्यवसाय, व्यापार, विनिर्माण में एक व्यवसाय के रूप में लगे होते हैं लेकिन कर्मचारी उत्पादन की प्रक्रिया में अपनी श्रम शक्ति प्रदान करने में लगे होते हैं।

पाँच विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जैसे -

1) प्राथमिक

2) माध्यमिक

३) तृतीयक सेवा

4) चतुर्थ तथा

5) पंचम (क्विनरी)

बोध प्रश्न 2

i) श्रम शान्ति ऐसे व्यक्तियों का गठन करता है, जो या तो काम कर रहे हैं और/या कार्यरत हैं या रोजगार की मांग रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उस अवधि के दौरान बेरोजगार हैं जब उन्हें संदर्भित किया जाता है या उनकी गिनती की जाती है। श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) को प्रति 1000 व्यक्तियों पर श्रम बल में व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, हम अलग-अलग समय में श्रम बल में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को देखते हैं। श्रम बल की समग्र वृद्धि भारत में देखी जा सकती है। यह 1991 में लगभग 337 मिलियन से बढ़कर 2013 में लगभग 488 मिलियन हो गया। उद्योग में भारत की रोजगार दर तुलनात्मक रूप से 56 प्रतिशत कम है जो कि भारत में श्रम शक्ति महिलाओं के कारण कम है।

ii) व्यापार संघ बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण, उद्योगों की एकाग्रता और औद्योगिक समस्याओं की उपस्थिति के संदर्भ में उभरा। इससे पहले घर आधारित उद्योग या यहां तक कि पारंपरिक गिल्ड सिस्टम जो भारत में मौजूद थे,उनमें नियोक्ता कर्मचारी के आमने -सामने के संबंध थे । लेकिन जब आधुनिक फैक्ट्री सिस्टम उभरा तो व्यक्तिगत अंतः क्रिया ने काम हो गयी । आज नियोक्ताओं की रुचि लक्ष्य उत्पादन प्राप्त करने में निहित है जबकि श्रमिकों के हितों को अनसुना या दबा दिया जाता है। इस प्रकार, श्रमिकों का व्यापार संघ, कस्बों और शहरों में अपने हितों, आजीविका की स्थिति की रक्षा करने के लिए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्पन्न हुआ।

iii) केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून हैं।

1) नियोक्ता मुआवजा अधिनियम, 1923।

2) नियोक्ता भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1953।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY